₹ 49/-

TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

Monthly CURRENT AFFAIRS

By - Toppers Club

Mar-2026

Contact Us

+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
www.topperclubiasacademy.in

Er Dev Pratap Singh
Director

IAS | IPS | PCS | IFS | IRS & OTHER COMPETITIVE EXAMS

विश्व समाचार

- एपस्टीन फाइल्स खुलासा: लीक दस्तावेजों ने वैश्विक राजनीतिक तूफान मचाया
- नई नेतृत्व त्रयी: Bangladesh, Barbados, Japan में नई युगारंभ
- भारत की कूटनीतिक सफलता: अमेरिका, यूरोपीय संघ, एशिया के साथ मेगा करार
- ट्रंप का व्यापार युद्ध 2.0: सहयोगी राष्ट्रों में हड़कंप
- दो-राज्य समाधान का पुनरागमन: इजरायल-फलस्तीन विवाद समाप्ति का मार्ग

राष्ट्रीय प्रमुख समाचार

वंदे मातरम का पुनरुद्धार: राष्ट्रगान के लिए केंद्र की व्यापक दिशानिर्देश

यूजीसी कोटा नियम पर Supreme Court of India की रोक: कॉलेजों को राहत, भविष्य क्या ?

निधन: Ajit Pawar, Sarla Maheshwari, I. S. Bindra का निधन

बजट 2026

भारत का विकास मानचित्र

टैक्स राहत, इंफ्रा बूस्ट, किसान हित

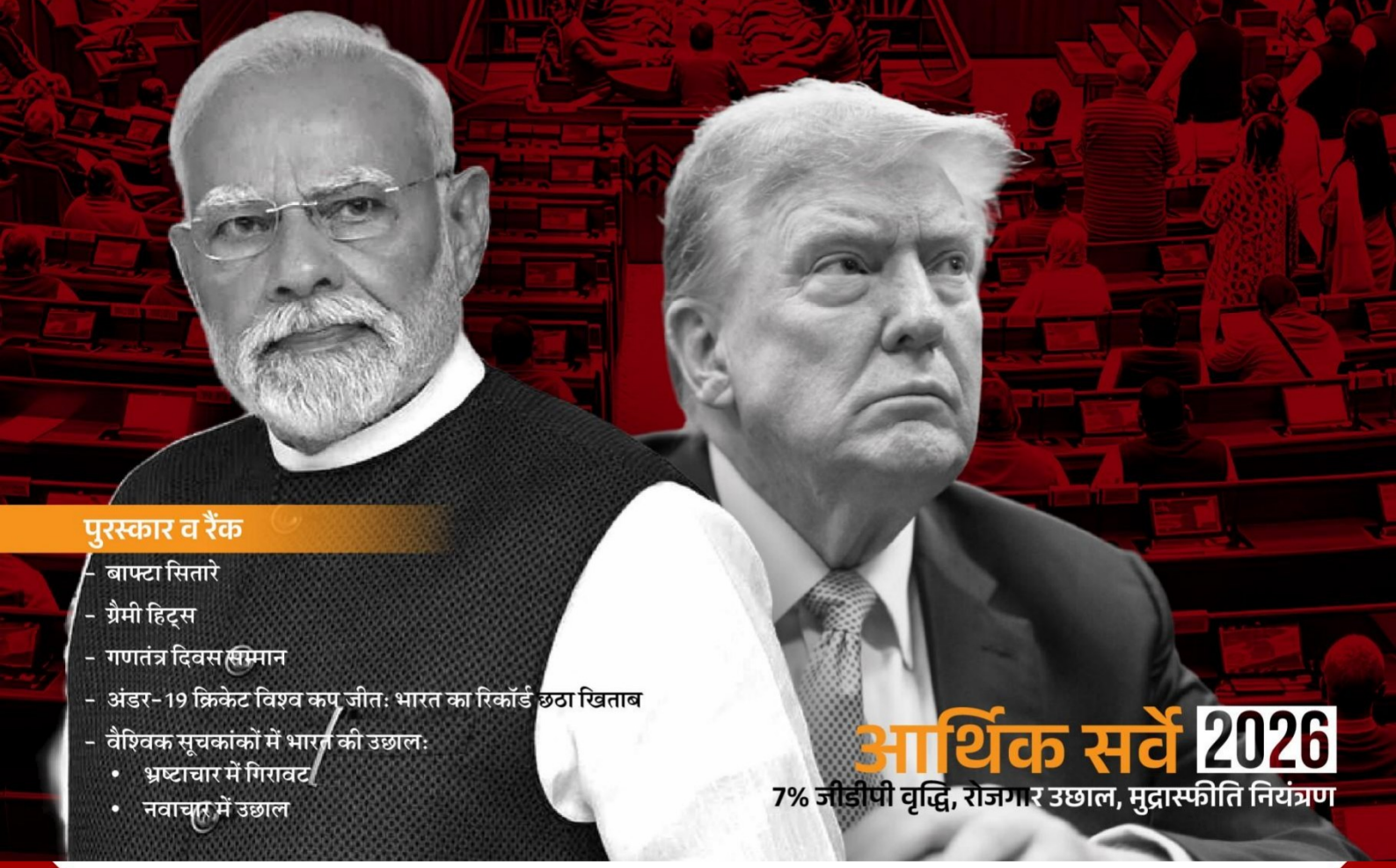

पुरस्कार व रैंक

- बाफ्टा सितारे
- ग्रैमी हिट्स
- गणतंत्र दिवस सम्मान
- अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीत: भारत का रिकॉर्ड छठा खिताब
- वैश्विक सूचकांकों में भारत की उछाल:
  - भ्रष्टाचार में गिरावट
  - नवाचार में उछाल

आर्थिक सर्वे 2026

7% जीडीपी वृद्धि, रोजगार उछाल, मुद्रास्फीति नियंत्रण

Toppers Club IAS Academy
All Copyright Reserved

Contact Info:
Phone No: +91 6388671098
Mail: dpsctc@gmail.com
Website: www.topperclubiasacademy.in

अस्वीकरण

यह पुस्तक विशेष रूप से शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। लेखक(ों) द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है कि किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन न हो। यदि किसी स्रोत का अनजाने में उल्लेख नहीं किया गया है या किसी प्रकार का अनचाहा उल्लंघन हुआ है, तो कृपया प्रकाशक को लिखित रूप में सूचित करें ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जा सके।

हालाँकि सामग्री की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की गई है, फिर भी अनजाने में कुछ त्रुटियाँ या चूक हो सकती हैं। किसी भी पाई गई विसंगति को आगामी संस्करणों में ठीक किया जाएगा। लेखक(ों), प्रकाशक और वितरक इस पुस्तक में दी गई जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कानूनी, तथ्यात्मक या महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से परामर्श करें।

बाइंडिंग में दोष, प्रिंटिंग में त्रुटि या पृष्ठों की कमी जैसी समस्याओं के मामलों में प्रकाशक की ज़िम्मेदारी केवल उसी या समकक्ष संस्करण की दोषपूर्ण प्रति के प्रतिस्थापन तक ही सीमित है। प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध खरीद की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इससे संबंधित सभी लागतें, जैसे कि शिपिंग, क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी।

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन के किसी भी भाग को बिना प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी रूप में—चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोग्राफिक या अन्य कोई माध्यम हो—प्रतिलिपि, संग्रह या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के उपयोग, पुनरुत्पादन या वितरण के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

लेखक इस कृति की मूल सामग्री पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सिवाय उन उद्धरणों के जहाँ उपयुक्त अनुमति के साथ स्रोत का उल्लेख किया गया है। यह प्रकाशन किसी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है, और इसमें कोई मानहानिकारक सामग्री सम्मिलित नहीं है।

प्रिय अभ्यर्थियों,

आज का अध्ययन अनुशासन ही कल की सेवा की जिम्मेदारी बनता है।

सिविल सेवाओं की तैयारी केवल एक परीक्षा की तैयारी नहीं है, बल्कि राष्ट्र और विश्व की धड़कन को समझने का एक गंभीर संकल्प है। इस परीक्षा में जहाँ स्थैतिक ज्ञान आधार प्रदान करता है, वहीं समसामयिक घटनाओं की गहरी और निरंतर समझ अंतिम चयन में निर्णायक भूमिका निभाती है। नियमित रूप से वर्तमान घटनाओं का अध्ययन न केवल तथ्यात्मक ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि दृष्टिकोण को परिपक्व बनाता है, विश्लेषण क्षमता को सुदृढ़ करता है और प्रशासनिक संवेदनशीलता विकसित करता है—जो एक भावी सिविल सेवक के लिए अनिवार्य गुण हैं।

जैसा कहा गया है, "उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है।"
दैनिक और गंभीर अध्ययन वही आदत है, जो आपकी तैयारी को उद्देश्यपूर्ण बनाती है और लक्ष्य को उपलब्धि में परिवर्तित करती है।

इस अंक में हमने उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समाहित किया है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्श की दिशा तय कर रही हैं। "टू-स्टेट सॉल्यूशन रिवाइवल: इज़राइल-फिलिस्तीन गतिरोध के समाधान की नई राह" अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक कूटनीति की जटिलताओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। "नए नेतृत्व का उदय: बांग्लादेश, बारबाडोस और जापान में नए युग की शुरुआत" दर्शाता है कि राजनीतिक परिवर्तन क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

घरेलू परिप्रेक्ष्य में "वंदे मातरम् पुनर्जीवित: सरकार ने राष्ट्रीय गीत प्रोटोकॉल देशभर में लागू किए" संवैधानिक मूल्यों, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक निर्णयों के बीच संतुलन पर विचार करने का अवसर देता है। वहीं "सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी नियमों पर रोक लगाई: कॉलेजों को राहत, आगे क्या?" न्यायपालिका और नीति निर्माण के संबंध को समझने में सहायक है।

आर्थिक और वैश्विक परिदृश्य में "अमेरिकी व्यापार समझौता सुरक्षा प्रावधान: भारत ने किसानों को आयात दबाव से बचाया" रणनीतिक आर्थिक कूटनीति को रेखांकित करता है। "SCOTUS ने ट्रंप टैरिफ पर रोक लगाई: क्या वैश्विक व्यापार युद्ध टला?" और "ट्रंप का ट्रेड वॉर 2.0: अमेरिकी टकराव से वैश्विक सहयोगी चिंतित" अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीतिक तनावों की गहराई को उजागर करते हैं। वहीं "एपस्टीन फाइल्स खुलासा: लीक दस्तावेजों से वैश्विक राजनीतिक हलचल" कानून, जवाबदेही और मीडिया की भूमिका पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत करता है।

यह पत्रिका केवल समाचारों का संकलन नहीं है, बल्कि विश्लेषण की दृष्टि विकसित करने का माध्यम है। एक भावी सिविल सेवक के लिए घटनाओं को समझना, उनके कारणों और परिणामों का मूल्यांकन करना तथा संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना अत्यंत आवश्यक है।

आप केवल एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी नहीं कर रहे—आप शासन, नीति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में अग्रसर हैं।
नियमित रहें। निष्पक्ष सोच रखें। लक्ष्य के प्रति अडिग रहें।

मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु निरंतर प्रयास और स्पष्ट दृष्टि आपको सेवा, नेतृत्व और प्रभाव के शिखर तक अवश्य पहुँचाएगी।

गहराई से पढ़ो। स्पष्ट सोचो। गर्व से सेवा करो।

इस संस्करण में शामिल हैं

राजतंत्र एवं शासन 5
- पूजा स्थल अधिनियम: कानूनी लड़ाई, एक नज़र
- सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दी
- पीएमओ सेवा तीर्थ में शिफ्ट
- राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर व्यापक दिशा-निर्देश
- औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
- प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिए कई निजी सदस्यों के विधेयक
- क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (लचीलापन, संरक्षण और जवाबदेही) विधेयक, 2026
- सामान नियम 2026
- यूजीसी 2026 इक्विटी विनियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- अन्य प्रमुख खबरें

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ 14
- एपस्टीन फाइल्स विवाद
- दो-राज्य शांति सूत्र को जाने
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा
- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए
- भारत-यूके और उत्तरी आयरलैंड सामाजिक सुरक्षा समझौता (2026)
- ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की चीन यात्रा
- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
- वेनेजुएला ने एमनेस्टी विधेयक को मंजूरी दी
- UNSC सदस्यता की 'तीसरी श्रेणी'
- नेतन्याहू का नियोजित 'षट्भुज' गठबंधन क्या है?
- क्या नया 'निर्वासन अधिनियम' एच-1बी वीजा को लक्षित करता है?
- अन्य प्रमुख खबरें

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार 33
- भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता
- अमेरिकी व्यापार समझौते में किसानों को बचाने की भारत की योजना
- अमेरिका फरवरी, 2026 से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाएगा
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ पर लगाई रोक
- प्रोजेक्ट वॉल्ट: $12 बिलियन अमेरिकी रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिज भंडार
- सोने के मूल्य को समझना
- एग्रीस्टैक - यूपीआई के बाद भारत का अगला बड़ा डिजिटल पुश
- पावर गैप इंडेक्स
- जीएम फसलें
- 'भारत टैक्सी' - भारत की पहली सहकारी राइड-हेलिंग सेवा
- अमेरिका-बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौता
- भारत और फ्रांस ने डीटीएसी को संशोधित करने के लिए हस्ताक्षर किए
- भारत-कनाडा ऊर्जा सहयोग
- अन्य प्रमुख खबरें

रक्षा एवं सुरक्षा 47
- राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति "समर्थन"
- बहुराष्ट्रीय CTF-154 टास्क फोर्स
- 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ का सौदा
- भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर उत्पादन
- अन्य प्रमुख खबरें
- माह के रक्षा/सैन्य अभ्यास

पर्यावरण और पारिस्थितिकी 56
- ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट
- हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना
- पटना पक्षी अभयारण्य और छाड़ी-ढांड
- नागालैंड में पैंगोलिन के शिकार पर रोक
- सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएं
- मेरी रसोई योजना
- पीएम राहत योजना
- नए सेवा तीर्थ कार्यालय से चार प्रमुख योजनाएं
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
- केरल एनपीएस को एश्योर्ड पेंशन स्कीम से लेगा
- नमो लक्ष्मी योजना
- तुलबुल नेविगेशन परियोजना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 59
- व्यापक कार्बन-व्यापार कार्यक्रम
- बीआईआरएसी-आरडीआई फंड
- भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी
- स्वदेशी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन
- ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष
- स्वास्थ्य एआई इकोसिस्टम के लिए SAHI और BODH
- अग्नि-III इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
- नियोनसैट-1ए
- एआई-डिज़ाइन वायरस "Evo-Φ2147"
- अन्य प्रमुख खबरें

संस्कृति एवं इतिहास 64
- चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल
- मिस्र की राजाओं की घाटी में भारतीय भाषा के शिलालेख
- केरल का नाम बदलकर केरलम हुआ
- विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान
- अन्य प्रमुख खबरें

चर्चित व्यक्ति 79
- नियुक्तियाँ
- निधन

खेल-कूद 81
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण दिन 85
पुस्तकें एवं लेखक 86
केंद्रीय बजट 2026-27 हाइलाइट्स 88
आर्थिक सर्वेक्षण हाइलाइट्स 91

बिजनेस न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज, इंडिया न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज एवं कई अन्य विषयों को कवर किया गया .....

समाचार साभार

बीबीसी, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, पीआईबी, पीटीआई, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस लाइन, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल एवं अन्य सभी प्रमुख समाचार पत्र

राजतन्त्र एवं शासन

पूजा स्थल अधिनियम: कानूनी लड़ाई, एक नज़र

1991 के कानून का बैकग्राउंड

प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट, 1991 को सभी पूजा की जगहों का धार्मिक स्टेटस 15 अगस्त, 1947 जैसा ही रखने के लिए पास किया गया था। यह उस तारीख के बाद उनके धर्म या कैरेक्टर में किसी भी तरह के बदलाव को रोकता है।

यह कोर्ट को इन जगहों के धार्मिक कैरेक्टर को बदलने के बारे में नए केस या मामलों की सुनवाई करने से भी रोकता है।

कानून को क्यों चैलेंज किया जा रहा है

याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र के पास यह कानून बनाने का अधिकार नहीं था क्योंकि भारतीय संविधान के तहत "तीर्थयात्रा" और "पब्लिक ऑर्डर" जैसे मामले राज्य के विषय हैं। इसमें कहा गया है कि यह कानून कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेता है, जो एक फंडामेंटल राइट है। 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ डेट को उन समुदायों के लिए मनमाना और गलत बताया गया है जिनके पूजा की जगहों में उस तारीख से पहले बदलाव किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या किया है

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की कोर्ट को इस एक्ट से जुड़े मामलों में नए केस रजिस्टर करने या फाइनल ऑर्डर जारी करने से तब तक रोक दिया है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का फैसला नहीं हो जाता। यह रोक पहले से पेंडिंग मामलों के साथ-साथ नए मामलों पर भी लागू होती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक कोई असरदार अंतरिम आदेश (जैसे ASI द्वारा सर्वे) पास नहीं किया जाना चाहिए।

- हाल की कोर्ट कार्रवाई: अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में एक याचिका और यह दावा कि यह कभी एक हिंदू मंदिर था, खारिज कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह अपने मौजूदा निर्देशों को सख्ती से लागू करेगा।
- एक्ट के समर्थन में तर्क: समर्थकों का कहना है कि यह कानून सेक्युलरिज़्म को बचाने और ऐतिहासिक झगड़ों को फिर से होने से रोकने में मदद करता है। 2019 के अयोध्या फैसले में इसे राष्ट्रीय एकता के लिए एक ज़रूरी टूल के तौर पर बताया गया था।
- मौजूदा स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस संवैधानिक सवाल पर फैसला नहीं किया है कि एक्ट खुद वैध है या नहीं। मामला जारी है।

आसान शब्दों में

1991 का एक कानून भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान में बदलाव को रोकता है। लोग तर्क देते हैं कि यह गैर-संवैधानिक है और न्याय को रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े सवाल का हल होने तक कानून के तहत कानूनी कार्रवाई रोक दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई की इजाज़त दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कोर्ट परिसर के आसपास ट्रैफिक जाम की आशंका के कारण 16 से 20 फरवरी 2026 तक वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध और रजिस्ट्री द्वारा जारी एक सर्कुलर के आधार पर लिया गया।

वर्चुअल सुनवाई ऑप्शनल है, और सभी बेंच हाइब्रिड मोड (फ़िज़िकल + वर्चुअल) में काम करेंगी। इसी तरह, दिल्ली हाई कोर्ट ने AI समिट और दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों को कोर्ट परिसर के पास होने को ध्यान में रखते हुए 16 से 23 फरवरी 2026 तक वकीलों और केस करने वालों को वर्चुअल पेशी की इजाज़त दी।

यह क्यों ज़रूरी है

न्याय और डिजिटल कोर्ट तक पहुँच

वर्चुअल सुनवाई की इजाज़त न्यायिक प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाती है, जिससे असाधारण घटनाओं के दौरान वकीलों और केस करने वालों के लिए न्याय तक पहुँच बेहतर होती है। वर्चुअल और हाइब्रिड कोर्ट की कार्यवाही फिजिकल मौजूदगी पर निर्भरता कम करती है, खासकर इमरजेंसी, ज़्यादा ट्रैफिक वाले इवेंट, या भारी भीड़ या खराब एयर क्वालिटी जैसी पब्लिक सेफ्टी चिंताओं के दौरान।

AI इम्पैक्ट समिट का संदर्भ

नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट (16–20 Feb 2026) एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है जो पॉलिसीमेकर, इंडस्ट्री लीडर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में इनोवेटर को एक साथ लाता है। समिट के आसपास सिक्योरिटी और ट्रैफिक के उपायों को तेज़ कर दिया गया है, जिसमें भीड़ और पब्लिक सेफ्टी को मैनेज करने के लिए बड़ी पुलिस टुकड़ियों की तैनाती भी शामिल है।

ज्यूडिशियल रिफॉर्म और वर्चुअल हियरिंग

COVID-19 महामारी के बाद भारत में वर्चुअल हियरिंग आम हो गई, जिससे देश भर में कोर्ट के कामकाज के हाइब्रिड तरीके अपनाए गए। कोर्ट ने आसान डिजिटल कार्यवाही में मदद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है।

PMO सेवा तीर्थ शिफ्ट हुआ

प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) ऑफिशियली ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से — जो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से इसका बेस था — नई दिल्ली में सेवा तीर्थ नाम के एक नए बने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया है। यह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह 78 सालों में PMO की लोकेशन में पहली शिफ्ट है और ब्रिटिश-युग की कॉलोनियल इमारतों में सेंटर्ड फैसले लेने के दौर का अंत करता है।

इस शिफ्टिंग की खास बातें:

सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (NSCS) के साथ एक इंटीग्रेटेड कैंपस में होगा, जो कई जगहों पर बिखरे हुए ऑफिस की जगह लेगा। यह कॉम्प्लेक्स डिजिटली इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस, स्मार्ट एक्सेस सिस्टम से इक्विप्ड है, और सस्टेनेबिलिटी के लिए 4-स्टार GRIHA एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। पास के कर्तव्य भवन-1 और 2 में कई खास मिनिस्ट्री होंगी, जिससे बेहतर इंटर-मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंट गवर्नेंस हो सकेगा। मशहूर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग, जिनमें कभी डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे बड़े मंत्रालय हुआ करते थे, उन्हें भारत के सिविलाइज़ेशनल इतिहास को दिखाने के लिए 'युगीन युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम' में बदल दिया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट:

यह एक बड़ी अर्बन रीडेवलपमेंट पहल है जिसका मकसद नई दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री इलाकों को मॉडर्न बनाना है, जिसमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेवा तीर्थ जैसी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और पब्लिक जगहें बनाना शामिल है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2019 में भारत में गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए की गई थी।

साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का महत्व:

साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक ब्रिटिश ज़माने की मशहूर बिल्डिंग हैं जिन्हें आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था और 1931 में पूरा किया गया था; आज़ादी के बाद से ये भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाउस के कोर के तौर पर काम करती थीं। असल में, साउथ ब्लॉक PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का लोकेशन रहा है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री थे।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर गाइडलाइंस जारी

नया क्या है?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सरकारी और पब्लिक फंक्शन में भारत के राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को गाने के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। जब भी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान (जन गण मन) के साथ गाया जाता है, तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाना चाहिए। गाइडलाइंस में यह ज़रूरी है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ओरिजिनल रचना के सभी छह छंद गाए जाएं — पूरा वर्शन वापस लाया जाए।

खास प्रोटोकॉल और मौके

ऑफिशियल सेरेमनी

इन मौकों पर गाया/बजाया जाएगा:

- राज्य के फंक्शन में प्रेसिडेंट और गवर्नर का आना और जाना
- नेशनल फ्लैग फहराना
- सिविल इंवेस्टीचर और अवॉर्ड सेरेमनी
- स्टेट मीडिया (ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न) पर प्रेसिडेंट के एड्रेस से पहले और बाद में

स्कूल और पब्लिक इवेंट

स्कूलों को नेशनल सिंबल के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए दिन की शुरुआत नेशनल सॉन्ग से करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। यह गाना सरकार द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए पब्लिक इवेंट में भी डेकोरम के साथ गाया जाना है।

स्टैंडिंग प्रोटोकॉल

जब वंदे मातरम बजाया या गाया जाता है, तो वहां मौजूद लोगों को अटेंशन में खड़ा होना चाहिए। एक्सेप्शन: अगर गाना सिनेमा या स्क्रीनिंग में न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के तौर पर बजाया जाता है, तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।

ऑफिशियल वर्शन की डिटेल्स

ऑफिशियल रेंडिशन में वंदे मातरम के सभी छह स्टैंज़ा शामिल हैं, जो अपने ओरिजिनल रूप में वापस आते हैं, और लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड का है।

ऐतिहासिक और प्रासंगिक बैकग्राउंड

वंदे मातरम के बारे में

इसे 19वीं सदी के आखिर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवेल आनंदमठ में लिखा था। इसे 1950 में संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया था, जो राष्ट्रगान (जन गण मन) से अलग था। इसके पूरे छह छंद ऐतिहासिक रूप से आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते थे; कई औपचारिक समारोहों में केवल पहले दो ही गाए जाते थे।

आज़ादी के आंदोलन में महत्व

वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन में एक नारा था और देशभक्ति के जोश का प्रतीक था। (सामान्य ऐतिहासिक तथ्य) इसकी बहाली राज्य के प्रोटोकॉल में राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक पहचान पर ज़ोर दिखाती है।

कानूनी और प्रोटोकॉल स्टेटस

राष्ट्रगान के विपरीत, राष्ट्रीय गीत को अभी तक स्पष्ट संवैधानिक या कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है, हालांकि MHA की गाइडलाइन इसे आधिकारिक आयोजनों में औपचारिक औपचारिक दर्जा देती हैं। प्रिवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 अभी सीधे तौर पर नेशनल एंथम पर लागू होता है, लेकिन वंदे मातरम पर नहीं।

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2026

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। इस बिल का मकसद इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के तहत आने वाले श्रम कानूनों को रद्द करने और जारी रखने के बारे में कानूनी स्पष्टता देना है।

अमेंडमेंट का मकसद

- रद्द किए गए श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति के बारे में किसी भी तरह की उलझन को दूर करना।
- इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के सेक्शन 104 के तहत "सेविंग्स क्लॉज" को मजबूत करना।
- पिछले एक्ट्स को रद्द करने को लेकर भविष्य में होने वाले मुकदमे या कानूनी झगड़ों को रोकना।
- पुराने श्रम कानूनों से नए कोड फ्रेमवर्क में आसानी से बदलाव पक्का करना।

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के तहत रद्द किए गए एक्ट

2020 कोड में ये शामिल किए गए और उनकी जगह ली गई:

- ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926
- इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट, 1946
- इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947
- अमेंडमेंट बिल इस बात को पक्का करता है कि ये रद्द किए गए एक्ट कानूनी तौर पर मान्य हैं और लागू हैं।

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के बारे में

- संसद द्वारा पास किए गए चार लेबर कोड में से एक।
- इसका मकसद भारत के लेबर कानूनों को मज़बूत और मॉडर्न बनाना है।
- इन पर फोकस: ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल झगड़े, रोज़गार की शर्तें, छंटनी और ले-ऑफ

भारत में चार लेबर कोड

भारत ने 29 सेंट्रल लेबर कानूनों को चार कोड में मिला दिया:

- मज़दूरी पर कोड, 2019
- इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020
- ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड, 2020
- सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020

अहम सार्वजनिक मुद्दों को सुलझाने हेतु कई प्राइवेट मेंबर्स के बिल

राज्यसभा (संसद का ऊपरी सदन) ने अपने प्राइवेट मेंबर बिज़नेस सेशन के दौरान कई प्राइवेट मेंबर्स के लेजिस्लेटिव बिलों पर चर्चा की।

प्राइवेट मेंबर्स के बिल क्या होते हैं?

- ये ऐसे बिल होते हैं जिन्हें उन सांसदों द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं।

- ये कई तरह के सार्वजनिक और सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, हालांकि ये शायद ही कभी कानून बन पाते हैं।

पेश किए गए या लाए गए महत्वपूर्ण बिल

- एयरलाइन पैसेंजर्स राइट्स बिल
- शिवसेना (UBT) के एक सांसद द्वारा लाया गया।
- इसका मकसद एयरलाइन यात्रियों के लिए अधिकार और सुरक्षा स्थापित करना है।

एजुकेशनल कंसल्टेंसी रेगुलेशन बिल

- CPI (M) के ए ए रहीम द्वारा पेश किया गया।
- इसका मकसद एजुकेशनल कंसल्टेंसी को रेगुलेट करना और छात्रों को गलत तरीकों से बचाना है।

स्मॉल क्लेम्स कोर्ट बिल

- बीजेपी के संजय सेठ द्वारा लाया गया।
- इसका मकसद छोटे वित्तीय विवादों को कुशलता से सुलझाने के लिए आसान अदालतों का गठन करना है।

क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (रेज़िलिएंस, प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी) बिल, 2026

निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा पेश किया गया। इसका मकसद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करना और उसकी सुरक्षा करना है और नुकसान या जानमाल के नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराना है। इसका मकसद लापरवाही वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण होने वाली मौतों को गंभीर आपराधिक अपराध मानना है।

शक्ति सम्मान (महिलाओं के लिए समान वेतन) बिल, 2026

यह भी कार्तिकेय शर्मा द्वारा पेश किया गया। इसका मकसद AI-आधारित पोर्टल और नौकरी मूल्यांकन मानकों के माध्यम से लैंगिक वेतन अंतर को खत्म करना है। इसका मकसद समान वेतन लागू करने और भेदभाव को खत्म करने के लिए महिलाओं के लिए वेतन समानता के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्रस्ताव करना है।

ये बिल क्यों महत्वपूर्ण हैं

इनका मकसद आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले असली मुद्दों को सुलझाना है - यात्रा अधिकारों और शिक्षा सुधारों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा और महिलाओं के समान वेतन तक। ऐसे बिलों पर चर्चा उन मुद्दों को उजागर करती है जिन्हें सांसद महत्वपूर्ण मानते हैं, भले ही ये बिल तुरंत कानून न बनें।

बैगेज नियम 2026

नए बैगेज नियम, 2026 क्या हैं?

भारत सरकार ने बैगेज नियम, 2026 नोटिफाई किए हैं और नए कस्टम बैगेज (घोषणा और प्रोसेसिंग) रेगुलेशन, 2026 जारी किए हैं। ये नियम भारत आने-जाने वाले लोगों पर लागू होते हैं और इनका मकसद एयरपोर्ट पर बैगेज की प्रक्रियाओं को आसान और तेज़ बनाना है।

नए नियम क्यों बनाए गए?

नए नियमों से कस्टम पर कागजी कार्रवाई कम होगी। ये पारदर्शिता बढ़ाएंगे और यात्रियों के लिए बैगेज क्लीयरेंस को तेज़ करेंगे। ये बदलती आर्थिक स्थितियों, ज़्यादा लोगों के यात्रा करने और यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों को दर्शाते हैं।

यात्रियों के लिए मुख्य बदलाव

ड्यूटी-फ्री भत्ता

भारत में सामान लाने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। इसका मतलब है कि ₹75,000 तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए लाया जा सकता है। विदेशी पर्यटकों के लिए, ड्यूटी-फ्री लिमिट अब ₹25,000 है।

इलेक्ट्रॉनिक और एडवांस घोषणा

- यात्री अब कस्टम पर पहुंचने से पहले अपने बैगेज की घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
- इससे एयरपोर्ट पर समय बचाने और प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने में मदद मिलती है।
- एक लैपटॉप ड्यूटी-फ्री: 18 साल से ज़्यादा उम्र के यात्रियों को बिना ड्यूटी दिए एक लैपटॉप लाने की अनुमति है।
- अस्थायी आयात और पुनः आयात: विदेश ले जाए गए और बाद में वापस लाए गए सामान के लिए नए नियमों के तहत प्रक्रियाएं आसान होंगी।
- पालतू जानवर ड्यूटी-फ्री: यात्री अब निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए पालतू जानवरों को ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।

विशेष भत्ते

- गहने: नए नियमों में कुछ शर्तों के तहत बिना ड्यूटी के गहने लाने के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं।

- निवास का स्थानांतरण: जो लोग अपना निवास भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं, उन्हें सामान और व्यक्तिगत सामान लाने के लिए स्पष्ट और बेहतर लाभ मिलेंगे।

अपेक्षित लाभ

- उम्मीद है कि इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कस्टम क्लीयरेंस आसान और तेज़ होगा।
- कम वेरिफिकेशन और आसान प्रक्रियाएं भारतीय निवासियों और विदेशी पर्यटकों दोनों की मदद करेंगी।

UGC 2026 इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशंस, 2026 के लागू होने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक 2012 के UGC इक्विटी नियम लागू रहेंगे। यह रोक का आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिया, जिन्होंने केंद्र और UGC को नोटिस भी जारी किए।

नए UGC इक्विटी रेगुलेशंस (2026) की पृष्ठभूमि

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशंस, 2026 को नोटिफाई किया था। इन नियमों का मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना था, खासकर जाति-आधारित भेदभाव से संबंधित। इन रेगुलेशंस में कैंपस में भेदभाव के मामलों से निपटने के लिए नई परिभाषाएं, शिकायत तंत्र और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का प्रस्ताव था। इन्हें 2012 के मौजूदा UGC इक्विटी रेगुलेशंस की जगह लेने के लिए बनाया गया था। नोटिफाई होने के बाद, 2026 के नियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों में तुरंत लागू किया जाना था।

नए UGC रेगुलेशंस को क्यों चुनौती दी गई?

- भेदभाव की अस्पष्ट परिभाषा
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट और बहुत व्यापक थी।
- उन्हें डर था कि सामान्य शैक्षणिक फैसलों (जैसे मूल्यांकन, अनुशासन, या उपस्थिति के नियम) को भेदभाव के रूप में गलत समझा जा सकता है।

दुरुपयोग की गुंजाइश

- आलोचकों ने दावा किया कि ये रेगुलेशंस दुरुपयोग के लिए सक्षम थे क्योंकि स्पष्ट सुरक्षा उपायों के बिना शिकायतें दर्ज की जा सकती थीं।
- इस बात की चिंता थी कि झूठी या प्रेरित शिकायतें शिक्षकों, प्रशासकों और संस्थानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

कुछ समूहों के प्रति कथित पूर्वाग्रह

- नियमों पर एकतरफा होने का आरोप लगाया गया था, कथित तौर पर कुछ सामाजिक समूहों का पक्ष लेने का।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह ढांचा सामान्य श्रेणी के छात्रों को प्रभावी शिकायत निवारण से बाहर कर सकता है।

संवैधानिक चिंताएं

- चुनौती देने वालों ने तर्क दिया कि ये रेगुलेशंस संविधान के तहत कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकते हैं।
- उन्होंने दावा किया कि ये नियम कैंपस में सद्भाव को बढ़ावा देने के बजाय सामाजिक विभाजन पैदा कर सकते हैं।

समीक्षा के बिना मौजूदा नियमों को बदलना

- 2012 के रेगुलेशंस पहले से ही लागू थे और काम कर रहे थे।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नए नियम पुराने सिस्टम के प्रदर्शन की पर्याप्त सलाह या समीक्षा के बिना पेश किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों किया

- सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 2026 के रेगुलेशंस के कुछ प्रावधान प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और समस्याग्रस्त थे। कोर्ट को लगा कि उन्हें काम करने की इजाज़त देने से गंभीर सामाजिक नतीजे हो सकते हैं।
- इसलिए, उसने 2026 के नियमों पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक 2012 के नियम लागू रहेंगे।

अन्य प्रमुख खबरें

रेप बनाम रेप की कोशिश: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी फर्क समझाया गया

केस में क्या हुआ?

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले ने 20 साल पुराने रेप केस में सज़ा को रेप की कोशिश से बदलकर रेप की कोशिश कर दिया।

यह फैसला 16 फरवरी, 2026 को हाई कोर्ट की एक बेंच ने सुनाया।

केस का बैकग्राउंड

यह केस असल में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 2004 में हुई एक घटना से जुड़ा है। सर्वाइवर ने कहा कि एक आदमी उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले गया, दोनों के कपड़े उतारे और उसका सेक्शुअल असॉल्ट किया। 2005 में, एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को इंडियन पीनल कोड के तहत रेप का दोषी ठहराया और उसे गलत तरीके से कैद करने के लिए छह महीने के साथ सात साल की जेल की सज़ा सुनाई।

मुख्य कानूनी सवाल: पेनेट्रेशन और रेप

2004 में जो कानून था, उसके तहत रेप को कानूनी तौर पर रेप मानने के लिए वजाइना में पेनिस के पेनेट्रेशन का सबूत ज़रूरी था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना साबित पेनिट्रेशन के इजैक्युलेशन या जेनिटल कॉन्टैक्ट उस समय रेप की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं करता था। इस वजह से, कोर्ट ने कहा कि सबूत रेप के ज़रूरी हिस्से को पक्के तौर पर साबित नहीं करते।

सबूतों में विरोधाभास

कोर्ट ने सर्वाइवर की गवाही की बारीकी से जांच की और पाया कि क्या पेनिट्रेशन सच में हुआ था, इस बारे में विरोधाभास है। मेडिकल सबूतों से पता चला कि हाइमन सही सलामत थी, और डॉक्टर रेप पर कोई पक्की राय नहीं दे सके, उन्होंने सिर्फ़ थोड़ा पेनिट्रेशन होने का सुझाव दिया। क्योंकि सबूतों से पेनिट्रेशन साफ तौर पर साबित नहीं हुआ, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि इस अपराध को पूरा रेप नहीं माना जा सकता।

हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

हाई कोर्ट ने रेप की सज़ा को रद्द कर दिया और इसे रेप करने की कोशिश में बदल दिया। सज़ा सात साल से घटाकर तीन साल और छह महीने की कड़ी कैद कर दी गई। कोर्ट ने गलत तरीके से कैद करने के लिए एक अलग सज़ा को भी बरकरार रखा।

यह फ़ैसला क्यों ज़रूरी है

इस फ़ैसले पर बहुत बहस और आलोचना हुई है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि 'पेनेट्रेशन' की टेक्निकल परिभाषाओं पर कानूनी फ़ोकस, बिना सहमति के यौन हिंसा की गंभीर प्रकृति को नज़रअंदाज़ करता है। कुछ कानूनी जानकारों का तर्क है कि यह फ़ैसला हमले की मॉडर्न समझ के बजाय पुराने कानूनों के सख़्त इस्तेमाल को दिखाता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान (केस से जुड़े आर्टिकल/सेक्शन)

सेक्शन 375, इंडियन पीनल कोड (IPC) – रेप को बताता है (2013 से पहले के कानून के अनुसार जो 2004 की घटना पर लागू होता है, जहाँ पेनेट्रेशन ज़रूरी था)।

- सेक्शन 376, IPC – रेप के लिए सज़ा।
- सेक्शन 511, IPC – अपराध करने की कोशिश करने की सज़ा (जब सज़ा को रेप की कोशिश में बदला जाता है तो लागू होता है)।
- सेक्शन 342, IPC – गलत तरीके से कैद करने की सज़ा (केस में भी बरकरार)।

संवैधानिक प्रावधान (संदर्भ के हिसाब से)

आर्टिकल 136 – स्पेशल लीव पिटीशन (अगर मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है)। आर्टिकल 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (इसमें सम्मान और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत शामिल हैं)।

आगे का रास्ता:

- यौन अपराधों की साफ़ और मज़बूत कानूनी परिभाषाएँ पक्का करें।
- सर्वाइवर-सेंट्रिक और ट्रॉमा-सेंसिटिव न्यायिक तरीका अपनाएँ।
- जांच और फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने में सुधार करें।
- जजों और पुलिस को रेगुलर जेंडर-सेंसिटाइज़ेशन ट्रेनिंग दें।
- यौन अपराध के मामलों में तेज़ी से ट्रायल पक्का करें।

चेक बाउंस मामलों में बरी होने पर अपील के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट साफ़ करेगा

भारत का सुप्रीम कोर्ट चेक बाउंस मामलों के बारे में एक कानूनी सवाल की जांच कर रहा है। सवाल यह है: क्या कोई शिकायत करने वाला ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने (दोषी नहीं पाए जाने का फैसला) के खिलाफ ऊपरी अदालत से इजाज़त (लीव) लिए बिना अपील कर सकता है?

बैकग्राउंड: चेक बाउंस मामले

चेक तब "बाउंस" होता है जब कोई बैंक उस पर लिखी रकम का पेमेंट करने से मना कर देता है, आमतौर पर पैसे कम होने या बैंक के दूसरे सही कारणों से। चेक बाउंस मामले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI एक्ट) के सेक्शन 138 के तहत आते हैं, जिससे चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया कि क्या शिकायत करने वाले बरी होने के बाद सीधे अपील कर सकते हैं। मुख्य सवाल: क्या शिकायत करने वाले को पहले हाई कोर्ट से "अपील की लीव" (परमिशन) लेनी होगी, या वे बिना पहले से इजाज़त के अधिकार के तौर पर अपील कर सकते हैं?

पिछली कानूनी बातें अलग-अलग

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों (2013 और 2015) में कहा गया था कि शिकायत वाले मामलों में, शिकायत करने वाले को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए स्पेशल लीव लेनी होगी। लेकिन 2025 के एक फैसले (सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए ज्ञानशेखरन) में कहा गया कि एक शिकायत करने वाला जो कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के तहत "विक्टिम" भी है, वह पहले लीव मांगे बिना सीधे सेक्शन 372 के तहत अपील कर सकता है।

इसमें शामिल कानूनी नियम

सेक्शन 372, CrPC:

आम तौर पर बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, जब तक कि कानून इसकी इजाज़त न दे। लेकिन यह एक "विक्टिम" को बरी होने या कम मुआवज़े के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है।

सेक्शन 378(4), CrPC:

कहता है कि शिकायत वाले मामलों (जैसे चेक बाउंस) में, शिकायत करने वाले को बरी होने के खिलाफ अपील करने के लिए हाई कोर्ट से लीव लेनी होगी।

CrPC सेक्शन 2(wa):

"विक्टिम" का मतलब है वह व्यक्ति जिसे कोई नुकसान या चोट लगी हो, जिसमें फाइनेंशियल नुकसान भी शामिल है — जो चेक बाउंस केस में शिकायत करने वाले को "विक्टिम" बनाता है अगर नुकसान साबित हो सके।

मुख्य कानूनी सवाल

क्या चेक बाउंस केस में शिकायत करने वाले को CrPC के तहत "विक्टिम" माना जाना चाहिए और बिना इजाज़त के अपील करने की इजाज़त दी जानी चाहिए?

या उन्हें अपील फाइल करने से पहले सेक्शन 378(4) के तहत इजाज़त लेनी होगी?

सुप्रीम कोर्ट इस झगड़े को साफ करने की कोशिश कर रहा है।

यह क्यों मायने रखता है

अगर शिकायत करने वाला सीधे अपील कर सकता है:

बरी होने के फैसले को चुनौती देना आसान हो जाता है।

पहले इजाज़त लेने की रुकावट के बिना केस का मेरिट के आधार पर रिव्यू किया जा सकता है।

अगर इजाज़त चाहिए:

शिकायत करने वालों को अपील की सुनवाई से पहले हाई कोर्ट को यह यकीन दिलाना होगा कि बरी होने में कोई गलती थी, जो एक ज़्यादा लिमिट है।

RERA मुश्किल में? सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी क्यों दी कि इसे बंद किया जा सकता है

क्या हुआ

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि अगर RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) घर खरीदने वालों की सुरक्षा नहीं करती है, तो इसे बंद किया जा सकता है।

कोर्ट नाराज़ क्यों है

कोर्ट ने कहा कि RERA घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने के बजाय डिफ़ॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद करने के अलावा कुछ भी काम का करने में नाकाम रहा है। इसने सुझाव दिया कि अगर अथॉरिटी सिर्फ़ बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाती है, खरीदारों को नहीं, तो यह कानून के मकसद को खत्म कर देता है।

कौन सा केस सुना जा रहा था

ये टिप्पणियाँ तब की गईं जब सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश RERA से जुड़े एक केस की सुनवाई कर रहा था।

कानून का मकसद क्या था

RERA एक्ट, 2016 इसलिए बनाया गया था:

- रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट और बढ़ावा देना
- प्रॉपर्टी की बिक्री को कुशल और पारदर्शी बनाना
- घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना
- खरीदारों के लिए एक तेज़ विवाद समाधान सिस्टम और अपील प्रोसेस देना।

RERA के काम करने के तरीके की आलोचना

घर खरीदने वालों और कोर्ट ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया है:

- मामलों को सुलझाने में देरी
- ऑर्डर को ठीक से लागू न करना
- कुछ राज्यों में ट्रांसपेरेंसी की कमी
- रेगुलेटर कभी-कभी सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पाते।
- कई लोग शिकायत करते हैं कि RERA ऑर्डर तो दे सकता है, लेकिन कभी-कभी उसे पूरी तरह से लागू करने की पावर नहीं होती।

कोर्ट ने क्या कहा कि क्या हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने RERA को ऑफिशियली खत्म नहीं किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर यह लगातार फेल होता रहा, तो इसके होने पर फिर से विचार किया जा सकता है या इसे खत्म भी किया जा सकता है।

यह क्यों मायने रखता है

ये बातें इस बात को लेकर गंभीर चिंताओं को दिखाती हैं कि RERA राज्यों में कैसे काम करता है। यह सरकार और रेगुलेटर पर कमियों को ठीक करने, परफॉर्मेंस सुधारने और यह पक्का करने के लिए दबाव डाल सकता है कि कानून घर खरीदने वालों की अच्छे से सुरक्षा करे।

उत्तराखंड ने UCC (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया

उत्तराखंड सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम, 2024 के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी किया है।

संशोधन का उद्देश्य:

- यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार लाना, जिससे इसे लागू करना आसान और अधिक पारदर्शी हो सके।
- कार्यान्वयन को मजबूत करना, समानता सुनिश्चित करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि संदर्भ:

- यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पहली बार 27 जनवरी, 2025 को उत्तराखंड में लागू किया गया था, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया जिसने UCC को लागू किया।
- UCC धर्म पर आधारित कई व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य नागरिक कानून लाता है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और लिव-इन रिलेशनशिप शामिल हैं।
- इस दिन को पूरे राज्य में सालाना "UCC दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

UCC के तहत मुख्य प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक सुधार:

- नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण – लगभग 100% विवाह पंजीकरण अब ऑनलाइन पूरे हो रहे हैं; पति-पत्नी और गवाहों के वीडियो बयान दूर से अपलोड किए जा सकते हैं।
- तेज़ प्रोसेसिंग – विवाह प्रमाण पत्र औसतन पांच दिनों के भीतर जारी किए जाते हैं।
- एक साल में 5 लाख से अधिक आवेदन संसाधित किए गए हैं, जिसमें विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण शामिल हैं।
- तलाक और विरासत के लिए समान आधार और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं एक ही नागरिक कानून के तहत लाई गई हैं।

दंडात्मक और दंड सुधार (संशोधन का फोकस):

- संशोधन अध्यादेश विवाह और लिव-इन संबंधों में धोखाधड़ी, पहचान छिपाने और जबरदस्ती को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधानों को स्पष्ट करता है।
- अपीलीय तंत्र और पंजीकरण से संबंधित शक्तियों को मजबूत करता है।

संवैधानिक आधार:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को "भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने" का निर्देश देता है। उत्तराखंड UCC इस निर्देशक सिद्धांत से प्रेरित एक राज्य-स्तरीय पहल है।

UCC का महत्व:

- बहुविवाह, तीन तलाक, हलाला और असमान संपत्ति अधिकारों जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने का लक्ष्य है।
- सभी धर्मों के लिए एक सामान्य कानून लागू करके लैंगिक न्याय और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।

जॉइंट फ़ैमिली का हिंदू कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ से अलग

केस किस बारे में था

गुजरात में एक मुस्लिम महिला ने कोर्ट से वडोदरा (अकोटा और तंदलजा) में अपने मरे हुए पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। उसने दावा किया कि वह इस हिस्से की हक़दार है, भले ही 1983 से एक फ़ैमिली सेटलमेंट (एग्रीमेंट) हुआ था, जिसके तहत उसे और उसकी बहन को प्रॉपर्टी के बदले एक तय रकम दी गई थी।

गुजरात हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया

गुजरात हाई कोर्ट ने उसका दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला हिंदू लॉ कॉन्सेप्ट के तहत "पैतृक प्रॉपर्टी" का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ़ हिंदू विरासत कानून में लागू होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं।

दावा क्यों खारिज किया गया

1. अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून

हिंदू लॉ के तहत, जॉइंट फ़ैमिली और पैतृक प्रॉपर्टी का आइडिया मौजूद है — जहाँ प्रॉपर्टी पीढ़ियों से एक अनडिवाइडेड फ़ैमिली के तौर पर आगे बढ़ती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, जॉइंट फ़ैमिली का आइडिया मौजूद नहीं है। हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी अलग-अलग होती है, और विरासत का मामला मौत के बाद ही धार्मिक उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर तय होता है।

2. मुस्लिम लॉ में व्यक्तिगत मालिकाना हक

मुस्लिम लॉ में, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पर्सनल होता है, और परिवार के एक सदस्य के मिलने से सभी रिश्तेदारों को अपने आप फायदा नहीं होता है। उत्तराधिकार (विरासत) का अधिकार तभी मिलता है जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है — जन्म से कोई अपने आप पुश्तैनी हिस्सा नहीं होता है।

3. लंबी देरी और फैमिली सेटलमेंट

महिला ने अपना दावा फाइल करने से पहले कई साल (37 साल) इंतजार किया था। कोर्ट ने कहा कि उसने 1983 के ओरिजिनल फैमिली सेटलमेंट को चुनौती नहीं दी, जिसमें पहले ही एक तय रकम के लिए उसके और उसकी बहन के अधिकारों का सेटलमेंट हो चुका था।

कानूनी सिद्धांत लागू

हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू लॉ के आइडिया (जैसे जॉइंट फैमिली या पुश्तैनी प्रॉपर्टी) का इस्तेमाल तब लागू नहीं होता जब लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। फैसले में इस स्थापित सिद्धांत का जिक्र किया गया कि मुस्लिम लॉ प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार को अलग-अलग मानता है, जॉइंट फैमिली या कोपार्सनरी अधिकारों को मान्यता दिए बिना।

यह क्यों ज़रूरी है

यह केस दिखाता है कि विरासत के अधिकार भारत में हर धर्म के पर्सनल लॉ पर निर्भर करते हैं। यह दिखाता है कि हिंदू और मुस्लिम विरासत के सिद्धांत कैसे अलग हैं, खासकर प्रॉपर्टी के अधिकार और पारिवारिक रिश्तों में। यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पुराने पारिवारिक समझौतों के साथ गलत हुआ है, तो उन्हें समय पर चुनौती देना कितना ज़रूरी है।

TOPPERS CLUB IAS ACADEMY

" कोशिश हमेशा आखरी सांस तक करनी चाहिए !

या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव !!"

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ

एपस्टीन फाइल्स विवाद

एपस्टीन फाइल्स क्या हैं?

"एपस्टीन फाइल्स" यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा सेट है, जो दोषी सेक्स अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ा है। इन फाइलों में उसके अपराधों की जांच से जुड़े लाखों पेज के ईमेल, रिपोर्ट, इमेज और वीडियो शामिल हैं। यह रिलीज़ एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत की गई थी, जो एक US कानून है जो अधिकारियों को इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने के लिए मजबूर करता है। इन फाइलों में एपस्टीन और कई देशों के अमीर या ताकतवर लोगों के बीच बातचीत शामिल है, जिससे दुनिया भर में दिलचस्पी और विवाद पैदा हो गया।

जेफ़री एपस्टीन कौन थे?

जेफ़री एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर थे, जिन्हें 2008 में नाबालिगों से जुड़े सेक्सुअल अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन एक विवादित प्ली डील के ज़रिए वह कड़ी सज़ा से बच गए। उन्हें 2019 में नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल खत्म होने से पहले मैनहट्टन जेल में उनकी आत्महत्या से मौत हो गई।

लेटेस्ट रिलीज़ क्यों ज़रूरी है

जनवरी 2026 के डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 3 मिलियन से ज़्यादा पेज और 2,000 वीडियो हैं, जिसमें ईमेल, मैसेज, इंटरव्यू, इमेज और कोर्ट रिकॉर्ड शामिल हैं। इस मटीरियल में भारत, UK, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और स्लोवाकिया जैसे देशों के असरदार ग्लोबल हस्तियों के कम्युनिकेशन शामिल हैं।

भारत में पॉलिटिकल असर

इस रिलीज़ से भारतीय पॉलिटिक्स में गरमागरम बहस शुरू हो गई, खासकर तब जब फाइलों में एक कथित ईमेल में नरेंद्र मोदी का ज़िक्र था, जो उनके 2017 के इज़राइल के ऑफिशियल दौरे से जुड़ा था।

भारत के विदेश मंत्रालय ने उस ज़िक्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया, इसे "एक दोषी अपराधी की बेकार बातें" कहा और ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

इस विवाद को पॉलिटिकल पार्टियों ने और बढ़ा दिया: कुछ विपक्षी नेताओं ने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर किया और जवाबदेही की मांग की, जबकि रूलिंग पार्टी के नेताओं ने उन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया।

कुछ मामलों में, एपस्टीन फाइल्स से उठने वाले दावों की निगरानी वाली जांच की मांग करते हुए पिटीशन भारत के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची हैं।

नोट: कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जेफरी एपस्टीन से जुड़े मटीरियल में नरेंद्र मोदी का ज़िक्र था, लेकिन इसमें कोई गलत काम होने का सबूत नहीं है, और भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

दुनिया भर में बड़े रिएक्शन

भारत के बाहर, इन फाइलों ने राजनीतिक उथल-पुथल भी मचा दी है। UK में, एपस्टीन के करीबी लोगों से जुड़े डिप्लोमैटिक अपॉइंटमेंट्स के खुलासे से कीर स्टारमर जैसे नेताओं की आलोचना हुई और राजनीतिक पार्टियों के अंदर चुनौतियां पैदा हुईं। नॉर्वे जैसे दूसरे देशों को फाइलों में बताए गए शाही परिवार के सदस्यों और बातचीत से जुड़ी जांच का सामना करना पड़ा।

फाइलों में क्या है

जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में एपस्टीन और बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल हस्तियों, एकेडेमिक्स और सेलिब्रिटीज के बीच ईमेल शामिल हैं, जिनमें से कई अनवेरिफाइड हैं और ऐसे ड्राफ्ट मैसेज हैं जो खुद बताए गए लोगों द्वारा किए गए गलत काम को साबित नहीं करते हैं। कुछ रिकवर किए गए ईमेल कंटेंट से पता चलता है कि अनिल अंबानी जैसे लोगों ने एपस्टीन के कनेक्शन का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल और बिजनेस मीटिंग्स अरेंज करने की कोशिश की, हालांकि ये वेरिफिकेशन के अधीन हैं।

मुख्य मुद्दे

रिडक्शन में नाकामी: कुछ जारी की गई फाइलों में प्राइवेसी प्रोटेक्शन काफी नहीं था, जिससे सेंसिटिव पर्सनल जानकारी सामने आ गई।

ग्लोबल पॉलिटिक्स: कई देशों में विपक्षी पार्टियों ने इन फाइलों का इस्तेमाल सरकारों को चुनौती देने या जांच की मांग करने के लिए किया है।

जवाबदेही पर पब्लिक चर्चा: इस पब्लिकेशन ने इस बारे में चर्चाओं को फिर से शुरू कर दिया है कि जब डॉक्यूमेंट्स बिना कॉन्टेक्स्ट या वेरिफिकेशन के सामने आते हैं तो समाज ताकतवर लोगों के खिलाफ आरोपों को कैसे हैंडल करता है।

जरूरी शब्दों की व्याख्या

1. एपस्टीन फाइल्स: जेफरी एपस्टीन के लीगल केस से जुड़े ऑफिशियल और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा कलेक्शन, जो लीगल मैंडेट के तहत जारी किया गया है।
2. एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट: एक US कानून जिसके तहत एपस्टीन की जांच से जुड़े पहले से सील किए गए डॉक्यूमेंट्स को जारी करना जरूरी है।
3. रेडक्शन: डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ करने से पहले उनसे सेंसिटिव जानकारी छिपाने या हटाने का प्रोसेस।
4. सेक्स ट्रैफिकिंग: एक क्रिमिनल जुर्म जिसमें लोगों, खासकर नाबालिगों का सेक्सुअल मकसद के लिए शोषण किया जाता है।

निष्कर्ष

एपस्टीन फाइल्स के ग्लोबल रिलीज़ ने यूनाइटेड स्टेट्स से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल बहस छेड़ दी है, क्योंकि ताकतवर लोगों से जुड़े बिना वेरिफाइड कम्युनिकेशन सामने आए हैं। जबकि कुछ सरकारों और नेताओं ने आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, इन खुलासों से कई देशों में पॉलिटिकल नैरेटिव, लीगल पिटीशन और पब्लिक स्क्रूटनी को बढ़ावा मिल रहा है।

टू-स्टेट पीस फ़ॉर्मूला को जाने विस्तार से

टू-स्टेट सॉल्यूशन क्या है?

टू-स्टेट सॉल्यूशन इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े को खत्म करने के लिए एक प्रस्तावित शांति योजना है। इसमें दो स्वतंत्र देश बनाने का सुझाव दिया गया है — एक का नाम यहूदी लोगों के लिए इज़राइल और दूसरा फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए फ़िलिस्तीन — जो शांति और सुरक्षा के साथ साथ रहें। यह सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त डिप्लोमैटिक ढांचा है जिसे कई देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन झगड़े को सुलझाने के लिए सपोर्ट करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यह विचार दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब ब्रिटेन फ़िलिस्तीन पर अपना कंट्रोल खत्म करने की तैयारी कर रहा था, और यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में ज़मीन को अलग-अलग यहूदी और अरब देशों में बांटने का प्रस्ताव रखा (UN पार्टीशन प्लान)। उस योजना के बाद 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई, लेकिन उस समय कोई फ़िलिस्तीनी देश नहीं बना था। ज़मीन और अधिकारों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और दशकों तक चलता रहा। 1967 के छह-दिन के युद्ध में, इज़राइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया, जिन इलाकों पर फ़िलिस्तीनी अपने भविष्य के देश का दावा करते हैं।

मुख्य समझौते और कोशिशें

ओस्लो समझौता (1990 का दशक) दो-राज्य के विचार की दिशा में एक बड़ा कदम था। इज़राइल और फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (PLO) वेस्ट बैंक और गाज़ा के कुछ हिस्सों में फ़िलिस्तीनी सेल्फ़-रूल बनाने पर सहमत हुए और बातचीत के ज़रिए भविष्य में एक

फ़िलिस्तीनी राज्य की कल्पना की। इन समझौतों ने इलाकों के कुछ हिस्सों पर शासन करने के लिए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी (PA) की भी स्थापना की।

दो-राज्य समाधान से जुड़े मुख्य मुद्दे

बॉर्डर: भविष्य के बॉर्डर ज़्यादातर 1967 के युद्ध से पहले की लाइनों को फ़ॉलो करेंगे, शायद ज़मीन पर हुए बदलावों को दिखाने के लिए ज़मीन की अदला-बदली के साथ।

यरूशलेम: इज़राइली और फ़िलिस्तीनी दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, जिससे यह सुलझाने के लिए सबसे मुश्किल विवादों में से एक बन गया है।

शरणार्थी: फ़िलिस्तीनी उन लोगों के वापस लौटने के अधिकार पर ज़ोर देते हैं जो पिछले झगड़ों में बेघर हो गए थे या भाग गए थे, जिसका इज़राइल विरोध करता है।

सुरक्षा: इज़राइल हमलों को रोकने के लिए मज़बूत सुरक्षा गारंटी चाहता है, जबकि फ़िलिस्तीनी अपने राज्य पर पूरी आज़ादी चाहते हैं।

इसे लागू करना मुश्किल क्यों है

बस्तियों का विस्तार: कई लोग वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में इज़राइली बस्तियों के बढ़ने को एक कामयाब फ़िलिस्तीनी देश के लिए मौजूद ज़मीन को कम करने वाला मानते हैं, जिससे दो अलग-अलग देशों का विचार कमज़ोर होता है। वेस्ट बैंक में इज़राइल के हालिया पॉलिसी बदलावों, जिनके बारे में आलोचक कहते हैं कि वे इज़राइली कंट्रोल को बढ़ाते हैं और फ़िलिस्तीनी शासन को कमज़ोर करते हैं, को कुछ अधिकारियों ने "असल में संप्रभुता" बनाने वाला और एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी देश की संभावना को कम करने वाला बताया है। भरोसे की कमी और हिंसा: लगातार हिंसा, आपसी अविश्वास और राजनीतिक मतभेद बातचीत को मुश्किल बनाते हैं और एक पक्के समझौते तक पहुँचने की उम्मीद को कम करते हैं।

इंटरनेशनल और रीजनल सपोर्ट

कई देश और ऑर्गनाइज़ेशन — जिसमें यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और अरब लीग देश शामिल हैं — पक्की शांति के लिए बातचीत से बने दो-स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं।

कुछ देशों ने फ़िलिस्तीनी देश को भी मान्यता दी है, जिसके सपोर्टर्स का कहना है कि यह दो देशों के लिए पॉलिटिकल बेस को मज़बूत करता है।

भारत जैसे देशों ने बार-बार बातचीत से बने दो-स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया है, और शांतिपूर्ण बातचीत और इज़राइल और फ़िलिस्तीन को आपसी पहचान देने की अपील की है।

यह क्यों ज़रूरी है

कई डिप्लोमैट टू-स्टेट सॉल्यूशन को दशकों के झगड़े के बाद दोनों लोगों के लिए शांति, न्याय और स्टेबिलिटी पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। बिना किसी साफ़ समझौते के, यह झगड़ा ज़िंदगी, रीजनल रिश्तों और ग्लोबल डिप्लोमेसी पर असर डालता रहता है।

ज़रूरी शब्दों की व्याख्या

1. टू-स्टेट सॉल्यूशन: एक शांति फ्रेमवर्क जो इज़राइलियों और फ़िलिस्तीनियों के लिए अलग, पूरी तरह से आज़ाद देशों का प्रस्ताव करता है।
2. वेस्ट बैंक: 1967 से इज़राइल के कब्ज़े वाला एक इलाका, जिस पर फ़िलिस्तीनियों ने अपने देश का दावा किया है।
3. गाज़ा पट्टी: एक तटीय फ़िलिस्तीनी इलाका जो प्रस्तावित फ़िलिस्तीनी देश का भी हिस्सा है।
4. ओस्लो समझौते: 1990 के दशक में हुए समझौते जिनसे एक औपचारिक शांति प्रक्रिया शुरू हुई और सीमित फ़िलिस्तीनी स्व-शासन स्थापित हुआ।
5. फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी (PA): ओस्लो फ्रेमवर्क के तहत वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों के लिए अंतरिम गवर्निंग बॉडी।
6. बस्तियां: कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में बनी इज़राइली कम्युनिटी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, लेकिन इज़राइल इस पर विवाद करता है।

निष्कर्ष

इज़राइल-फ़िलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए दो-राज्य समाधान सबसे ज़्यादा माना जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बना हुआ है, लेकिन सीमाओं, सुरक्षा, यरुशलम, शरणार्थियों और बस्तियों के विस्तार पर मतभेदों के कारण इसे हासिल करना मुश्किल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज़राइल दौरा

भारत के प्रधानमंत्री 25-26 फरवरी 2026 तक इज़राइल के दो दिन के ऑफिशियल दौरे पर गए। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करना और भारत-इज़राइल पार्टनरशिप को "स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" बनाना है। इस दौरे में डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक सहयोग में बढ़ते रिश्तों पर ज़ोर दिया गया।

दौरे का एजेंडा

- स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सहयोग: यह दौरा डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग को मज़बूत करने पर फोकस करेगा, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बेहतर सहयोग और डिफेंस सिस्टम में संभावित जॉइंट प्रोडक्शन शामिल है।
- टेक्नोलॉजी और इनोवेशन: बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग शामिल है।
- आर्थिक और ट्रेड संबंध: बातचीत का मकसद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाना है, जिसमें आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत-इज़राइल FTA बातचीत का इस्तेमाल करना शामिल है।
- कृषि और जल प्रबंधन: भारत और इज़राइल कृषि इनोवेशन और जल टेक्नोलॉजी में सहयोग की संभावना तलाशेंगे — ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इज़राइल के पास ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है।
- लोगों से लोगों का मिलना-जुलना और कल्चरल डिप्लोमेसी: इस दौरे में भारत में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत और याद वाशेम — वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस सेंटर जैसी खास जगहों पर जाना शामिल है।

इस दौरे का महत्व

- दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना: यह रिश्ता — जिसे पहली बार मोदी के 2017 के दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया था — इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है, शायद इसे "स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" बनाया जा सकता है, जो सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में साझा हितों को दिखाता है।
- जियोपॉलिटिकल संदर्भ: यह दौरा मिडिल ईस्ट में बदलते रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स के बीच हो रहा है और इसका मकसद इज़राइल और अरब देशों दोनों के साथ भारत के मज़बूत संबंधों को बैलेंस करना है।
- व्यापार का महत्व: भारत एशिया में इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसका 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार USD 3.6 बिलियन से ज़्यादा होगा।
- डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग: भारत की विदेश नीति फ़िलिस्तीनी मकसद के लिए ऐतिहासिक समर्थन बनाए रखते हुए इज़राइल के साथ स्ट्रेटेजिक सहयोग को बैलेंस करना जारी रखती है।

इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किए

पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन क्या है?

पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में एक स्ट्रेटेजिक पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ज़रूरी मिनरल्स के लिए सुरक्षित और मज़बूत सप्लाई चेन बनाने पर फोकस करती है। इसका उद्देश्य संभावित रूप से नुकसानदायक सोर्स पर दुनिया भर की निर्भरता कम करना और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी नेटवर्क को मज़बूत करना है।

इंडिया पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल हुआ

इंडिया ने नई दिल्ली में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर ऑफिशियली साइन किए। इस डिक्लेरेशन पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और US अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जैकब हेलबर्ग ने इंडिया में US एम्बेसडर सर्जियो गोर की मौजूदगी में साइन किए।

अलायंस का उद्देश्य और फोकस

इस अलायंस का मकसद एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना है, जिसके लिए ये चीज़ें सुरक्षित की जाती हैं:
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी ज़रूरी मिनरल्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर (चिप्स), और AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसका मकसद जॉइंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, सप्लाई-चेन के जोखिमों की पहचान करना और ज़रूरी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स तक सुरक्षित पहुँच पक्का करना है।

भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व

भारत की एंट्री को अमेरिका और दूसरे सहयोगी पार्टनर्स के साथ ग्लोबल टेक सहयोग को मज़बूत करने के लिए स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी माना जा रहा है। इस अलायंस में शामिल होने से भारत को चिप्स और ज़रूरी कच्चे माल तक लंबे समय तक पहुँच बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे उसके सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते को मज़बूत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन बनाकर आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के तरीके के तौर पर भी देखा जा रहा है।

पैक्स सिलिका का ग्लोबल संदर्भ

पैक्स सिलिका को दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इज़राइल और दूसरे कई शुरुआती पार्टनर देशों के साथ लॉन्च किया गया था।

भारत के शामिल होने से यह एक बड़े कोएलिशन में शामिल हो गया है जिसका मकसद डेमोक्रेटिक देशों के बीच भरोसेमंद टेक पार्टनरशिप बनाना है।

इंडिया–UK और नॉर्दर्न आयरलैंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (2026)

इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) साइन किया है ताकि एक-दूसरे के देश में टेम्परारी असाइनमेंट पर काम करने वाले एम्प्लॉई को डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से बचाया जा सके।

एग्रीमेंट के मुख्य नियम

- 36 महीने (3 साल) तक डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से छूट।
- एम्प्लॉई टेम्परारी पोस्टिंग के दौरान सिर्फ़ अपने देश के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे।
- छूट का दावा करने के लिए कम्पेटेंट अथॉरिटी (इंडिया में, EPFO) से सर्टिफिकेट ऑफ़ कवरेज (CoC) लेना होगा।
- यह एग्रीमेंट दोनों देशों के वर्कर के लिए रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है।
- यह बड़े इंडिया–UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA/FTA) फ्रेमवर्क के साथ लागू होगा।
- सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या हैं? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई द्वारा किए जाने वाले ज़रूरी पेमेंट हैं ताकि इन चीज़ों को फंड किया जा सके: पेंशन बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी और सर्वाइवर बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स
- भारत में, सोशल सिक्योरिटी मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) द्वारा मैनेज की जाती है।
- UK में, कंट्रीब्यूशन को नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन (NICs) के रूप में जाना जाता है।

एग्रीमेंट की ज़रूरत

पहले, UK में भारतीय प्रोफेशनल्स को EPF (इंडिया) और NIC (UK) दोनों में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। कई शॉर्ट-टर्म एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करने के बावजूद UK पेंशन बेनिफिट्स के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते थे। इससे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स पर फाइनेंशियल बोझ पड़ा और कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई।

भारत के लिए महत्व

खासकर IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को बढ़ाता है। विदेश में एम्प्लॉई भेजने वाली भारतीय कंपनियों के लिए कॉस्ट कम करता है। भारत-UK ट्रेड पार्टनरशिप के तहत बाइलेटरल इकोनॉमिक संबंधों को मज़बूत करता है। क्रॉस-बॉर्डर सर्विसेज़ में बिज़नेस करने में आसानी को बेहतर बनाता है।

और बातें

भारत ने जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साउथ कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSAs) साइन किए हैं।

SSAs में आम तौर पर दो खास बातें शामिल होती हैं:

- डबल कंट्रीब्यूशन से बचना
- बेनिफिट्स का टोटलाइज़ेशन (पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए दोनों देशों में कंट्रीब्यूशन पीरियड को मिलाना)
- EPFO को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स एक्ट, 1952 के तहत बनाया गया था।

ब्रिटिश PM कीर स्टारमर का चीन दौरा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तीन दिन की यात्रा के बाद चीन का अपना आधिकारिक दौरा पूरा किया। इस दौरे का मकसद ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधों को मज़बूत करना और पहले से तनावपूर्ण UK-चीन संबंधों में स्थिरता लाना था।

मुख्य ट्रेड और इन्वेस्टमेंट समझौते

इस दौरे के दौरान UK और चीन ने £2.2 बिलियन के एक्सपोर्ट डील पक्के किए। अगले पाँच सालों में मार्केट एक्सेस पैक्ट्स में लगभग £2.3 बिलियन के समझौते भी किए गए। इसके अलावा, नतीजों के हिस्से के तौर पर सैकड़ों मिलियन पाउंड के नए इन्वेस्टमेंट की भी पुष्टि की गई।

बढ़ी हुई मार्केट एक्सेस

इन डील्स से कई सेक्टर्स में UK की कंपनियों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ने की उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं:
सेवाएँ, कृषि, भोजन और रिटेल, खेल और जीवन विज्ञान

अन्य रिपोर्टों द्वारा बताए गए अतिरिक्त परिणाम

- चीन ने UK स्कॉच व्हिस्की के इंपोर्ट पर टैरिफ आधा करने पर सहमति जताई, जिससे UK इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है।
- ब्रिटिश नागरिकों के लिए चीन में 30 दिनों तक वीज़ा-फ्री यात्रा की व्यवस्था पर सहमति बनी, जिसका मकसद बिज़नेस और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
- खिलौना बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट सहित कई विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट और नए UK ऑपरेशन्स का वादा किया।

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 25-27 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें EU-भारत शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत का दौरा किया।

मुख्य परिणाम:

- भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA): इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। इसे "सभी सौदों की जननी" कहा गया है - जिससे भारत और EU के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जो लगभग 2 अरब लोगों के संयुक्त बाजार और वैश्विक GDP के एक बड़े हिस्से को कवर करेगा।
- रणनीतिक साझेदारी एजेंडा: दोनों पक्षों ने "2030 की ओर: एक संयुक्त भारत-यूरोपीय संघ व्यापक रणनीतिक एजेंडा" अपनाया - जो कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है।
- आर्थिक और वित्तीय सहयोग: वित्तीय नियामक सहयोग को गहरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) के बीच समझौता ज्ञापन। सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहरों पर प्रशासनिक व्यवस्था।
- सुरक्षा और रक्षा: एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी स्थापित की गई, और रक्षा, सुरक्षा और सूचना साझाकरण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-EU सूचना सुरक्षा समझौते पर बातचीत शुरू की गई।
- गतिशीलता और कौशल सहयोग: गतिशीलता (कौशल और गतिशीलता) पर सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचे पर सहमति हुई, साथ ही कानूनी गतिशीलता और कौशल आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत में यूरोपीय संघ के एक पायलट कानूनी गेटवे कार्यालय की योजनाओं पर भी सहमति हुई।
- आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया: आपदा जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सहयोग में सुधार के लिए भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और EU के यूरोपीय नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय (DG-ECHO) के बीच एक प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।
- संयुक्त परियोजनाएँ: डिजिटल इनोवेशन और स्किल्स, महिला किसानों के लिए सोलर समाधान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और अफ्रीका और छोटे द्वीप विकासशील देशों में सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांज़िशन पर संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट लागू करने पर समझौता।

नवाचार, विज्ञान और हरित ऊर्जा:

- वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-EU समझौते का नवीनीकरण (2025-2030)।
- हॉराइजन यूरोप कार्यक्रम (EU का अनुसंधान और नवाचार ढांचा) के साथ भारत के जुड़ाव के लिए प्रारंभिक बातचीत शुरू की गई।
- स्वच्छ ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

- मुख्य अतिथि के रूप में पहले EU नेता: इस यात्रा में पहली बार यूरोपीय संघ के नेता भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे — जो भारत-EU संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
- लंबी बातचीत के बाद सबसे बड़ा व्यापार सौदा: यात्रा के दौरान संपन्न हुआ भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता लगभग दो दशकों की बातचीत को समाप्त करता है, जिसका लक्ष्य भारत और EU के बीच वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर बाज़ार पहुंच को बढ़ावा देना और टैरिफ कम करना है।
- रणनीतिक आर्थिक भागीदार: 2024-25 में, भारत और EU के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $136 बिलियन था, जिससे EU भारत का सबसे बड़ा माल व्यापार भागीदार बन गया — जो इस साझेदारी के आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है।
- लोगों के बीच संबंध: 930,000 से अधिक भारतीय EU देशों में रहते हैं, और 6,000 से अधिक भारतीय छात्रों को इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति से लाभ हुआ है, जो मजबूत शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।

वेनेज़ुएला ने एमनेस्टी बिल को मंज़ूरी दी

वेनेज़ुएला की लेजिस्लेचर (संसद) ने एक एमनेस्टी बिल को मंज़ूरी दी जिससे पॉलिटिकल वजहों से जेल में बंद कई लोगों को रिहा किया जा सकता है। सांसदों से मंज़ूरी मिलने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने बिल पर साइन करके इसे कानून बना दिया। इस कदम को पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि सरकार कई सालों से पॉलिटिकल कैदियों को रखने से मना कर रही थी।

किसे रिहा किया जा सकता है?

किन ग्रुप्स को फ़ायदा हो सकता है

इस कानून से पॉलिटिकल वजहों से जेल में बंद सैकड़ों लोगों को रिहा किया जा सकता है।

इससे कई ग्रुप्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है जैसे:

- विपक्षी नेता
- एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर
- पत्रकार और वकील
- ये वे लोग हैं जिन्हें पिछले दो से तीन दशकों में सरकार का विरोध करने के लिए हिरासत में लिया गया है।

यह कानून क्या कवर करता है

यह 1999 से लेकर हाल के सालों तक की घटनाओं से जुड़े पॉलिटिकल अपराधों के लिए आम माफ़ी देता है। यह उन अपराधों पर लागू होता है जो विरोध प्रदर्शनों या पॉलिटिकल झगड़ों के दौरान हुए हों। यह कानून विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को वकीलों के ज़रिए एमनेस्टी के लिए अप्लाई करने की भी इजाज़त देता है, बिना तुरंत वेनेज़ुएला लौटे।

कौन कवर नहीं है

यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन्हें गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- मर्डर
- ड्रग्स की तस्करी
- करप्शन
- ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन
- वेनेज़ुएला के खिलाफ हथियारों से हमले या विदेशी दखल से जुड़े दूसरे मामले
- इन छूटों की वजह से, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं।

एमनेस्टी कानून क्या है?

मतलब: एमनेस्टी कानून सरकार द्वारा पास किया गया एक कानून है जो कुछ अपराधों को माफ कर देता है और खास लोगों या ग्रुप्स के लिए कानूनी सज़ा हटा देता है।

एमनेस्टी के पीछे बेसिक थ्योरी

एमनेस्टी का इस्तेमाल आमतौर पर:

- पॉलिटिकल टेंशन कम करने के लिए
- नेशनल यूनिटी या सुलह को बढ़ावा देने के लिए
- झगड़ों, विरोध प्रदर्शनों, सिविल वॉर या पॉलिटिकल संकटों के बाद
- सरकार बदलने के दौरान
- यह शांति बहाल करने का एक पॉलिटिकल और लीगल टूल है।

खास बातें

इसे सरकार या पार्लियामेंट देती है। यह आमतौर पर लोगों के ग्रुप पर लागू होता है, सिर्फ़ एक व्यक्ति पर नहीं। यह अक्सर पॉलिटिकल अपराधों को कवर करता है। हत्या, आतंकवाद, या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों को आमतौर पर बाहर रखा जाता है।

वेनेज़ुएला

- राजधानी: काराकस
- मुद्रा: वेनेज़ुएला बोलिवर
- महाद्वीप: दक्षिण अमेरिका
- राष्ट्रपति: डेल्सी रोड्रिगेज (कार्यवाहक)

UNSC मेंबरशिप की 'तीसरी कैटेगरी'

भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में मेंबरशिप की तीसरी कैटेगरी बनाने के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। प्रपोज़ल में लंबे समय तक चलने वाली और दोबारा चुने जाने की एलिजिबिलिटी वाली एक नई तरह की सीट का सुझाव दिया गया था। भारत ने इस आइडिया को UNSC में सही सुधारों में देरी करने की एक चाल बताया।

यह कहाँ हुआ?

यह रिजेक्शन यूनाइटेड नेशंस में UNSC सुधार पर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन (IGN) के दौरान किया गया था। भारत की तरफ से भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने बात की।

प्रपोज़ल क्यों रिजेक्ट किया गया?

भारत ने कहा कि तीसरी कैटेगरी एक "लालच" है जो दशकों तक सुधार की प्रोग्रेस को रोक देगी। उसने तर्क दिया कि यह आइडिया काउंसिल में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक नहीं करता है। भारत ने ज़ोर देकर कहा कि परमानेंट और नॉन-परमानेंट कैटेगरी को बढ़ाना UNSC में सुधार का सही तरीका है।

तीसरी कैटेगरी का प्रपोज़ल किसने दिया?

यह आइडिया मुख्य रूप से इटली के लीडर और पाकिस्तान समेत यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (UfC) ग्रुप से आया था। यह ग्रुप परमानेंट मेंबर कैटेगरी को बढ़ाने का विरोध करता है और इसके बजाय फिक्स्ड रीजनल सीट्स का सुझाव देता है।

रिफॉर्म-ओरिएंटेड ग्रुप्स क्या कहते हैं?

ग्रुप ऑफ़ 4 (G4) – जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील शामिल हैं – परमानेंट और नॉन-परमानेंट सीटों को बढ़ाने का सपोर्ट करता है। डेवलपिंग देशों के L.69 ग्रुप ने भी तीसरी कैटेगरी का विरोध किया, इसे अधूरा रिफॉर्म बताया।

नेतन्याहू का प्लान किया हुआ 'हेक्सागन' अलायंस क्या है?

'हेक्सागन ऑफ़ अलायंस' क्या है?

बेंजामिन नेतन्याहू ने "हेक्सागन ऑफ़ अलायंस" नाम का एक नया रीजनल फ्रेमवर्क प्रपोज़ किया है। इसका आइडिया छह देशों के ग्रुप को एक साथ लाना है, जो रीजनल सिक्योरिटी और चुनौतियों पर एक जैसे विचार रखते हैं। "हेक्सागन" शब्द का मतलब है छह साइड या पार्टनर का एक साथ काम करना।

कौन से देश शामिल हैं?

- नेतन्याहू ने इज़राइल, इंडिया, ग्रीस और साइप्रस जैसे कोर पार्टिसिपेंट्स का ज़िक्र किया।
- उन्होंने ग्रुप में शामिल होने वाले दूसरे बिना नाम वाले अरब, अफ़्रीकी और एशियाई देशों के बारे में भी बात की।
- हालांकि, अभी तक किसी भी सरकार ने ऑफिशियली इस प्लान पर सहमति नहीं जताई है।

इसे क्यों प्रपोज़ किया गया है?

नेतन्याहू का कहना है कि यह अलायंस "रेडिकल एक्सिस" का मुकाबला करने के लिए है – जिसे वह इज़राइल के हितों के खिलाफ़ ग्रुप या देश बताते हैं, जिसमें ईरान का असर भी शामिल है। वह इस पैक्ट को मेंबर देशों के बीच इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाने के तरीके के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि यह अलायंस इज़राइल के अमेरिका के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाएगा, उनकी जगह नहीं लेगा।

पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक संदर्भ

यह प्रपोज़ल मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन और झगड़ों के बीच आया है, जिसमें रीजनल दुश्मनों की तरफ़ से इज़राइल पर दबाव भी शामिल है। इसे पब्लिकली शेयर किया गया जब नरेंद्र मोदी इज़राइल जाने की तैयारी कर रहे थे, जिससे भारत और इज़राइल के बीच करीबी रिश्तों का संकेत मिला। क्रिटिक्स का कहना है कि यह आइडिया फॉर्मल से ज़्यादा सिंबॉलिक हो सकता है, और कुछ को लगता है कि यह एक बाइंडिंग अलायंस बनने की संभावना नहीं है।

क्या नया 'EXILE Act', H-1B वीज़ा को टारगेट करता है?

क्या हो रहा है

U.S. कांग्रेस में EXILE Act नाम का एक नया बिल पेश किया गया है, जिसका मकसद यूनाइटेड स्टेट्स में H-1B वीज़ा प्रोग्राम को खत्म करना है। यह बिल फ्लोरिडा के रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव ग्रेग स्ट्यूब ने पेश किया था।

EXILE Act का क्या प्रस्ताव है

EXILE Act का मतलब है Exploitative Imported Labor Exemptions Act को खत्म करना। यह U.S. Immigration and Nationality Act में बदलाव करके H-1B वीज़ा प्रोग्राम को लगभग 2027 तक खत्म करने की कोशिश करता है। इस बिल के तहत, प्रोग्राम खत्म होने के बाद नए H-1B वीज़ा आखिरकार बंद कर दिए जाएंगे।

बिल क्यों पेश किया गया

बिल को स्पॉन्सर करने वाले सांसद का तर्क है कि H-1B सिस्टम का कंपनियों द्वारा सस्ते विदेशी लेबर को हायर करने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे अमेरिकी वर्कर्स और जॉब के मौकों को नुकसान हुआ है। बिल के सपोर्टर्स का कहना है कि इसका मकसद U.S. नागरिकों को नौकरियों के लिए प्रायोरिटी देना और घरेलू रोज़गार को बचाना है।

H-1B वीज़ा प्रोग्राम के बारे में

H-1B वीज़ा U.S. एम्प्लॉयर्स को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर जैसे स्पेशलाइज़्ड रोल्स में विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करने की इजाज़त देता है। H-1B वीज़ा होल्डर्स की एक बड़ी संख्या भारत या चीन से है, हाल के सालों में मंज़ूर पिटीशन्स में से 70% से ज़्यादा भारतीय हैं।

मौजूदा पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट

EXILE एक्ट तब आया है जब U.S. पहले से ही इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को सख़्त कर रहा है, जिसमें सख़्त वीज़ा चेक और ज़्यादा फ़ीस शामिल हैं। इन बदलावों ने भारतीय प्रोफेशनल्स सहित विदेशी वर्कर्स के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है।

यह क्यों ज़रूरी है

अगर पास हो जाता है, तो EXILE एक्ट विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर भारत से, के लिए भविष्य में H-1B काम के मौकों को कम कर सकता है। यह बहस लोकल नौकरियों को बचाने और U.S. में स्किल्ड विदेशी लेबर की मांग को पूरा करने के बीच तनाव को दिखाती है।

आगे का रास्ता

- H-1B सिस्टम में बैलेंस्ड सुधार: U.S. गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों में सुधार कर सकता है, जबकि टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर जैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स को अभी भी इजाज़त दे सकता है।
- दोनों वर्कर्स को सुरक्षित रखें: पॉलिसीज़ को अमेरिकी नौकरियों को सुरक्षित रखना चाहिए और प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय ग्लोबल टैलेंट के लिए सही मौके भी पक्के करने चाहिए।
- स्किल-बेस्ड सिलेक्शन बढ़ाएँ: हाई-स्किल, हाई-सैलरी वाले एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता देने से सस्ते लेबर की चिंताएँ कम हो सकती हैं और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है।
- कंपनियों की मज़बूत मॉनिटरिंग: एम्प्लॉयर्स पर सही नज़र रखने से सैलरी में कटौती और विदेशी वर्कर्स का शोषण रुक सकता है।
- भारत-U.S. सहयोग: भारत और U.S. प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, स्किल पार्टनरशिप्स और दूसरे वीज़ा तरीकों पर मिलकर काम कर सकते हैं।
- घरेलू स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना: U.S. अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे विदेशी वीज़ा पर लंबे समय की निर्भरता कम हो जाएगी।

अन्य प्रमुख खबरें

भारत और केन्या ने केन्या में DigiLocker पायलट प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए

भारत और केन्या ने DigiLocker टेक्नोलॉजी पर एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए। यह एग्रीमेंट नैरोबी, केन्या में साइन किया गया। इस पर भारत से अश्विनी वैष्णव और केन्या से यूजीन वमालवा ने साइन किए।

DigiLocker क्या है?

DigiLocker भारत का सुरक्षित डिजिटल डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर और शेयर करने देता है। यह कागजी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कम करने में मदद करता है और वेरिफिकेशन को आसान और तेज़ बनाता है।
केन्या इस सिस्टम को पायलट करेगा ताकि यह टेस्ट किया जा सके कि यह लोकल लेवल पर कैसे काम करता है।

पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य

- DigiLocker सिस्टम का इस्तेमाल करके केन्या में ज़रूरी सर्टिफिकेट और ऑफिशियल रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना।
- लोगों के लिए डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करना आसान बनाना।
- फिजिकल डॉक्यूमेंट से जुड़ी एफिशिएंसी में सुधार करना और फ्रॉड को कम करना।

यह प्रोजेक्ट केन्या को कैसे फायदा पहुंचाता है

केन्या के नागरिकों और संस्थाओं को पर्सनल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के डिजिटल वर्जन स्टोर करने में मदद करता है। सरकारी एजेंसियों, यूनिवर्सिटी और एम्प्लॉयर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली वेरिफाई करना आसान बनाता है। एक पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देता है जिससे समय और खर्च बचता है।

केन्या

- कैपिटल: नैरोबी

- मुद्रा: केन्याई शिलिंग
- ऑफिशियल भाषाएँ: स्वाहिली, इंग्लिश
- राष्ट्रपति: विलियम रूटो

FCI–WFP MoU दुनिया भर में भूख से राहत के लिए चावल सप्लाई करेगा

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI) ने दुनिया भर में इंसानी भूख से राहत के कामों में मदद के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल सप्लाई करने के लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम (WFP) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किया है।

समय और शर्तें

MoU साइन करने की तारीख से पांच साल के लिए वैलिड है और आपसी सहमति से इसे बढ़ाया जा सकता है। सप्लाई किए जाने वाले चावल में 25% तक टूटा हुआ चावल हो सकता है, जो इंसानी मदद के लिए बांटने के लिए ठीक है। कीमत पर हर साल बातचीत की जाएगी; अभी, 31 मार्च 2026 तक कीमत ₹2,800 प्रति क्विंटल तय है।

ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए यह क्यों ज़रूरी है

- यह पार्टनरशिप SDG-2: ज़ीरो हंगर की दिशा में ग्लोबल कोशिशों को मज़बूत करती है, जिसका मकसद 2030 तक भूख खत्म करना, फूड सिक्योरिटी हासिल करना और बेहतर न्यूट्रिशन देना है।
- भारत का चावल सप्लाई में योगदान WFP को संघर्ष वाले इलाकों, आपदा से प्रभावित इलाकों और फूड की कमी वाले इलाकों में कमज़ोर आबादी तक पहुंचने में मदद करता है।
- भारत दुनिया में चावल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में से एक है, जो घरेलू और ग्लोबल फूड सिस्टम दोनों में अपनी भूमिका को बढ़ाता है।

भारत-WFP कोलेबोरेशन हिस्ट्री

भारत और WFP 1960 के दशक से साथ काम कर रहे हैं, फूड असिस्टेंस एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट से टेक्निकल और लॉजिस्टिक पार्टनरशिप में बदलाव किया है।

क्रिमिनल मामलों में भारत-नेपाल का अपडेटेड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट

भारत और नेपाल ने क्रिमिनल मामलों में एक अपडेटेड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं ताकि दोनों देशों के बीच जांच, सबूत शेयर करने और कानूनी कार्रवाई में सहयोग को मजबूत किया जा सके।

एग्रीमेंट का उद्देश्य

यह एग्रीमेंट एक फॉर्मल कानूनी फ्रेमवर्क बनाता है जो दोनों देशों को जानकारी शेयर करने, मुकदमा चलाने में मदद करने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, ऑर्गनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग जैसे क्रॉस-बॉर्डर क्राइम के खिलाफ मिलकर काम करने की इजाजत देता है।

यह एग्रीमेंट क्यों जरूरी है

यह अपडेटेड पैक्ट कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों के बीच सहयोग को तेज और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाएगा। यह दोनों देशों को शामिल करने वाली क्रिमिनल जांच के असर को बेहतर बनाएगा और कानून के पूरे राज और न्याय देने के सिस्टम को मजबूत करेगा।

ऐतिहासिक बैकग्राउंड

दोनों पड़ोसियों के बीच पहले के सहयोग के तरीके पुराने और सीमित दायरे के थे। नया एग्रीमेंट पुराने इनफॉर्मल अरेंजमेंट की जगह लेता है और आज की सुरक्षा और क्राइम चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी तालमेल को मॉडर्न बनाता है।

म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कॉन्सेप्ट

म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट देशों के बीच एक कानूनी व्यवस्था है जो उन्हें सबूत और जानकारी शेयर करने, आपराधिक जांच में मदद करने और यह पक्का करने की अनुमति देता है कि अपराधी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके न्याय से बच न सकें।

नेपाल

- राजधानी: काठमांडू
- राष्ट्रपति: राम चंद्र पौडेल
- प्रधानमंत्री: सुशीला कार्की
- करेंसी: नेपाली रुपया

भारत-फ्रांस ने डिफेंस, एनर्जी और ज़रूरी मिनरल्स में 21 एग्रीमेंट किए

नरेंद्र मोदी और इमैनुएल मैक्रों भारत-फ्रांस के आपसी रिश्तों को "स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" तक बढ़ाने पर सहमत हुए और मैक्रों के भारत दौरे के दौरान डिफेंस, एनर्जी, ज़रूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और दूसरे खास सेक्टर्स से जुड़े 21 एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स का आदान-प्रदान किया।

खास एग्रीमेंट और नतीजे

1. डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन

दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया और इंटरऑपरेबिलिटी और मिलिट्री लिंकेज को मज़बूत करने के लिए इंडियन आर्मी और फ्रेंच लैंड फोर्सेज़ के बीच अधिकारियों की आपसी तैनाती पर सहमति जताई। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए BEL और सफरान के बीच एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की गई, जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया गया, जिससे जॉइंट कोऑपरेशन के तहत भारत का एयरोस्पेस इंडस्ट्रियल बेस मज़बूत हुआ।

2. एनर्जी और ज़रूरी मिनरल्स में सहयोग

भारत और फ्रांस ने ज़रूरी मिनरल्स में सहयोग पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ़ इंटेंट पर साइन किए, जिसका मकसद डिफ़ेंस, ग्रीन इकॉनमी और टेक सेक्टर के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ्स और ज़रूरी मिनरल्स की खोज, निकालने, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग पर मिलकर काम करना है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और CNRS के बीच एडवांस्ड मटीरियल्स पर एक सेंटर बनाने के लिए एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर सहमति बनी।

3. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप्स

साइंस, स्टार्टअप्स, रिसर्च, डिजिटल साइंस और हेल्थ में AI में सहयोग को गहरा करने के लिए इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ़ इनोवेशन 2026 और इंडिया-फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च किए गए। हेल्थकेयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर बनाने, जॉइंट R&D और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए।

4. दूसरे स्ट्रेटेजिक सहयोग

नई बढ़ी हुई पार्टनरशिप को लागू करने का रेगुलर रिव्यू करने और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को गाइड करने के लिए एक सालाना फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग शुरू किया गया। दोहरे इन्वेस्टमेंट और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) पर प्रोटोकॉल में बदलाव किया जाएगा। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम कोऑपरेशन, एरोनॉटिक्स में स्किलिंग, हेल्थ रिसर्च सेंटर और एडवांस्ड मटीरियल टेक्नोलॉजी के लिए MoU साइन किए गए।

भारत के स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों के लिए महत्व

डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करना

फ्रांस – एक मुख्य यूरोपियन पार्टनर – के साथ बेहतर डिफेंस संबंध भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया पहल को सपोर्ट करते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने में मदद मिलती है। BEL–सफ्रान जॉइंट वेंचर और भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सहयोग विदेशी निर्भरता को कम करने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

ज़रूरी मिनरल्स और एनर्जी सिक्योरिटी

लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ्स जैसे ज़रूरी मिनरल्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकल जोखिमों के कारण दबाव में हैं, ऐसे में फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सहयोग अलग-अलग तरह की, लचीली सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को सपोर्ट करता है। ज़रूरी मिनरल्स रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उभरती टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं – जिससे ऐसे सहयोग भारत की भविष्य की एनर्जी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के लिए सेंट्रल बन जाते हैं।

ग्लोबल टेक और इनोवेशन लीडरशिप

इंडो-फ्रेंच AI और डिजिटल साइंस सेंटर जैसी पहलें डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विसेज़ में AI इंटीग्रेशन और ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी के तहत भारत के लक्ष्यों से मेल खाती हैं। यह पार्टनरशिप नॉलेज एक्सचेंज, रिसर्च और हाई-स्किल जॉब क्रिएशन को बढ़ाती है।

फ्रांस

- राजधानी: पेरिस
- मुद्रा: यूरो
- राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों
- ऑफिशियल भाषा: फ्रेंच

भारत और ग्रीस ने एजेंडा 2030 के तहत पार्टनरशिप के ज़रिए अपनी-अपनी देसी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने का फ़ैसला किया

भारत और ग्रीस अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर राज़ी हुए हैं। इसका मतलब है कि वे एक-दूसरे की मदद करते हुए अपने-अपने देशों में ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं।

दो बड़े प्लान के बीच पार्टनरशिप

भारत के पास "आत्मनिर्भर भारत" नाम का एक प्लान है (जिसका मतलब है डिफेंस में आत्मनिर्भर होना)। ग्रीस के पास "एजेंडा 2030" नाम का एक डिफेंस रिफॉर्म प्लान है। दोनों देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक साथ बढ़ाने में मदद करने के लिए इन प्लान को एक साथ लाएंगे।

एग्रीमेंट पर साइन हुए

- जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ़ इंटेंट: भारत और ग्रीस के नेताओं ने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए। यह एग्रीमेंट जॉइंट डिफेंस काम के लिए पांच साल का प्लान बनाने की दिशा में पहला कदम है।
- मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान: दोनों पक्षों ने साल 2026 के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए एक प्लान शेयर किया। यह प्लान बताता है कि उनकी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स एक साथ कैसे काम करेंगी।

शांति और सुरक्षा पर फोकस

- क्षेत्रीय शांति पर बातचीत: रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने स्थिरता और सुरक्षा जैसे साझा लक्ष्यों पर ज़ोर दिया।
- समुद्री सहयोग: ग्रीस गुरुग्राम में भारत के इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) में एक इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर नियुक्त करेगा। इससे दोनों देशों को समुद्र और सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी शेयर करने में मदद मिलेगी।

यह क्यों ज़रूरी है

यह कदम दिखाता है कि भारत और ग्रीस रक्षा और सुरक्षा में पार्टनर के तौर पर करीब आ रहे हैं। साथ मिलकर काम करके, दोनों देश अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा नौकरियां पैदा कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को मज़बूत कर सकते हैं।

ग्रीस

- राजधानी: एथेंस
- राष्ट्रपति: कॉन्स्टेंटिनोस तसौलास
- प्रधानमंत्री: किरियाकोस मित्सोटाकिस
- करेंसी: यूरो (€)

हेल्थ, सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग बढ़ाने के लिए इंडिया-सेशेल्स एग्रीमेंट साइन हुए

सेशेल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिनी के नई दिल्ली के स्टेट विज़िट के दौरान इंडिया और सेशेल्स ने कई एग्रीमेंट और MoU साइन किए। लीडर्स ने भविष्य के सहयोग को गाइड करने के लिए सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी (SESEL) के लिए एक जॉइंट विज़न भी अपनाया।

स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज

इंडिया ने सेशेल्स के डेवलपमेंट में मदद के लिए $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई-मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में मदद करेगा।

सहयोग के मुख्य एरिया

- हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज़: हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट और सहयोग के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए।
- डिजिटल और टेक्नोलॉजी: MoU में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्निकल सहयोग शामिल हैं।
- 3. मैरीटाइम और सिक्योरिटी: सहयोग एग्रीमेंट में मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओशन साइंस और हाइड्रोग्राफी शामिल हैं। इंडिया एक सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र पक्का करने के लिए मैरीटाइम सर्विलांस और सिक्योरिटी में मदद करेगा। 4. ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग: भारत सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने और स्किल्स बनाने में मदद करेगा।
- 5. मौसम विज्ञान और रिसर्च: एग्रीमेंट्स में मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट्स के बीच साइंटिफिक कोलेबोरेशन शामिल हैं।

यह क्यों ज़रूरी है

ये एग्रीमेंट्स भारत और सेशेल्स के बीच एक मज़बूत और बढ़ती पार्टनरशिप दिखाते हैं। इस कोलेबोरेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और जॉब्स शामिल हैं। यह इंडियन ओशन में डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी में शेयर्ड प्रायोरिटीज़ को दिखाता है।

सेशेल्स

- कैपिटल: विक्टोरिया
- करेंसी: सेशेल्स रुपया

- प्रेसिडेंट: पैट्रिक हर्मिनी
- वाइस-प्रेसिडेंट: सेबेस्टियन पिल्ले

भारत-मलेशिया ने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए; UPI-PayNet लिंक से रेमिटेंस आसान होगा

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी की, और कई सहयोग समझौतों के माध्यम से मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।

मुख्य द्विपक्षीय समझौते

व्यापार, रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए कुल 11 MoU और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) – PayNet लिंकेज:

सीमा पार डिजिटल भुगतान और रेमिटेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को मलेशिया के PayNet सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटकों, श्रमिकों और व्यवसायों को दोनों देशों के बीच आसान, कम लागत वाले लेनदेन करने में मदद मिलेगी।

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान:

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक नेगारा मलेशिया भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट का उपयोग करके व्यापार निपटान पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिससे USD पर निर्भरता कम होगी।

कोटा किनाबालु में पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास: मलेशिया ने सबा राज्य में पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमति व्यक्त की।

रणनीतिक प्राथमिकताएं और सहयोग क्षेत्र

शामिल प्राथमिकता वाले क्षेत्र: व्यापार, बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, समुद्री सुरक्षा और उभरती तकनीक (AI, सेमीकंडक्टर)।

- सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथ, आतंकी वित्तपोषण और समुद्री सुरक्षा पर बढ़ा हुआ सहयोग। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की पुष्टि की।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध: संगठित अपराध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी और ज्ञान साझा करने के समझौते।

UPI और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान

- UPI: NPCI द्वारा प्रबंधित भारत का रियल-टाइम भुगतान प्रणाली घरेलू स्तर पर अरबों लेनदेन संसाधित करता है; मलेशिया जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव भारत के डिजिटल वित्त पदचिह्न के विस्तार का प्रतीक है।
- प्रोजेक्ट नेक्सस: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के तहत एक बहु-देशीय पहल जो ASEAN और उससे आगे डिजिटल भुगतान प्रणालियों को जोड़ती है - जिसमें भारत, मलेशिया, सिंगापुर, आदि भाग ले रहे हैं।

भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंध: अवलोकन

- ऐतिहासिक संबंध: 1957 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए; 2024 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत।
- व्यापार की मात्रा: भारत-मलेशिया व्यापार लगभग US$19 बिलियन (2025) था, जिसे और बढ़ाने की आकांक्षा है।
- स्थानीय मुद्रा में व्यापार: दोनों देश वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने और विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने के लिए INR और MYR में निपटान पर जोर देते हैं।
- मुख्य निर्यात/आयात: मलेशिया ताड़ का तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है; भारत मशीनरी, रसायन और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है।

भारत-भूटान बिजली सेक्टर में संबंधों को और मज़बूत करेंगे

भारत और भूटान ने नई दिल्ली में भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, ल्योनपो जेम शेरिंग और भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री, मनोहर लाल के बीच हुई बैठक में बिजली सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

- यह क्यों महत्वपूर्ण है: दोनों देशों ने पुनात्सांगछू-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1020 MW) से कमर्शियल आउटपुट को ऑप्टिमाइज़ करने और पुनात्सांगछू-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1200 MW) के कमीशनिंग में तेज़ी लाने पर चर्चा की, जो उनके हाइड्रोपावर सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने 2040 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की भी समीक्षा की।

- लंबे समय से चली आ रही बिजली साझेदारी: भारत-भूटान हाइड्रोपावर सहयोग 1960 के दशक से चला आ रहा है, जिसमें 2006 में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसने बिजली उत्पादन में संयुक्त प्रयासों को औपचारिक रूप दिया।

पूरे हुए प्रमुख हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट:

- भारत-भूटान सहयोग के माध्यम से, कई प्रमुख प्रोजेक्ट विकसित किए गए हैं, जिससे भूटान की ऊर्जा क्षमता और निर्यात क्षमता बढ़ी है:
  1. चुखा HEP (336 MW)
  2. कुरिछू HEP (60 MW)
  3. ताला HEP (1020 MW)
  4. मांगदेछू HEP (720 MW)
- ये प्रोजेक्ट मिलकर 2,100 MW से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं और इन्होंने भूटान की स्थापित क्षमता को काफी बढ़ाने में मदद की है।

पुनात्सांगछू-II HEP और ऊर्जा निर्यात:

- चल रहा पुनात्सांगछू-II प्रोजेक्ट (1020 MW) सहयोग की एक आधारशिला है; एक बार जब सभी यूनिट चालू हो जाएंगी, तो भूटान की कुल स्थापित बिजली क्षमता बढ़कर लगभग 3,465 MW हो सकती है, जिससे निर्यात बढ़ेगा, खासकर भारत को।
- आर्थिक और रणनीतिक लाभ: हाइड्रोपावर भूटान का सबसे बड़ा निर्यात आइटम है, जो उसके GDP और राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि भारत को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा आयात और बेहतर ऊर्जा सुरक्षा से लाभ होता है।
- नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान: हाइड्रोपावर के अलावा, दोनों देशों ने सौर, पवन, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर सहयोग में रुचि व्यक्त की है, जो एक विविध ऊर्जा साझेदारी को दर्शाता है।
- वित्तीय सहायता: भारत ने भूटान के विकास के लिए काफी वित्तीय सहायता दी है, जिसमें हाइड्रोपावर और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,000 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) शामिल है, जो एनर्जी सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करता है।

भूटान

- राजधानी: थिम्पू
- मुद्राएँ: भूटानी नगुल्ट्रम
- आधिकारिक भाषा: ज़ोंगखा
- राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
- प्रधान मंत्री: शेरिंग टोबगे

सिक्योरिटी रिस्क की वजह से भारत ने रूस के सपोर्ट वाले माली लिथियम प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया

भारत ने माली में लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से हटने का फैसला किया है, जिसे रूस की रोसाटॉम का सपोर्ट था। यह फैसला माली में गंभीर सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से लिया गया।

भारत ने हाथ क्यों खींचा

माली में राजनीतिक रूप से अस्थिर माहौल है, खासकर अल कायदा से जुड़े ग्रुप्स के बढ़ते मिलिटेंट हमलों की वजह से, यह विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए असुरक्षित हो गया है। पश्चिमी देशों ने भी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से अपने नागरिकों को माली छोड़ने की चेतावनी दी है। भारत खतरनाक स्थिति में अपना इन्वेस्टमेंट खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता था।

कौन शामिल था

माली में इस प्रोजेक्ट को रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम का सपोर्ट था। भारत की सरकारी कंपनियां खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) और NLC इंडिया लिमिटेड इस प्लान का हिस्सा थीं।

भारत के लिए लिथियम का महत्व

लिथियम एक ज़रूरी मिनरल है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजी की बैटरी में होता है। भारत लिथियम सप्लाई पक्का करने पर फोकस कर रहा है क्योंकि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है और कार्बन एमिशन कम करने का लक्ष्य बना रहा है।

अब भारत क्या करेगा

माली के बजाय, भारत अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे ज़्यादा स्थिर देशों में लिथियम डील ढूंढ रहा है। 2024 में, KABIL ने अर्जेंटीना की एक सरकारी कंपनी के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट साइन किया, जो ज़रूरी मिनरल्स को सुरक्षित करने की भारत की कोशिश को दिखाता है।

सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट बैलेंस

भारत का यह कदम दिखाता है कि वह जोखिम भरे विदेशी मिनरल प्रोजेक्ट्स के बजाय फंड्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन को प्राथमिकता दे रहा है।

कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुआ

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और उनके कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच ओटावा में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा वार्ता के दौरान, भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक साझा कार्य योजना पर सहमत हुए।

मुख्य बातें

- सुरक्षा सहयोग पर साझा कार्य योजना: भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पर सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए एक साझा कार्य योजना बनाने पर सहमत हुए, जिससे आपसी प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक सहयोग संभव होगा।
- संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति: दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्र में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे ताकि संचार को सुव्यवस्थित किया जा सके और नशीली दवाओं की तस्करी, संगठित अपराध और साइबर खतरों जैसे खतरों पर समय पर जानकारी साझा करने में सुधार किया जा सके।
- साइबर सुरक्षा सहयोग पर ध्यान: दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा नीति पर सहयोग को औपचारिक रूप देने और घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप साइबर खतरों पर सूचना आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र: चर्चाओं में धोखाधड़ी की रोकथाम और आव्रजन प्रवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग भी शामिल था, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रयास दोनों देशों में कानूनी ढांचे के अनुरूप हों।
- नियमित सुरक्षा वार्ता: यह समझौता एक नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का हिस्सा था, जो पिछले राजनयिक तनावों के बाद संस्थागत सुरक्षा संबंधों को फिर से बनाने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।

भारत-कनाडा संबंधों की पृष्ठभूमि

2023 में कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर राजनयिक तनाव के बाद भारत-कनाडा संबंधों में तनाव आया, जिसे भारत ने नकार दिया था; तब से दोनों पक्षों ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं। पूर्ण राजनयिक जुड़ाव बहाल करने में दोनों राजधानियों में उच्चायुक्तों की वापसी और उच्च-स्तरीय वार्ताओं को फिर से शुरू करना शामिल था।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ

- फेंटानिल और इसके अग्रदूत: कनाडा फेंटानिल से संबंधित ओवरडोज के कारण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है; भारत के साथ सहयोग सीमाओं के पार अवैध नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने में मदद करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध: संपर्क तंत्र विभिन्न क्षेत्राधिकारों में संचालित आपराधिक नेटवर्क के लिए संयुक्त प्रतिक्रियाओं में सुधार करते हैं।

साइबर सुरक्षा ढाँचे

भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013) का लक्ष्य महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण को सुविधाजनक बनाना है। भारत में राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) साइबर खतरों के लिए वास्तविक समय की प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है; कनाडा के साथ सहयोग साझा खतरे की खुफिया जानकारी का समर्थन कर सकता है। कनाडा साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है जो साइबर अपराध जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

सुरक्षा सहयोग तंत्र

लियाज़ों अधिकारी राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में काम करते हैं, जिससे ज़रूरी खतरों पर सीधे संचार और समन्वय में आसानी होती है। साइबर सुरक्षा सहयोग में सबसे अच्छे तरीकों, खतरे के डेटा और साइबर घटनाओं पर समन्वित प्रतिक्रियाओं को साझा करना शामिल है।

रैंकिंग एवं इंडेक्स

करप्शन इंडेक्स में बांग्लादेश दुनिया में 13वें सबसे निचले पायदान पर

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI)-2025 में बांग्लादेश दुनिया में 13वें सबसे निचले पायदान पर है। यह इंडेक्स यह मापता है कि किसी देश का पब्लिक सेक्टर कितना भ्रष्ट माना जाता है। CPI में कम रैंक का मतलब है कि दूसरे देशों की तुलना में वहां ज़्यादा करप्शन माना जाता है। ये नतीजे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक ग्लोबल एंटी-करप्शन ऑर्गनाइज़ेशन है, ने जारी किए हैं।

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। यह देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि एक्सपर्ट्स और बिज़नेस करने वाले उनके पब्लिक सेक्टर को कितना भ्रष्ट मानते हैं। इंडेक्स एक स्कोर (0 से 100 तक) का इस्तेमाल करता है — जिसमें 0 का मतलब है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट और 100 का मतलब है बहुत साफ़।

बांग्लादेश कहाँ है

लेटेस्ट 2025 इंडेक्स में, सर्वे किए गए देशों में बांग्लादेश 13वें सबसे निचले पायदान पर था। इससे पता चलता है कि बहुत से लोग मानते हैं कि इसके पब्लिक इंस्टीट्यूशन में करप्शन बहुत ज़्यादा है और करप्शन की सोच तुलना में ज़्यादा है।

टॉप 5 सबसे कम करप्ट देश

- डेनमार्क – सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और मज़बूत पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ पहले नंबर पर है।
- फ़िनलैंड – साफ़-सुथरे गवर्नेंस और मज़बूत कानून के राज के लिए जाना जाता है।
- न्यूज़ीलैंड – ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक पावर का कम गलत इस्तेमाल।
- नॉर्वे – ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और असरदार एंटी-करप्शन सिस्टम। सिंगापुर – सख्त कानून और अच्छा शासन भ्रष्टाचार को कम करता है।

सबसे नीचे के 5 सबसे भ्रष्ट देश

- साउथ सूडान – संघर्ष, कमजोर संस्थानों और खराब शासन के कारण सबसे नीचे रैंक पर है।
- सोमालिया – लंबे समय से अस्थिरता और नाजुक सरकारी ढांचे।
- वेनेजुएला – राजनीतिक संकट और कमजोर जवाबदेही के तरीके।
- सीरिया – लगातार संघर्ष और संस्थानों का टूटना।
- यमन – युद्ध और शासन के गिरने से भ्रष्टाचार की धारणा बढ़ रही है।

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक:

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2025 में भारत 182 देशों और क्षेत्रों में 91वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 100 में से 39 है, जो इसकी पिछली स्थिति से थोड़ा सुधार दिखाता है।

भारत ने अपनी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार किया लेकिन दो देशों में वीज़ा-फ़्री एक्सेस खो दिया

भारत 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 10 पायदान ऊपर चढ़कर 2025 के 85वें स्थान से 75वें स्थान पर आ गया है, जो दूसरे देशों के मुकाबले ग्लोबल मोबिलिटी में सुधार दिखाता है। हालांकि, इस बढ़ोतरी के बावजूद, भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के पास अब 56 देशों में वीज़ा-फ़्री एक्सेस है, जो पहले से एक कम है और 2025 की तुलना में दो देशों में वीज़ा-फ़्री एंट्री का नुकसान दिखाता है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में

हेनले एंड पार्टनर्स का पब्लिश किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ट्रैवल फ़्रीडम के आधार पर 227 डेस्टिनेशन के मुकाबले 199 पासपोर्ट को रैंक करता है। यह उन डेस्टिनेशन को गिनकर पासपोर्ट को एक "स्कोर" देता है जो वीज़ा-फ़्री एंट्री, वीज़ा-ऑन-अराइवल, बॉर्डर पर विज़िटर परमिट, या बिना पहले एम्बेसी अप्रूवल के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन की इजाज़त देते हैं। फिर पासपोर्ट को कुल स्कोर के आधार पर ग्लोबली रैंक किया जाता है।

भारत ने वीज़ा-फ़्री एक्सेस क्यों खो दिया

भारत ने ईरान और बोलीविया में वीज़ा-फ़्री एक्सेस खो दिया:

ईरान ने नवंबर 2025 में आम भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अपनी वीज़ा-फ़्री एंट्री सस्पेंड कर दी थी, ऐसा कथित तौर पर भारतीय यात्रियों को टारगेट करने वाले फ्रॉड और ट्रैफिकिंग के मामलों के बाद हुआ था। इसका मतलब था कि भारतीयों को जाने से पहले वीज़ा लेना पड़ता था। बोलीविया ने अपनी पॉलिसी वीज़ा-ऑन-अराइवल से बदलकर ई-वीज़ा सिस्टम कर दिया, जिसमें भारतीयों को यात्रा से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना और अप्रूवल लेना ज़रूरी था, जो इसे इंडेक्स मेथड के तहत वीज़ा-फ़्री माने जाने से डिसक्वालिफ़ाई करता है। इन नुकसानों के बावजूद, फरवरी 2026 तक गाम्बिया को भारत की वीज़ा-फ़्री लिस्ट में वापस जोड़ दिया गया, जिससे कुल एक्सेसिबल डेस्टिनेशन 56 हो गए।

भारत की ट्रैवल फ़्रीडम पर एक नज़र

- 2026 रैंकिंग: 75वां स्थान
- वीज़ा-फ़्री डेस्टिनेशन: 56
- 2025 रैंकिंग: 85वां स्थान

- 2025 में वीज़ा-फ़्री एक्सेस: 57 डेस्टिनेशन
- सबसे ऊंची हिस्टॉरिकल रैंक: 71वां (2006 में)

ये बदलाव दिखाते हैं कि ग्लोबल मोबिलिटी रिलेटिव है—वीज़ा-फ़्री देशों की संख्या कम होने पर भी पासपोर्ट रैंक में ऊपर जा सकता है, क्योंकि दूसरे देश उसी समय में ज़्यादा एक्सेस खो सकते हैं।

पासपोर्ट की मज़बूती का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट

दुनिया भर में सबसे पावरफ़ुल पासपोर्ट — जैसे सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया — 180 से ज़्यादा डेस्टिनेशन तक वीज़ा-फ़्री या वीज़ा-ऑन-अराइवल एक्सेस देते हैं, जो बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रैवल फ़्रीडम को दिखाता है। पाकिस्तान (लगभग 100+) या बांग्लादेश (95वां) जैसे साउथ एशियाई पड़ोसियों में भारत की रैंक कुछ दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा ठीक-ठाक ट्रैवल फ़्रीडम दिखाती है।

इंडेक्स ऑफ़ इकोनॉमिक फ़्रीडम 2025 में पाकिस्तान 150वें स्थान पर

हेरिटेज इंस्टीट्यूट के पब्लिश किए गए 2025 इंडेक्स ऑफ़ इकोनॉमिक फ़्रीडम में पाकिस्तान को 184 इकॉनमी में से 150वें स्थान पर रखा गया है, जिसका कुल स्कोर 100 में से 49.1 है। देश की इकॉनमी को इंडेक्स में "दबा हुआ" बताया गया है, जो सीमित इकोनॉमिक फ़्रीडम और स्ट्रक्चरल चुनौतियों को दिखाता है।

इंडेक्स ऑफ़ इकोनॉमिक फ़्रीडम के बारे में

इंडेक्स ऑफ़ इकोनॉमिक फ़्रीडम हर साल हेरिटेज इंस्टीट्यूट (हेरिटेज फ़ाउंडेशन), जो एक US थिंक टैंक है, दुनिया भर के देशों में इकोनॉमिक फ़्रीडम की सीमा को मापता है। यह रूल ऑफ़ लॉ, गवर्नमेंट साइज़, रेगुलेटरी एफ़िशिएंसी और ओपन मार्केट जैसे मुख्य पिलर के तहत ग्रुप किए गए 12 कंपोनेंट का मूल्यांकन करता है। देशों को उनके 100 में से स्कोर के आधार पर पाँच कैटेगरी में बांटा गया है: फ़्री, ज़्यादातर फ़्री, थोड़ा फ़्री, ज़्यादातर अनफ़्री, और दबे हुए।

हेरिटेज फाउंडेशन के पब्लिश किए गए 2025 के इकोनॉमिक फ़्रीडम इंडेक्स में टॉप 5 देश:

- सिंगापुर — दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ़्रीडम स्कोर के साथ पहले नंबर पर।
- स्विट्ज़रलैंड — मज़बूत इंस्टीट्यूशनल और मार्केट फ़्रीडम के साथ दूसरे नंबर पर।
- आयरलैंड — प्रो-बिज़नेस और ओपन मार्केट पॉलिसी से फ़ायदा उठाते हुए तीसरे नंबर पर।
- ताइवान — रेगुलेटरी एफिशिएंसी और ट्रेड फ़्रीडम में हाई स्कोर के लिए जाने जाने वाले चौथे नंबर पर।
- लक्समबर्ग — मज़बूत इकोनॉमिक फ़्रीडम इंडिकेटर के साथ पाँचवें नंबर पर।

इकोनॉमिक फ़्रीडम के हिस्से:

12 इंडिकेटर्स में प्रॉपर्टी राइट्स, सरकार की ईमानदारी, ज्यूडिशियल इफेक्टिवनेस, टैक्स का बोझ, सरकारी खर्च, फिस्कल हेल्थ, बिज़नेस फ़्रीडम, लेबर फ़्रीडम, मॉनेटरी फ़्रीडम, ट्रेड फ़्रीडम, इन्वेस्टमेंट फ़्रीडम और फाइनेंशियल फ़्रीडम शामिल हैं। ज़्यादा स्कोर ज़्यादा फ़्रीडम और ज़्यादा मार्केट-ओरिएंटेड इकोनॉमी दिखाते हैं।

इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन:

- फ़्री: मज़बूत प्रोटेक्शन और ओपन मार्केट के साथ सबसे अच्छा इकोनॉमिक माहौल।
- ज़्यादातर फ़्री: कुछ रुकावटों के साथ ज़्यादा इकोनॉमिक फ़्रीडम।
- थोड़ा फ़्री: खास पाबंदियों वाला बैलेंस्ड माहौल।
- ज़्यादातर अनफ़्री: बड़ी, हर जगह सरकारी दखल।
- दबा हुआ: लिमिटेड इकोनॉमिक लिबर्टी — पाकिस्तान इसी कैटेगरी में आता है।

भारत की रैंकिंग से तुलना:

2025 के इंडेक्स में, भारत 53 के करीब स्कोर के साथ लगभग 128वें स्थान पर है, जो "ज़्यादातर अनफ़्री" कैटेगरी में आता है, जो पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर इकोनॉमिक फ़्रीडम दिखाता है।

साउथ एशिया में साक्षरता के मामले में पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पर: FAFEN रिपोर्ट

रिपोर्ट क्या कहती है

साउथ एशिया में पाकिस्तान में साक्षरता दर सबसे कम है, जहाँ 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सिर्फ़ 63% लोग पढ़ और लिख सकते हैं। यह रैंकिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क (FAFEN) द्वारा आधिकारिक सर्वे डेटा का इस्तेमाल करके की गई समीक्षा पर आधारित है। समीक्षा में डेटा का इस्तेमाल किया गया और वर्ल्ड बैंक के साक्षरता आँकड़ों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तुलना साउथ एशिया के दूसरे देशों से की गई। साक्षरता में 2018-19 में 60% से 2024-25 में 63% तक मामूली सुधार हुआ, जो धीमी प्रगति दिखाता है।

लिंग भेद

- पाकिस्तान में पुरुषों की साक्षरता दर 73% है।
- महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, जो काफी कम है, यह एक बड़े लिंग अंतर को दिखाता है।

संक्षेप में

- हाल ही में FAFEN की एक समीक्षा से पता चलता है कि 10 में से सिर्फ़ 6 पाकिस्तानी (10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के) पढ़ और लिख सकते हैं।
- समय के साथ कुछ सुधार के बावजूद, साक्षरता के मामले में पाकिस्तान साउथ एशिया के देशों में सबसे नीचे है।
- महिलाओं और कुछ खास प्रांतों (जैसे बलूचिस्तान) में पुरुषों और दूसरे क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर बहुत कम है।
- ये निष्कर्ष शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता और सामर्थ्य में समस्याओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए हल किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट का नाम: फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क (FAFEN)

साउथ एशिया में साक्षरता के मामले में शीर्ष देश (उच्चतम दर):

1. मालदीव – ~98% साक्षरता (साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा)
2. श्रीलंका – ~93% साक्षरता
3. भारत – ~87% साक्षरता
4. बांग्लादेश – ~79% साक्षरता
5. नेपाल – ~68% साक्षरता
6. भूटान – ~65% साक्षरता (पाकिस्तान से ज़्यादा लेकिन निचले समूह में)
7. पाकिस्तान – ~63% (साउथ एशिया में सबसे कम)

UN रिपोर्ट: लैंडमाइन और विस्फोटक अवशेषों से होने वाली मौतों के मामले में अफगानिस्तान दुनिया में तीसरे स्थान पर

संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) का कहना है कि पिछले युद्धों से बचे लैंडमाइन और बिना फटे बमों से घायल या मारे गए लोगों के मामले में अफगानिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। ये ऐसे बम और विस्फोटक डिवाइस हैं जो पहली बार इस्तेमाल किए जाने पर फटे नहीं थे, लेकिन आज भी आम नागरिकों के लिए खतरनाक हैं।

सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है

बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो सभी पीड़ितों का लगभग 80 प्रतिशत हैं। कई बच्चे खेलते समय या अनजाने में विस्फोटक डिवाइस को छूने से घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। यह दिखाता है कि ये अवशेष कितने खतरनाक हैं, खासकर युवाओं के लिए जो इन्हें खिलौना समझ सकते हैं।

अफगानिस्तान में यह समस्या क्यों है

दशकों के संघर्ष - 1980 के दशक में सोवियत युद्ध से लेकर हाल के गृह युद्ध और विद्रोह तक - ने बड़े इलाकों को लैंडमाइन और बिना फटे बमों से दूषित कर दिया है। लगभग 3.3 मिलियन लोग दूषित इलाकों के पास रहते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें लगातार विस्फोटक खतरों का सामना करने का जोखिम रहता है।

खतरे को कम करने के प्रयास

- UNAMA का कहना है कि बारूदी सुरंग हटाने वाली टीमें हर दिन ज़मीन से विस्फोटक हटाने का काम करती हैं।
- लोगों को संदिग्ध चीज़ों को न छूने और अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं।
- हालांकि, ज़्यादा वित्तीय सहायता की ज़रूरत है ताकि संगठन ज़्यादा ज़मीन साफ कर सकें और आगे होने वाली मौतों को रोक सकें।
- लैंडमाइन मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार, लैंडमाइन और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से सबसे ज़्यादा मौतों वाले शीर्ष 5 देश:

1. म्यांमार – सबसे ज़्यादा मौतें (1,000 से ज़्यादा)
2. सीरिया – दूसरे नंबर पर (933 मौतें)
3. अफगानिस्तान – तीसरे नंबर पर (651 मौतें)
4. यूक्रेन – चौथे नंबर पर (580 मौतें)
5. यमन – पांचवें नंबर पर (499 मौतें)

ये रिपोर्ट क्यों प्रकाशित की जाती हैं

- लैंडमाइन की मानवीय कीमत को उजागर करने के लिए
- सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए
- बारूदी सुरंग हटाने और सफाई के प्रयासों का समर्थन करने के लिए
- अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और सहायता जुटाने के लिए
- नागरिकों की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए

- वैश्विक समझौतों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए
- नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए

भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 2019 के 66वें स्थान से 38वें स्थान पर पहुंच गया है

भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 में 38वां स्थान हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो 2019 के 66वें स्थान से काफी बेहतर है। यह पिछले कुछ सालों में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भारत की लगातार प्रगति को दिखाता है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (WIPO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह देशों को उनकी इनोवेशन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है, जिसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 2025 के इंडेक्स में दुनिया भर की लगभग 139 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

भारत के सुधार के पीछे के कारण

- इनोवेशन-आधारित विकास पर सरकार का मजबूत फोकस।
- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम जैसी पहलों के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को समर्थन।
- स्टार्टअप, रिसर्च और उभरती टेक्नोलॉजी में बढ़ा हुआ निवेश।
- प्रमुख शहरों में इनोवेशन हब का विकास।

मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शन

- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में भारत की वैश्विक स्थिति:
- ट्रेडमार्क में चौथा
- पेटेंट में छठा
- इंडस्ट्रियल डिजाइन में सातवां
- यह नए विचारों को बनाने और उनकी रक्षा करने की भारत की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष 10 देश

1. स्विट्जरलैंड
2. स्वीडन
3. संयुक्त राज्य अमेरिका
4. दक्षिण कोरिया
5. सिंगापुर
6. यूनाइटेड किंगडम
7. फिनलैंड
8. नीदरलैंड
9. डेनमार्क
10. चीन

यह क्यों मायने रखता है

भारत का 66वें से 38वें स्थान पर आना इनोवेशन नीतियों, औद्योगिक विकास और टेक्नोलॉजी विकास में लगातार सुधार दिखाता है। हालांकि अभी भी विकास की गुंजाइश है, लेकिन यह प्रगति वैश्विक इनोवेशन परिदृश्य में भारत की मजबूत स्थिति का संकेत देती है।

WIPO

- गठन: 14 जुलाई 1967
- प्रकार: संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- सदस्यता: 194 सदस्य देश
- महानिदेशक: डैरेन टैंग
- मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। इस फैसले से भारत को राहत मिली है, हालांकि समझौते की पूरी डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं।

पहले टैरिफ क्यों बढ़ाए गए थे

- पिछले साल अगस्त में, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था।
- ट्रंप ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत रियायती रूसी तेल खरीद रहा था, जिससे उनके दावे के अनुसार यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिल रही थी।
- नतीजतन, अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर बुरा असर पड़ा।

पीएम मोदी से बात करने के बाद ट्रंप ने क्या दावा किया?

- भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया।
- भारत अमेरिका और शायद वेनेजुएला से ज़्यादा तेल और सामान खरीदेगा।
- भारत ने आधिकारिक तौर पर इन दावों की पुष्टि नहीं की है।
- भारत पर ऊंचे टैरिफ का असर
- भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ देना पड़ा।
- अमेरिका को निर्यात में तेज़ी से गिरावट आई, खासकर इन क्षेत्रों में: कपड़ा, समुद्री भोजन और आभूषण
- ये क्षेत्र श्रम-प्रधान हैं, इसलिए नौकरियों पर भी असर पड़ा।

टैरिफ कटौती क्यों मायने रखती है

- नया 18% टैरिफ भारत को एशियाई देशों जैसे:
- वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश के बराबर लाता है।
- यह चीन के विकल्प के तौर पर भारत की स्थिति को बेहतर बनाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास अभी भी ये फायदे हैं:

- कम श्रम लागत
- राजनीतिक स्थिरता
- बड़ा घरेलू बाज़ार

चिंताएं और सावधानी

व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि:

- अभी तक यह साफ नहीं है कि किन उत्पादों को शामिल किया गया है।
- कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है।
- शून्य टैरिफ और शून्य गैर-टैरिफ बाधाओं के दावों पर अनिश्चितता है, खासकर कृषि क्षेत्र में।
- विशेषज्ञों ने ट्रंप के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि भारत 500 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदेगा, क्योंकि मौजूदा आयात इससे काफी कम है।
- विश्लेषकों ने ज़ोर दिया कि बिना किसी संयुक्त लिखित समझौते के, इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम डील के रूप में।

भारत की व्यापक व्यापार रणनीति

- अमेरिकी टैरिफ दबाव के कारण, भारत ने:
- अन्य साझेदारों के साथ व्यापार सौदों को तेज़ी से आगे बढ़ाया।
- निर्यात बाज़ारों में विविधता लाई।
- हाल ही में, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया, जिसमें 80-90% सामानों पर टैरिफ कम किया गया।
- यह चार साल में भारत का नौवां मुक्त व्यापार समझौता था।

भू-राजनीतिक पहलू

- अमेरिकी टैरिफ के बाद, भारत, चीन और रूस एक-दूसरे के करीब आए।
- भारत और चीन ने खुद को "साझेदार, प्रतिद्वंद्वी नहीं" कहा। भारत, चीन और रूस के नेताओं ने ग्लोबल मंचों पर एकता दिखाई।
- भारत ने उच्च-स्तरीय बैठकों के ज़रिए रूस के साथ संबंध भी मज़बूत किए।

आगे क्या होगा

- भारत और अमेरिका दोनों इसे सिर्फ़ पहला कदम मानते हैं।
- आने वाले महीनों में और बातचीत और चरणों की उम्मीद है।

US ट्रेड पैक्ट में भारत किसानों को कैसे बचाने का प्लान बना रहा है

ट्रेड डील क्या है

भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क की घोषणा की है। इस डील का मकसद कई चीज़ों पर टैरिफ कम करना है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट के लिए नए मौके खुलेंगे। हालांकि, बातचीत में खेती और उससे जुड़े सेक्टर बहुत सेंसिटिव पॉइंट बने हुए हैं।

खेती और किसानों के लिए सुरक्षा

भारत सरकार ने डील के तहत ज़्यादातर ज़रूरी खेती और डेयरी प्रोडक्ट जैसे गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, चीज़, इथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्ज़ियां और मीट को टैरिफ में छूट से पूरी तरह सुरक्षित किया है। यह सुरक्षा उन छोटे और मार्जिनल किसानों की रोजी-रोटी की सुरक्षा के लिए है जो इन सेक्टर पर निर्भर हैं। भारत ने US से बड़े पैमाने पर इंपोर्ट के लिए अपना घरेलू खेती का बाज़ार नहीं खोला है, ताकि यह पक्का हो सके कि किसानों को विदेशी प्रोडक्ट से अचानक कॉम्पिटिशन का सामना न करना पड़े। केंद्रीय मंत्रियों ने बार-बार कहा है कि डील के तहत छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

ये प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी हैं

खेती और उससे जुड़े कामों में करोड़ों भारतीय काम करते हैं और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारतीय किसानों को विदेशी प्रोड्यूसर की तुलना में अलग हालात का सामना करना पड़ता है — सीमित मशीनीकरण, ज़्यादा मेहनत, और कुल मिलाकर कम सब्सिडी। डर है कि सस्ते या भारी सब्सिडी वाले US फ़ार्म इंपोर्ट से लोकल कीमतें अस्थिर हो सकती हैं और अगर ठीक से बचाव नहीं किया गया तो भारतीय प्रोड्यूसर को नुकसान हो सकता है।

भारत ने सेंसिटिव सेक्टर को कैसे बचाया

यह एग्रीमेंट टैरिफ़ रेट कोटा जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है ताकि यह पक्का हो सके कि सेंसिटिव प्रोडक्ट तक पहुँच सीमित हो और किसानों पर बुरा असर न पड़े। खास अनाज और डेयरी जैसी सेंसिटिव चीज़ों पर कोई ड्यूटी में छूट नहीं दी गई है — इसका मतलब है कि अंतरिम डील के तहत अमेरिकी इंपोर्ट कम टैरिफ़ लेवल पर इन सेगमेंट में नहीं आ सकते।

फायदे और एक्सपोर्ट के मौके

किसानों को बचाने के साथ-साथ, यह डील टेक्सटाइल, स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल्स, मसाले, कॉफी और प्रोसेस्ड फूड जैसे कई नॉन-फार्म एक्सपोर्ट पर ज़ीरो या कम टैरिफ देती है — जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने में मदद मिलती है। कम टैरिफ से कपास उगाने वालों, मसाला प्रोड्यूसर और MSMEs (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़) को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे विदेशों में मार्केट बढ़ सकते हैं।

पॉलिटिकल और सोशल रिस्पॉन्स

कुछ किसान ग्रुप और पॉलिटिकल लीडर्स ने इसका विरोध किया है, उनका कहना है कि अगर अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स के लिए कोई मार्केट एक्सेस खुलता है तो यह डील अभी भी खेती के लिए खतरा बन सकती है। विरोध प्रदर्शन और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा बुलाया गया देशव्यापी भारत बंद, ट्रांसपेरेंसी और लंबे समय के असर को लेकर किसानों की चिंताओं को दिखाता है। विपक्ष के नेताओं ने इस डील को "किसान विरोधी" करार दिया है और फाइनल करने से पहले साफ सुरक्षा उपायों और सलाह-मशविरे की मांग की है।

मुख्य शब्दों की व्याख्या

1. टैरिफ: इंपोर्टेड सामान पर टैक्स। टैरिफ कम करने से विदेशी प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, जबकि ऊंचे टैरिफ रखने से घरेलू प्रोड्यूसर सुरक्षित रहते हैं। अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट: एक टेम्परारी फ्रेमवर्क जो किसी बड़ी डील को फाइनल करने से पहले ट्रेड की शर्तों को बताता है।
2. सेंसिटिव सेक्टर: ऐसे प्रोडक्ट या इंडस्ट्री (जैसे खेती और डेयरी) जिन्हें रोजी-रोटी और फूड सिक्योरिटी के लिए उनकी अहमियत की वजह से खास सुरक्षा की ज़रूरत होती है।
3. टैरिफ रेट कोटा: एक ऐसा सिस्टम जो किसी प्रोडक्ट के कम टैरिफ पर लिमिटेड इम्पोर्ट की इजाज़त देता है, जबकि उस लिमिट से ज़्यादा घरेलू मार्केट को बचाता है।
4. MSME: माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज — भारत में नौकरियों और एक्सपोर्ट के लिए एक ज़रूरी सेक्टर।

निष्कर्ष

भारत-US अंतरिम ट्रेड पैक्ट किसानों और संवेदनशील खेती के सेक्टर की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह कई भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बढ़े हुए मार्केट एक्सेस को ज़रूरी खेती के सामान के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ता है, जिसका मकसद आर्थिक विकास को सामाजिक और ग्रामीण स्थिरता के साथ बैलेंस करना है।

अमेरिका फरवरी, 2026 से भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% ड्यूटी हटाएगा

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने घोषणा की है कि वह भारतीय सामानों पर पहले लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा देगी। यह कदम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहमत एक अंतरिम व्यापार ढांचे के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और व्यापार बाधाओं को कम करना है।

इस डेवलपमेंट के मुख्य बिंदु

- टैरिफ हटाना: संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत लेवी को खत्म कर देगा। यह सरचार्ज अगस्त 2025 में भू-राजनीतिक और व्यापार तनाव से जुड़ी बढ़ी हुई ड्यूटी के हिस्से के रूप में लगाया गया था।
- पिछली ड्यूटी का संदर्भ: अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को पारस्परिक 25 प्रतिशत ड्यूटी के ऊपर जोड़ा गया था, जिससे अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले कई भारतीय निर्यात सामानों पर प्रभावी रूप से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लग गया था। इससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव पड़ा था।
- भारत की प्रतिबद्धताएं: टैरिफ में यह कमी भारत की रूसी तेल का सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आयात बंद करने की प्रतिबद्धता और अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग का विस्तार करने के समझौते के बाद हुई है।
- अंतरिम व्यापार ढांचा: संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक ढांचे की भी घोषणा की, जिसमें अमेरिका कई भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करेगा और भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि आयात पर बाधाओं को कम करने पर सहमत हुआ है। इसे एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का अग्रदूत माना जा रहा है।
- टैरिफ स्तरों पर प्रभाव: इस अंतरिम ढांचे के तहत, अमेरिका को भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ को लगभग 18 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले कुछ श्रेणियों में लगभग या 50 प्रतिशत से अधिक था।

US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ पर रोक लगाई

बैकग्राउंड: सुप्रीम कोर्ट ने पहले के टैरिफ को रद्द किया

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास बड़े ग्लोबल टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं था। यह फैसला 6–3 के बहुमत से सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ US कांग्रेस के पास बड़े टैक्स और टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार है।

टैरिफ को अमान्य क्यों घोषित किया गया?

इमरजेंसी लॉ (IEEPA) का इस्तेमाल

ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को सही ठहराने के लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह कानून प्रेसिडेंट को बड़े इंपोर्ट टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता है। इस फैसले ने US संविधान में शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को और मज़बूत किया।

टैरिफ को किसने चुनौती दी?

छोटे अमेरिकी बिज़नेस के एक ग्रुप ने केस फाइल किया था। कानूनी चुनौती का नेतृत्व भारतीय मूल के अमेरिकी वकील और US के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नील कत्याल ने किया। उन्होंने तर्क दिया कि टैरिफ गैर-संवैधानिक थे और राष्ट्रपति के अधिकार से ज़्यादा थे। फैसले के बाद, उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून के शासन की रक्षा करता है और एग्जीक्यूटिव पावर को सीमित करता है।

ट्रंप का जवाब: नया 10% ग्लोबल टैरिफ

कोर्ट से झटका लगने के बाद, ट्रंप ने तुरंत एक नए टैरिफ प्लान की घोषणा की।

इस बार इस्तेमाल किया गया कानून: ट्रेड एक्ट ऑफ़ 1974 (सेक्शन 122)

ट्रंप ने ट्रेड एक्ट ऑफ़ 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया।

यह कानून राष्ट्रपति को कांग्रेस की पूरी मंज़ूरी के बिना 150 दिनों के लिए 15% तक का टेम्पररी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।

इस नियम के तहत, ज़्यादातर इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाया गया है।

नए टैरिफ प्लान की मुख्य बातें

सभी देशों से इंपोर्ट पर 10% टैरिफ।

यह लगभग पाँच महीने (लगभग 150 दिन) तक लागू रहेगा। यह पहले से लागू टैरिफ के अलावा है। नया टैरिफ 24 फरवरी, 2026 से लागू हुआ।

ग्लोबल ट्रेड पर असर

US में इंपोर्ट होने वाला सामान और महंगा हो सकता है। अमेरिकी कंज्यूमर्स को ज़्यादा कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत समेत एक्सपोर्ट करने वाले देशों पर असर पड़ सकता है, जब तक कि भविष्य की बातचीत में शर्तें नहीं बदल जातीं। इस कदम से ग्लोबल ट्रेड रिलेशन में अनिश्चितता बढ़ती है।

यह डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है

यह दिखाता है कि कानूनी हार के बाद भी, अलग-अलग कानूनों के तहत ट्रेड एक्शन जारी रह सकते हैं। US में एग्जीक्यूटिव पावर और कांग्रेसनल अथॉरिटी के बीच चल रही बहस को हाईलाइट करता है। US ट्रेड पॉलिसी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन पर इसका बड़ा असर पड़ता है।

प्रोजेक्ट वॉल्ट: $12 बिलियन का US स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिज़र्व

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने "प्रोजेक्ट वॉल्ट" नाम की एक नई पहल की घोषणा की। इसका मकसद इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी क्रिटिकल मिनरल्स का पहला स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल बनाना है।

"प्रोजेक्ट वॉल्ट" क्या है?

प्रोजेक्ट वॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिज़र्व बनाने की एक योजना है। यह रिज़र्व मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी मिनरल्स को स्टोर करेगा। इसे अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई में रुकावटों से बचाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ये मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं?

- कई एडवांस्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिनमें शामिल हैं:
- इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरी
- स्मार्टफोन और कंप्यूटर
- एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और डिफेंस सिस्टम
- रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी

अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है?

- अमेरिका इनमें से कई मिनरल्स चीन से लेता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर हावी है।
- प्रोजेक्ट वॉल्ट का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना और सप्लाई चेन को ज़्यादा सुरक्षित बनाना है।
- यह कमी या कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स की रक्षा करने में मदद करेगा।

फंडिंग और स्ट्रक्चर

- इस पहल को लगभग $12 बिलियन की फंडिंग से सपोर्ट मिलेगा।
- $10 बिलियन US एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (EXIM) बैंक से लोन के रूप में।
- लगभग $1.7 बिलियन प्राइवेट कंपनियों से।
- इसमें इंडस्ट्री के प्लेयर्स के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है।

यह कैसे काम करेगा?

- गैलियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, लिथियम, वगैरह जैसे मिनरल्स खरीदे और स्टोर किए जाएंगे।
- इस सप्लाई का इस्तेमाल मार्केट में रुकावटों या इमरजेंसी के दौरान किया जा सकता है।
- यह स्टॉकपाइल कॉन्सेप्ट के मामले में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जैसा ही है, लेकिन तेल के बजाय मिनरल्स के लिए।

उम्मीद किए गए फायदे

- मुख्य इंडस्ट्रीज़ के लिए मज़बूत सप्लाई चेन सुरक्षा।
- मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित करने वाली कमी का कम जोखिम।
- विदेशी सोर्स, खासकर चीन पर निर्भरता कम।

यह क्यों ज़रूरी है?

- प्रोजेक्ट वॉल्ट को आर्थिक और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी मिनरल्स की भविष्य की सप्लाई को सुरक्षित करने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सोना लोगों का ध्यान क्यों खींच रहा है

सोना लोगों का ध्यान क्यों खींच रहा है

सोने की कीमतें हाल के सालों में तेज़ी से बढ़ी हैं, पिछले एक दशक में चार गुना बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है। यह बढ़ोतरी आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंताओं और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच हुई है, जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स को सोने जैसे सुरक्षित एसेट्स की ओर धकेलते हैं।

अभी के प्राइस लेवल और ऐतिहासिक ऊंचाई

सोना दुनिया भर में लगभग रिकॉर्ड या रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जिससे देशों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स के पास मौजूद गोल्ड रिज़र्व की कुल वैल्यू बढ़ रही है।

जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, मौजूदा गोल्ड होल्डिंग्स की कीमत और ज़्यादा फिजिकल गोल्ड जोड़े बिना भी काफी बढ़ जाती है।

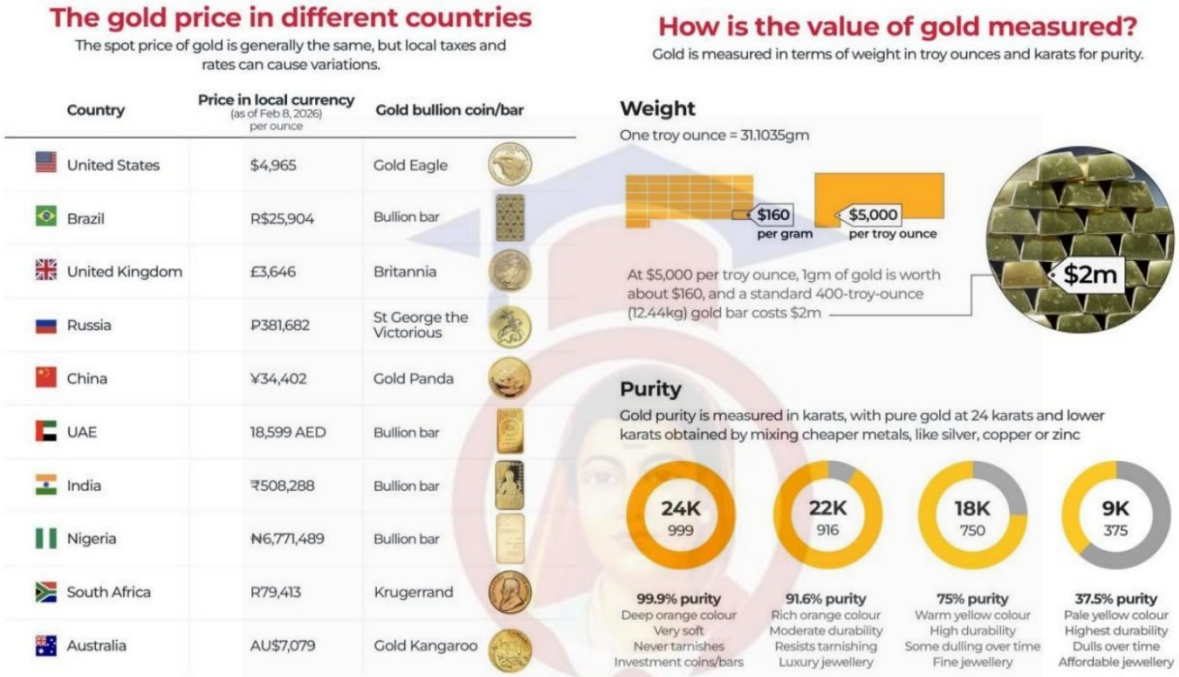

सोने की कीमतों को क्या बढ़ाता है

सेफ-हेवन डिमांड: ग्लोबल अस्थिरता के समय — जो जियोपॉलिटिकल झगड़ों, बढ़ती महंगाई या मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण होती है — इन्वेस्टर्स सोने को पसंद करते हैं क्योंकि यह कई दूसरे एसेट्स की तुलना में बेहतर वैल्यू बनाए रखता है।

सेंट्रल बैंक बाइंग: कई सेंट्रल बैंक US डॉलर जैसी पारंपरिक करेंसी से अलग होने के लिए अपने गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहे हैं। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन: देश एक ही रिज़र्व करेंसी पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और रिस्क को बांटने के लिए सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी: इंटरेस्ट रेट में बदलाव, महंगाई की उम्मीदें, और मॉनेटरी ईजिंग स्ट्रैटेजी भी सोने की डिमांड और कीमत पर असर डालती हैं।

सेंट्रल बैंक और गोल्ड रिज़र्व

सेंट्रल बैंक सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं, जो देशों के अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को मैनेज करने के तरीके में एक स्ट्रेटेजिक बदलाव को दिखाता है।

यह बदलाव कुछ हद तक करेंसी स्टेबिलिटी और US डॉलर में कमजोरी की चिंताओं के कारण है, जिससे सोना एक पसंदीदा रिज़र्व एसेट बन गया है।

सोना रखने से सरकारों को ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस के दौरान रिस्क को डाइवर्सिफाई करने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है।

ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सोने की भूमिका

सोना कई भूमिकाएँ निभाता है:

• वैल्यू का स्टोर: जब दूसरे मार्केट कमजोर होते हैं तो इन्वेस्टर पैसे बचाने के लिए सोने का इस्तेमाल करते हैं।

• सेफ-हेवन एसेट: जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक अनिश्चितता के समय में, सोने की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं।
• रिज़र्व एसेट: सेंट्रल बैंक करेंसी रिस्क से बचने और बचाव के लिए अपने ऑफिशियल रिज़र्व के हिस्से के तौर पर सोना रखते हैं।

जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक असर

चल रहे ग्लोबल टेंशन और ट्रेड से जुड़े मामलों ने इन्वेस्टर की सावधानी बढ़ा दी है, जिससे ज़्यादा खरीदार सोने की तरफ बढ़ रहे हैं।
जब बड़ी इकॉनमी महंगाई या धीमी ग्रोथ का सामना करती हैं, तो स्टॉक या बॉन्ड जैसे रिस्की एसेट्स की तुलना में सोना ज़्यादा आकर्षक हो जाता है।

आउटलुक और भविष्य के ट्रेंड

कई एनालिस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक की लगातार डिमांड, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बड़ी करेंसी से दूर डायवर्सिफिकेशन की वजह से सोने की कीमतें मज़बूत रहेंगी या बढ़ती रहेंगी।
कुछ अनुमान बताते हैं कि अगर मौजूदा ट्रेंड बने रहे तो 2026 के आखिर तक और उसके बाद भी सोने की कीमतें और भी ज़्यादा हो सकती हैं।

ज़रूरी शब्दों की व्याख्या

1. सोने की कीमत: वह मौजूदा मार्केट रेट जिस पर सोना खरीदा और बेचा जाता है, आमतौर पर US डॉलर प्रति औंस में बताया जाता है।
2. ग्लोबल रिज़र्व: सेंट्रल बैंकों और सरकारों द्वारा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के हिस्से के रूप में रखा गया सोने का स्टॉक।
3. सेफ-हेवन एसेट: एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय वैल्यू बने रहने या बढ़ने की उम्मीद होती है।
4. डी-डॉलराइज़ेशन: वह प्रोसेस जिससे देश अपने फाइनेंशियल रिज़र्व में US डॉलर पर निर्भरता कम करते हैं।
5. इन्फ्लेशन हेज: सोने जैसा एसेट जो महंगाई बढ़ने पर खरीदने की ताकत कम होने से बचाता है।

निष्कर्ष

ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई और सेंट्रल बैंकों द्वारा स्ट्रेटेजिक रिज़र्व डाइवर्सिफिकेशन के कारण सोने की कीमत बढ़ी है। एक सेफ हेवन और वैल्यू स्टोर के तौर पर इसकी भूमिका इसे दुनिया भर में एक ज़रूरी फाइनेंशियल एसेट बनाती है।

एग्रीस्टैक — UPI के बाद भारत का अगला बड़ा डिजिटल पुश

भारत सरकार एग्रीस्टैक नाम के एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के ज़रिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, जिसे "एग्रीकल्चर के लिए अगला UPI" बताया जा रहा है। एग्रीस्टैक का मकसद किसानों के लिए डिजिटल आइडेंटिटी और डेटा लेयर बनाना है ताकि अलग-अलग सोर्स से डेटा को एक ही इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करके क्रेडिट, इंश्योरेंस, सब्सिडी, मार्केट लिंकेज और फार्म सर्विसेज़ तक उनकी पहुंच बेहतर हो सके। इसका मकसद पेमेंट (जैसे, UPI) और वेलफेयर डिलीवरी जैसे एरिया में पहले से ही सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का फायदा उठाना है। (सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

एग्रीस्टैक क्या है?

एग्रीस्टैक एक ओपन, इंटरऑपरेबल एग्रीकल्चरल डेटा प्लेटफॉर्म का एक डेवलप हो रहा कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद किसान प्रोफाइल, लैंड रिकॉर्ड, मिट्टी की हेल्थ, फसल पैटर्न, मौसम डेटा, क्रेडिट हिस्ट्री, इनपुट यूसेज, इंश्योरेंस पॉलिसी और मार्केट प्राइस को इकट्ठा करना और लिंक करना है। यह एक डिजिटल पब्लिक गुड (DPG) के तौर पर काम करता है जिसे किसान, सरकारें, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एग्रीटेक सर्विस प्रोवाइडर सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं।

एग्रीस्टैक की ज़रूरत क्यों है?

- अलग-अलग हिस्सों में बंटा डेटा: भारत में खेती का डेटा कई डिपार्टमेंट (जैसे, खेती, रेवेन्यू, सिंचाई), स्कीम और राज्यों में बिखरा हुआ है, जिससे पॉलिसी बनाने में दिक्कतें आती हैं और जानकारी कम मिलती है।
- फाइनेंस तक पहुंच: छोटे किसानों को अक्सर वेरिफाइड डेटा की कमी के कारण क्रेडिट लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है; एग्रीस्टैक का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म डेटा-ड्रिवन क्रेडिट असेसमेंट को मुमकिन बना सकता है और इनफॉर्मल लेंडर्स पर निर्भरता कम कर सकता है।
- टारगेटेड सब्सिडी डिलीवरी: लाभार्थियों की डिजिटल पहचान को खेती की सर्विस और सब्सिडी से जोड़कर, सरकार भलाई के उपायों की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और लीक-प्रूफ डिलीवरी में सुधार कर सकती है।
- मार्केट एफिशिएंसी: कनेक्टेड डेटा मार्केट लिंकेज बना सकता है, जिससे किसानों को डिजिटल मार्केटप्लेस के ज़रिए रियल-टाइम कीमत की जानकारी, खरीदार और सप्लाई चेन तक पहुंचने में मदद मिलती है।

कंपोनेंट और टेक्निकल स्ट्रक्चर:

- किसानों की डिजिटल पहचान: हर किसान के लिए एक यूनिक डिजिटल प्रोफाइल जो आधार, बैंक अकाउंट, लैंड रिकॉर्ड और फसल की हिस्ट्री से जुड़ी होती है।
- जियो-टैग्ड फार्म डेटा: सैटेलाइट और सेंसर डेटा जो खेत की सटीक जगहों से जुड़ा होता है।
- डेटा एक्सचेंज लेयर: सुरक्षित API-बेस्ड इंटरऑपरेबिलिटी, जो बिना डेटा साइलो के सर्विसेज़ (क्रेडिट, इंश्योरेंस, इनपुट सप्लाई) देती है।
- ओपन API और थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन: स्टार्टअप, एग्रीटेक फर्म और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एग्रीस्टैक के टॉप पर सर्विसेज़ बनाने में मदद करता है।

संभावित फायदे

बेहतर फाइनेंशियल इनक्लूजन बैंक और NBFC क्रेडिट स्कोरिंग के लिए भरोसेमंद डेटासेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो सकती है और क्रेडिट रिस्क कम हो सकते हैं। इंश्योरेंस की पहुंच एग्री-इंश्योरेंस प्रोवाइडर पुरानी पैदावार, मिट्टी की क्वालिटी और मौसम के पैटर्न के आधार पर फसल और मौसम इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना सकते हैं। बेहतर पॉलिसी डिज़ाइन रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स सरकार को सबूतों पर आधारित पॉलिसी डिज़ाइन करने में मदद कर सकता है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) सुधार, फसल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी और रिस्क कम करने के प्लान।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- डेटा प्राइवेसी: एग्रीस्टैक का मुख्य हिस्सा पर्सनल और ज़मीन के डेटा का बड़ा कलेक्शन है, जो डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, सहमति के तरीकों और गलत इस्तेमाल के रिस्क के बारे में सवाल उठाता है।
- डिजिटल डिवाइड: छोटे, मार्जिनल और कम रिसोर्स वाले किसानों को कम कनेक्टिविटी, कम डिजिटल लिटरेसी और एक्सेस की दिक्कतों की वजह से इसे अपनाने में रुकावटें आ सकती हैं।
- इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव: भारत का फेडरल स्ट्रक्चर और अलग-अलग राज्यों की कैपेसिटी रोलआउट और डेटा स्टैंडर्डाइजेशन में दिक्कतें ला सकती हैं।
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: हालांकि UPI जैसे इनिशिएटिव को रेगुलेटरी ओवरसाइट का सपोर्ट है, लेकिन एग्रीस्टैक को डेटा गवर्नेंस और राइट्स के लिए एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है।

पावर गैप इंडेक्स

भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने देश के रणनीतिक प्रभाव और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार पावर गैप इंडेक्स का ज़िक्र किया है। यह इंडेक्स बताता है कि मज़बूत आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सैन्य बुनियाद होने के बावजूद भारत अपनी रणनीतिक क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है।

पावर गैप इंडेक्स क्या है?

पावर गैप इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक इंडिकेटर है। यह किसी देश के वास्तविक वैश्विक प्रभाव और उसकी आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताकत के हिसाब से जो प्रभाव होना चाहिए, उसके बीच के अंतर को मापता है। ज़्यादा पॉजिटिव स्कोर का मतलब है कि किसी देश का प्रभाव उम्मीद से ज़्यादा है; नेगेटिव स्कोर का मतलब है कि वह पीछे है।

इंडेक्स भारत के लिए क्या दिखाता है

इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि भारत का पावर गैप इंडेक्स स्कोर नेगेटिव है, जो बताता है कि देश अपनी रणनीतिक क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो, भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत, जनसंख्या का आकार और रणनीतिक क्षमता पूरी तरह से वैश्विक प्रभाव में नहीं बदल पा रही है।

यह क्यों मायने रखता है

- सर्वे ने पावर गैप इंडेक्स का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि अगर देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा मज़बूत भूमिका निभाता है, तो भारत का वैश्विक प्रभाव ज़्यादा हो सकता है।
- तेज़ी से बदलते वैश्विक व्यवस्था में भू-राजनीति, कूटनीति, व्यापार बातचीत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके मायने हैं।

सर्वे का आर्थिक संदर्भ

- हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और 2026-27 में इसके 6.8% से 7.2% के बीच बढ़ने का अनुमान है, लेकिन आर्थिक ताकत को रणनीतिक शक्ति में बदलने में चुनौतियां बनी हुई हैं।
- सर्वे ने इस स्थिति को एक "विरोधाभास" बताया, जहां भारत की मैक्रोइकोनॉमिक सफलता ऐसी वैश्विक स्थितियों के साथ मौजूद है जो प्रभाव के मामले में उस सफलता को पूरी तरह से नहीं दिखाती हैं।

सर्वे आगे के लिए क्या सुझाव देता है

- "पावर गैप" को खत्म करने के लिए, सर्वे ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में बेहतर रणनीतिक जुड़ाव, मज़बूत वैश्विक उपस्थिति और ज़्यादा मज़बूत नीतियों का आह्वान किया है।

- यह इस बात पर ज़ोर देता है कि भारत का संभावित प्रभाव उसके आर्थिक और जनसांख्यिकीय आकार से मेल खाना चाहिए।

GM फसलें

GM फसलें क्या हैं?

GM (जेनेटिकली मॉडिफाइड) फसलें ऐसे पौधे हैं जिनके DNA को जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बदला गया है ताकि उन्हें खास गुण मिल सकें, जैसे कीड़ों से बचना या खरपतवार नाशकों को सहना।

गुणों के उदाहरणों में कीड़ों से बचाव, हर्बिसाइड को सहना और बेहतर पोषण शामिल हैं।

दुनिया भर में आम GM फसलों में सोयाबीन, मक्का (कॉर्न), कपास और कैनोला शामिल हैं।

ट्रेड डील में GM फसलें फोकस में क्यों हैं

भारत-US ट्रेड डील ने GM फसलों पर फिर से बहस शुरू कर दी है क्योंकि कुछ US कृषि उत्पाद GM वेरिएंट के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन पर हावी हैं। सोयाबीन तेल, सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGS), और ज्वार जैसे उत्पाद ध्यान खींचते हैं क्योंकि वे US में GM फसलों से जुड़े हो सकते हैं।

GM फसल इंपोर्ट पर भारत की स्थिति

भारत डील के तहत GM फसल इंपोर्ट को लेकर सतर्क है। इसने ज़्यादातर GM फ़ूड फ़सलों के इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दी है और उन पर सख़्त नियम बनाए हैं। भारत में अब तक सिर्फ़ GM फ़सल की खेती की इजाज़त बीटी कॉटन को दी गई है। भारत की चिंता यह है कि GM प्रोडक्ट्स को इजाज़त देने से फ़ूड सेफ़्टी, बायोडायवर्सिटी और एक्सपोर्ट मार्केट पर असर पड़ सकता है, जो GM-फ़्री प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं।

किसानों के लिए यह क्यों ज़रूरी है

किसान ग्रुप्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ को डर है कि GM-लिंक्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि जानवरों के चारे के तौर पर भी, इम्पोर्ट करने से सोयाबीन और मक्का जैसी फ़सलों के लोकल किसानों को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि ऐसे इम्पोर्ट से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ सकता है और लोकल फ़सलों की माँग कम हो सकती है। इस बात की भी बड़ी चिंता है कि GM इम्पोर्ट से EU जैसे मार्केट में भारत का "नॉन-GM" एक्सपोर्ट फ़ायदा कमज़ोर हो सकता है, जहाँ कई खरीदार नॉन-GM प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं।

GM आइटम्स पर ट्रेड डील की लिमिट्स

अब तक, अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत, भारत ने मक्का और सोयाबीन जैसी बड़ी GM फ़सलों के लिए अपना मार्केट खोलने से परहेज़ किया है। ज़्यादातर फ़ोकस जानवरों के चारे के बाय-प्रोडक्ट (जैसे, DDGS) और सोयाबीन तेल जैसे लिमिटेड इम्पोर्ट पर है, लेकिन ये कोटा और ड्यूटी कंट्रोल के तहत आते हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए चावल, गेहूं, डेयरी, पोल्ट्री और चीनी जैसी ज़रूरी चीज़ों को ट्रेड में छूट से बाहर रखा गया है।

यह क्यों ज़रूरी है

ट्रेड डील में GM फसलों का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि यह फ़ूड सिक्योरिटी, किसानों की इनकम और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर असर डालता है। यह उन देशों के बीच पॉलिसी में अंतर को भी दिखाता है जो बड़े पैमाने पर GM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं (जैसे US) और जो इसे लेकर सावधान हैं (जैसे भारत)।

आगे का रास्ता

- GM फसलों के फ़ैसलों के लिए साइंस पर आधारित सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- इम्पोर्ट की इजाज़त देने से पहले किसानों की इनकम और कीमतों की सुरक्षा करें।
- कस्टमर की पसंद के लिए साफ़ GM फ़ूड लेबलिंग पक्का करें।
- जहाँ ज़रूरी हो, सिर्फ़ लिमिटेड, मॉनिटर किए गए इम्पोर्ट की इजाज़त दें।
- मज़बूत फसलों के लिए भारतीय बायोटेक रिसर्च को बढ़ावा दें।
- फ़ूड सिक्योरिटी और बायोडायवर्सिटी के साथ ट्रेड ग्रोथ को बैलेंस करें।

'भारत टैक्सी'— भारत की पहली कोऑपरेटिव राइड-हेलिंग सर्विस

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत का पहला कोऑपरेटिव-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' लॉन्च किया।

इसके पीछे कौन है?

यह सर्विस सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाई जाती है, जो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के तहत रजिस्टर्ड है, और इसे 6 जून 2025 को स्थापित किया गया था। इसे NCDC, IFFCO, Amul, KRIBHCO, NAFED, NDDB, NCEL और NABARD सहित प्रमुख कोऑपरेटिव संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

भारत टैक्सी की मुख्य विशेषताएं:

- कोऑपरेटिव मॉडल: ड्राइवर, जिन्हें सारथी के नाम से जाना जाता है, सह-मालिक होते हैं और गिग वर्कर के रूप में भुगतान पाने के बजाय मुनाफ़ा साझा करते हैं।
- ज़ीरो कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग: ड्राइवर अपनी कमाई अपने पास रखते हैं; इसमें प्राइवेट ऐप्स की तरह कोई पारंपरिक कमीशन या सर्ज प्राइसिंग नहीं है।
- ड्राइवर सोशल सिक्योरिटी: स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, रिटायरमेंट बचत और सहायता प्रणाली प्रदान करता है।
- प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने की आज़ादी: कोई एक्सक्लूसिविटी क्लॉज़ नहीं हैं, जिससे ड्राइवर दूसरे ऐप्स पर भी काम कर सकते हैं।
- सुरक्षा और सहायता: इसमें आपातकालीन सहायता, वेरिफाइड राइड डेटा, बहुभाषी सहायता और सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ सहयोग शामिल है।
- महिला सशक्तिकरण: "बाइक दीदी" पहल में 150 से ज़्यादा महिला ड्राइवरों को शामिल किया गया है।

पायलट और विस्तार योजनाएं:

- दिल्ली-NCR और गुजरात में 2025 के आखिर से एक पायलट चरण चलाया गया, जिसमें यूज़र अपनाने और ड्राइवर रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई।
- इस सर्विस का लक्ष्य दो साल के भीतर सभी भारतीय राज्यों और शहरों में विस्तार करना है।

भारत में कोऑपरेटिव क्षेत्र:

- भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन सामूहिक स्वामित्व, साझा शासन और मुनाफ़े के समान वितरण का समर्थन करता है। उदाहरणों में अमूल और कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
- भारत टैक्सी सरकार के "सहकार से समृद्धि" (सहयोग से समृद्धि) के विज़न के अनुरूप है और डिजिटल और गिग अर्थव्यवस्थाओं में कोऑपरेटिव की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

मोबिलिटी क्षेत्र का संदर्भ:

- Ola और Uber जैसी राइड-हेलिंग सेवाओं ने कमीशन-आधारित मॉडल के साथ बाज़ार पर कब्ज़ा कर लिया है। भारत टैक्सी ड्राइवर कल्याण और उचित कमाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्वदेशी विकल्प पेश करती है।
- कोऑपरेटिव प्लेटफ़ॉर्म का लक्ष्य विदेशी निवेश-आधारित मॉडल पर निर्भरता कम करना, मूल्य पारदर्शिता में सुधार करना और सेवा की सामर्थ्य बढ़ाना है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:
- 30% तक सस्ते किराए की पेशकश करके, यह सर्विस किफायती शहरी मोबिलिटी को सपोर्ट करती है, साथ ही ड्राइवरों को भी फायदा पहुंचाती है।
- राष्ट्रीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे, पहचान और पेमेंट सिस्टम) के साथ इंटीग्रेशन से एफिशिएंसी और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है।

US-बांग्लादेश रेसिप्रोकल ट्रेड पैक्ट

अमेरिका और बांग्लादेश ने वॉशिंगटन, USA में एक रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए। इस डील पर US की तरफ से US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीर उद्दीन ने दूसरों के साथ साइन किए।

यह डील क्या करती है

यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच ट्रेड की रुकावटों और टैरिफ को कम करता है। यह दोनों देशों के एक्सपोर्टर्स को बेहतर मार्केट एक्सेस देता है। यह किसी साउथ एशियन देश के साथ US का पहला ऐसा रेसिप्रोकल ट्रेड पैक्ट है।

टैरिफ में बदलाव (इम्पोर्ट पर टैक्स)

US ने बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर अपना टैरिफ पहले के 20% से घटाकर 19% कर दिया। बांग्लादेश और US एक-दूसरे के प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ लगाने पर सहमत हुए, जिससे ट्रेड सस्ता हो गया।

- बांग्लादेश के लिए फायदे: बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स, खासकर गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स में, कम टैरिफ कॉस्ट से फायदा होने की उम्मीद है।
- यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फ़ायदे: US को मशीनरी, डेयरी और सोया जैसे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए बांग्लादेश के मार्केट में ज़्यादा एक्सेस मिलेगा।

यह समझौता क्यों ज़रूरी है

यह समझौता US और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग के एक नए लेवल को दिखाता है। कम टैरिफ़ से दोनों तरफ़ से सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना सस्ता हो जाता है। इससे ट्रेड बढ़ सकता है, नौकरियाँ बन सकती हैं और आर्थिक रिश्ते मज़बूत हो सकते हैं।

रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है?

रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रेड डील है जिसमें दो देश एक-दूसरे को बराबर या आपसी फ़ायदे देते हैं, जैसे कम टैरिफ़, बेहतर मार्केट एक्सेस और कम ट्रेड रुकावटें।

नोट: यह डील दोनों देशों के बीच लगभग नौ महीने की बातचीत के बाद हुई है।

भारत और फ्रांस ने DTAC पर साइन किए

फ्रांस के राष्ट्रपति के हाल के भारत दौरे के दौरान, भारत और फ्रांस ने इंडिया-फ्रांस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन (DTAC) को अपडेट करने के लिए एक अमेंडिंग प्रोटोकॉल पर साइन किए, जिस पर असल में 1992 में साइन किया गया था। इस प्रोटोकॉल पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरपर्सन रवि अग्रवाल और भारत में फ्रांस के एम्बेसडर थिएरी मथौ ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से साइन किए।

अमेंडिंग प्रोटोकॉल में किए गए खास बदलाव

कैपिटल गेन्स टैक्सेशन राइट्स

यह बदला हुआ समझौता उस देश को शेयर बेचने से होने वाले कैपिटल गेन्स पर पूरे टैक्स लगाने के अधिकार देता है, जहाँ कंपनी रहती है, यह पहले के साफ़ न होने वाले नियमों की जगह लेता है और ग्लोबल नियमों के साथ तालमेल बिठाता है। इससे यह साफ़ होता है कि किस ज्यूरिस्डिक्शन के पास प्राइमरी टैक्सिंग अथॉरिटी है।

बदला हुआ डिविडेंड टैक्स स्ट्रक्चर

यह प्रोटोकॉल एक जैसे 10% डिविडेंड टैक्स रेट को दो-टियर स्ट्रक्चर से बदल देता है:

- कम से कम 10% कैपिटल रखने वाले शेयरहोल्डर्स के लिए 5%
- दूसरे शेयरहोल्डर्स के लिए 15%
- इस बदलाव का मकसद बड़े इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव को बैलेंस करना है, साथ ही सही टैक्स ट्रीटमेंट भी पक्का करना है।

मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) क्लॉज़ को हटाना

मोस्ट-फेवर्ड-नेशन क्लॉज़ को ट्रीटी से हटा दिया गया है, जिससे तीसरे देशों को दी जाने वाली बेहतर टैक्स शर्तों के ऑटोमैटिक हक पर लंबे समय से चले आ रहे मतलब के झगड़े खत्म हो गए हैं।

दूसरे टेक्निकल अपडेट्स

'टेक्निकल सर्विसेज़ के लिए फीस' की डेफिनिशन को इंडिया-U.S. DTAC के साथ अलाइन किया गया है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट (PE) का स्कोप बढ़ाकर इसमें सर्विस PE (लिमिट से ज़्यादा की गई सर्विसेज़) को शामिल किया गया है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के प्रोविज़न को अपडेट किया गया है, और टैक्स कलेक्शन में मदद पर एक नया आर्टिकल लाया गया है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन मज़बूत होगा। BEPS (बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग) मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट (MLI) के लागू होने वाले प्रोविज़न को ट्रीटी फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है।

बदलाव का महत्व

- टैक्स को लेकर ज़्यादा निश्चितता: अपडेटेड DTAC क्रॉस-बॉर्डर इनकम पर टैक्स लगाने के बारे में ज़्यादा साफ़ नियम देता है, जिससे इन्वेस्टर्स और टैक्सपेयर्स के लिए कन्फ्यूजन कम होता है।
- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा: इन सुधारों का मकसद दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करना, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और लोगों का फ्लो बढ़ाना और टैक्स फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना है।
- बिज़नेस के माहौल में सुधार: टैक्स अधिकारों और अपडेटेड डेफिनिशन पर बेहतर क्लैरिटी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों के बीच बिज़नेस करने में आसानी होने की उम्मीद है।

डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन (DTAC) क्या है?

DTAC एक बाइलेटरल ट्रीटी है जिसे दो ज्यूरिस्डिक्शन्स – सोर्स देश और रहने वाले देश – में एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लगाने से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे लोगों और बिज़नेस पर डबल टैक्स लगने से रोका जा सके। DTACs साफ़ टैक्स नियम देकर और फिस्कल रुकावटों को कम करके क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं।

मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) क्लॉज़ – मतलब

MFN क्लॉज़ यह पक्का करता है कि अगर कोई देश भविष्य की किसी ट्रीटी में किसी तीसरे देश को टैक्स बेनिफिट देता है (जैसे, कम विदहोल्डिंग टैक्स रेट), तो दूसरी पार्टी भी ऑटोमैटिकली उन्हीं बेनिफिट का दावा कर सकती है। इंडिया-फ्रांस DTAC में इसे हटाने का मतलब है कि अब बेनिफिट ट्रीटी में साफ तौर पर बताए जाने चाहिए और दूसरे एग्रीमेंट के आधार पर ऑटोमैटिकली उनका दावा नहीं किया जा सकता।

BEPS (बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग) कॉन्टेक्स्ट

BEPS का मतलब है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी, जिसका इस्तेमाल वे प्रॉफिट को कम या बिना टैक्स वाले जूरिस्डिक्शन में शिफ्ट करने के लिए करती हैं, जिससे दूसरे देशों का टैक्स बेस कम हो जाता है। DTAC में BEPS स्टैंडर्ड को शामिल करने से एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस को रोकने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और ट्रीटी को OECD के नेतृत्व वाले ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म के साथ अलाइन करने में मदद मिलती है।

भारत-कनाडा ऊर्जा सहयोग

भारत और कनाडा जनवरी 2026 में द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। इस समझौते की घोषणा गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान की गई।

- मंत्रिस्तरीय संवाद की शुरुआत: वरिष्ठ-स्तरीय सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद औपचारिक रूप से शुरू किया गया।
- विविध ऊर्जा व्यापार: दोनों पक्ष द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को गहरा करने पर सहमत हुए, जिसमें भारत को कनाडाई LNG, LPG और कच्चे तेल की आपूर्ति, और भारत से कनाडा को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति शामिल है।
- रणनीतिक संदर्भ: यह बैठक जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों द्वारा कार्य-स्तरीय जुड़ाव को फिर से शुरू करने के लिए दिए गए निर्देशों के बाद हुई।
- ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाएं: दोनों देशों ने आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और विविध ऊर्जा स्रोतों के महत्व पर प्रकाश डाला।
- IEW में पहले कनाडाई मंत्री: इस कार्यक्रम में पहली बार किसी कनाडाई कैबिनेट मंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक में भाग लिया।

भारत-कनाडा ऊर्जा सहयोग के बारे में:

- कनाडा का लक्ष्य पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा निर्यात दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और पारंपरिक बाजारों से विविधीकरण के साथ एक वैश्विक ऊर्जा महाशक्ति बनना है।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक और तीसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता है, और अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि के एक-तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार होने की उम्मीद है।
- यह नवीनीकृत साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता को संबोधित करती है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग शामिल है।

व्यापार और रणनीतिक निहितार्थ:

- भारत और कनाडा के बीच दो-तरफ़ा माल व्यापार 2024 में C$13.3 बिलियन था, जिसमें विस्तारित ऊर्जा और खनिज संबंधों के माध्यम से और बढ़ने की क्षमता है।
- भारत EV बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए कनाडा के साथ महत्वपूर्ण खनिज सहयोग की खोज कर रहा है।
- यह समझौता हाइड्रोजन, जैव ईंधन, बैटरी भंडारण और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में सहयोग के रास्ते भी खोलता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोण:

- यह ऊर्जा सहयोग पिछले तनावों के बाद राजनयिक और आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित करने और मजबूत करने के व्यापक भारत-कनाडा प्रयासों का हिस्सा है, जो एशिया के बढ़ते ऊर्जा बाजारों में व्यावहारिक कूटनीति और आपसी हितों को दर्शाता है।
- इस तरह के जुड़ाव भारत को मध्य पूर्व और कतर से परे अपने ऊर्जा आयात स्रोतों में विविधता लाने में मदद करते हैं, जहां से वह आज अधिकांश कच्चा तेल और LNG प्राप्त करता है।

अन्य प्रमुख खबरें

RBI-ESMA सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ पर MoU

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी (ESMA) ने सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ (CCPs) से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह नया MoU 28 फरवरी 2017 के पिछले समझौते की जगह लेता है, जो अपडेटेड रेगुलेटरी तालमेल को दिखाता है। यह ESMA के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करता है ताकि वह RBI की सुपरवाइज़री और रेगुलेटरी गतिविधियों पर भरोसा कर सके, साथ ही यूरोपियन यूनियन (EU) की वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित कर

सके। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम में सीमा-पार सहयोग के महत्व को दर्शाता है। नतीजतन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) और अन्य भारतीय CCPs यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (EMIR) के तहत मान्यता के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं, जिससे EU क्लियरिंग सदस्य ट्रेडों को अधिक कुशलता से क्लियर और सेटल कर सकेंगे। यह समझौता भारत के क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख को लेकर दो साल के रेगुलेटरी गतिरोध को खत्म करता है और भारत-EU वित्तीय बाज़ार एकीकरण के लिए रास्ता खोलता है।

CCPs और उनके कार्यों के बारे में

- सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ (CCPs) वित्तीय बाज़ारों में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, ट्रेड सेटलमेंट की गारंटी देते हैं और लेनदेन में काउंटरपार्टी जोखिम को कम करते हैं।
- CCPs क्लियरिंग और सेटलमेंट करते हैं - यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो भी ट्रेड पूरा हो।

EMIR मान्यता का महत्व

- यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (EMIR) के तहत, किसी तीसरे देश के CCP को EU वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने के लिए ESMA द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- मान्यता के बिना, EU बैंकों को उच्च पूंजी शुल्क और विदेशी क्लियरिंग हाउस तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे लेनदेन लागत बढ़ जाती है।

ESMA के बारे में

- यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी यूरोपियन यूनियन का वित्तीय बाज़ार नियामक है, जो सदस्य देशों में निष्पक्ष और स्थिर वित्तीय बाज़ारों को सुनिश्चित करता है।
- ESMA MiFID II (मार्केट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टिव) और EMIR (यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन) जैसे फ्रेमवर्क के तहत बाज़ारों की देखरेख करता है।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

- बढ़ा हुआ सहयोग EU के साथ भारत की वित्तीय कनेक्टिविटी में सुधार करता है, जो इसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
- यह वैश्विक वित्तीय एकीकरण और निवेशक विश्वास के भारत के उद्देश्य का समर्थन करता है।
- भारतीय वित्तीय बाज़ारों में विदेशी निवेशकों के लिए सीमा-पार क्लियरिंग दक्षता को सुविधाजनक बनाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के लिए एक तंत्र बनाता है। यह कदम वाशिंगटन के तेहरान पर आर्थिक दबाव डालने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के उद्देश्यों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

टैरिफ किस बारे में हैं?

- यह आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका को उन देशों से आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अनुमति देता है - उदाहरण के लिए 25% तक - जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान से सामान या सेवाएं खरीदते हैं।
- यह टैरिफ उन देशों से अमेरिका में आयात किए गए उत्पादों पर लागू होगा।

अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है?

- अमेरिकी सरकार का कहना है कि ईरान उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है - और टैरिफ ईरान के प्रभाव को कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
- कार्यकारी आदेश ईरान से संबंधित राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी रखता है।

यह कैसे काम करेगा?

- वाणिज्य सचिव और विदेश सचिव यह तय करेंगे कि कौन से देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं और कितना टैरिफ लगाना है, यह तय करेंगे।
- यह आदेश इन अधिकारियों को टैरिफ प्रणाली को लागू करने के लिए नियम और दिशानिर्देश बनाने की शक्ति देता है।

इसका क्या प्रभाव हो सकता है?

- ईरान के साथ मजबूत व्यापार संबंध रखने वाले देशों - जैसे चीन, तुर्की, यूएई, इराक और भारत - को अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, यदि वे ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं।
- उच्च टैरिफ उनके निर्यात किए गए सामानों को अधिक महंगा बना सकते हैं, जिससे संभावित रूप से वैश्विक व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है।

भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए

भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर साइन किए। ToR यह तय करता है कि FTA बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, इसका दायरा और फ्रेमवर्क क्या होगा।

GCC के सदस्य कौन हैं

- गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) में छह देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन

यह क्यों महत्वपूर्ण है

- लंबे समय से रुकी बातचीत फिर से शुरू करना
- भारत-GCC FTA के लिए बातचीत पहली बार दो दशक पहले शुरू हुई थी।
- पहले बातचीत 2006 और 2008 में हुई थी लेकिन फिर रुक गई थी।
- ToR पर साइन करने से यह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है और औपचारिक रूप से बातचीत का दौर शुरू होता है।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना

- FTA से भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है।
- यह खाद्य प्रसंस्करण, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग बढ़ा सकता है।

IDFC फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में ₹590 करोड़ के फ्रॉड का पता लगाया, जिससे मार्केट में उथल-पुथल मच गई

IDFC फर्स्ट बैंक ने अपनी चंडीगढ़ ब्रांच में **हरियाणा सरकार की संस्थाओं के अकाउंट्स में बिना इजाज़त और अनियमित ट्रांज़ैक्शन से जुड़े ₹590 करोड़ के संदिग्ध फ्रॉड का खुलासा किया है। इसके बाद रेगुलेटरी कार्रवाई, अंदरूनी जांच और बैंक के शेयर प्राइस में भारी गिरावट आई।

घटना का ओवरव्यू

ये गड़बड़ियां सबसे पहले तब सामने आईं जब हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट ने बैंक को बंद करने और फंड ट्रांसफर करने का अनुरोध किया, जिससे बैंक द्वारा दिखाए गए बैलेंस और सरकार द्वारा क्लेम की गई रकम के बीच अंतर का पता चला। बाद में उसी ब्रांच में रखे गए हरियाणा सरकार के दूसरे अकाउंट्स में भी इसी तरह की गड़बड़ियां पाई गईं, जिससे आगे की जांच शुरू हुई। रिकंसिलिएशन के तहत कुल रकम लगभग ₹590 करोड़ होने का अनुमान है, हालांकि इसका सही असर क्लेम वैलिडेशन, रिकवरी और कानूनी प्रोसेस के बाद पता चलेगा।

बैंक का जवाब और की गई कार्रवाई

बैंक ने चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनके शामिल होने का शक है और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसने बैंकिंग रेगुलेटर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को इसकी जानकारी दी है, और इसमें शामिल लोगों और बाहरी पार्टियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने कथित फ्रॉड के तरीकों का पता लगाने और इंटरनल कंट्रोल को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी (KPMG) को नियुक्त किया है। रिकवरी की कोशिशों के तहत, जिन अकाउंट्स पर गलत तरीके से फंड मिलने का शक है, उनमें बैलेंस पर लियन-मार्क लगाने के लिए दूसरे बैंकों को 'रिकॉल रिक्वेस्ट' भेजी गई हैं।

रेगुलेटरी और मार्केट पर असर

हरियाणा सरकार ने सरकारी काम के लिए IDFC फर्स्ट बैंक को डी-एम्पैनल्ड कर दिया है, और इसके डिपार्टमेंट्स को अगली सूचना तक लेंडर के साथ अकाउंट बंद करने का निर्देश दिया है। स्टॉक में भारी गिरावट के बावजूद, RBI ने कहा है कि इस अकेली घटना से बैंकिंग सेक्टर को कोई सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, जिसका मकसद मार्केट और डिपॉजिटर्स को फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ के बारे में भरोसा दिलाना है।

घटना का महत्व

कथित फ्रॉड की रकम (~₹590 करोड़) बैंक के हाल के तिमाही नेट प्रॉफिट ₹503 करोड़ से ज़्यादा है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और बैंकों के अंदर इंटरनल कंट्रोल पर ज़रूरी सवाल उठते हैं।

यह मामला इंटरनल कंट्रोल में चूक होने पर सरकारी और पब्लिक सेक्टर के अकाउंट्स की कमज़ोरी को दिखाता है, जिससे मज़बूत रिकंसिलिएशन प्रैक्टिस की ज़रूरत पर ज़ोर पड़ता है। रेगुलेटरी जांच और इंडिपेंडेंट ऑडिट के नतीजों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बैंकिंग फ्रॉड और इंटरनल कंट्रोल के बारे में

बैंकिंग फ्रॉड में इंटरनल या एक्सटर्नल एजेंट्स द्वारा जानबूझकर फंड का गलत इस्तेमाल/गलत इस्तेमाल शामिल होता है। फिड्यूशरी एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए मज़बूत इंटरनल कंट्रोल, कामों का बंटवारा और रेगुलर ऑडिट ज़रूरी हैं। फोरेंसिक ऑडिट फाइनेंशियल गड़बड़ियों के कारण और हद का पता लगाने और सिस्टम में सुधार के सुझाव देने में मदद करते हैं।

RBI के सिस्टमिक रिस्क असेसमेंट के बारे में

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी पर नज़र रखता है और यह पता लगाता है कि क्या किसी बैंक की समस्या पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। "कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं" का नतीजा यह भरोसा दिखाता है कि समस्या अलग-थलग है और इससे सेक्टर-वाइड ऑपरेशन को खतरा नहीं है।

बैंक गवर्नेंस और मार्केट का भरोसा

किसी बैंक में फाइनेंशियल गड़बड़ियों से अक्सर शेयर की कीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव होता है, जो इन्वेस्टर की भावना और भरोसे को दिखाता है। भरोसा वापस लाने के लिए रेगुलेटरी निगरानी, ट्रांसपेरेंट खुलासे और सुधार के कदम बहुत ज़रूरी हैं।

गुजरात में भारत का पहला CBDC-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) लॉन्च हुआ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 फरवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) का उद्घाटन किया।

इस पहल में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)-ऑथराइज़्ड डिजिटल करेंसी (e-₹) का इस्तेमाल डिजिटल टोकन के तौर पर किया जाता है ताकि PDS सब्सिडी को ट्रांसपेरेंट तरीके से बेनिफिशियरी के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सके। गुजरात इस पायलट को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, आनंद और वलसाड में 26,000 से ज़्यादा परिवार शामिल हैं। बेनिफिशियरी QR कोड या आधार-बेस्ड OTP का इस्तेमाल करके राशन का हक ले सकेंगे। एक 'अन्नापूर्ति ग्रेन ATM' भी लॉन्च किया गया जो 35 सेकंड में 25 kg तक अनाज देता है।

CBDC-बेस्ड PDS पायलट की खास बातें

डिजिटल टोकन वॉलेट: बेनिफिशियरी को आइटम, क्वांटिटी और कीमत बताने वाले टोकन मिलते हैं। ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी: डिजिटल सिस्टम का मकसद सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की रियल-टाइम ट्रैकिंग बनाकर PDS में करप्शन और लीकेज को कम करना है। कोई बिचौलिया नहीं: डायरेक्ट डिजिटल क्रेडिट बिचौलियों की भागीदारी को कम करता है और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है।

एजुकेशनल महत्व

CBDC क्या है?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) किसी देश की फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है, जिसे सेंट्रल बैंक (भारत में, RBI) जारी और रेगुलेट करता है। यह लीगल टेंडर है लेकिन सिर्फ डिजिटल रूप में मौजूद है और इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जा सकता है।

CBDC के फायदे

- ट्रांसपेरेंसी: डिजिटल लेजर से ट्रेस किए जा सकने वाले ट्रांजैक्शन मुमकिन होते हैं, जिससे फ्रॉड कम होता है।
- फाइनेंशियल इन्क्लूजन: बैंक अकाउंट की ज़रूरत के बिना डिजिटल करेंसी तक एक्सेस देता है।
- कम लागत: फिजिकल कैश पर कम डिपेंडेंस से प्रिंटिंग और हैंडलिंग कॉस्ट बचती है।
- रियल-टाइम ट्रांसफर: सब्सिडी या पेमेंट की तुरंत डिलीवरी।

दूसरे ज़रूरी डेवलपमेंट

- एक्सपेंशन प्लान: CBDC-PDS मॉडल को जल्द ही चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक्सपैंड किया जाएगा।
- नेशनल रोलआउट: एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि टेक्निकल और ऑपरेशनल तैयारी बेहतर होने पर इसे 3-4 साल में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है।
- डिजिटल इंडिया लिंक: यह पहल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जुड़ी है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सरकारी सेवाओं को मॉडर्न बनाना है।

याद रखने लायक ज़रूरी शब्द

- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS): योग्य नागरिकों को सब्सिडी वाली दरों पर अनाज और ज़रूरी चीज़ें देने की सरकारी योजना।
- ई-रुपी (e₹): CBDC का भारत का वर्शन, जो RBI द्वारा सपोर्टेड डिजिटल करेंसी के तौर पर काम करता है।
- प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी: डिजिटल टोकन जिन्हें कंडीशन किया जा सकता है (जैसे, फ़ूड सब्सिडी जैसे खास इस्तेमाल के लिए)।
- QR कोड और OTP ऑथेंटिकेशन: पारंपरिक कैश एक्सचेंज के बिना सुरक्षित ट्रांज़ैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल वेरिफिकेशन तरीके।

रक्षा एवं सुरक्षा

नेशनल काउंटर-टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी "PRAHAAR"

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत की पहली बड़ी नेशनल काउंटर-टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी PRAHAAR (पॉलिसी फॉर रिस्पॉन्स अगेंस्ट होस्टाइल एक्टिविटीज़ एंड रेडिकलिज्म) नाम से पेश की है। यह नई स्ट्रैटेजी भारत में बढ़ते आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क देती है, जिसमें रोकथाम, मिलकर जवाब देने और मज़बूती पर फोकस किया गया है।

PRAHAAR क्या है?

PRAHAAR एक नेशनल डॉक्ट्रिन है जो पूरी सरकार और पूरे समाज के नज़रिए से भारत के काउंटर-टेररिज्म प्रयासों को गाइड करता है। PRAHAAR का मतलब है स्ट्रैटेजी के मुख्य एलिमेंट:

- भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना
- तेज़ और सही जवाब
- तालमेल के लिए अंदरूनी क्षमताओं को इकट्ठा करना
- मानवाधिकार और कानून के आधार पर नुकसान कम करना
- आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हालात को कम करना
- आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को एक साथ लाना
- सामाजिक मदद से रिकवरी और मज़बूती

मुख्य उद्देश्य और स्ट्रैटेजिक फोकस

पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एक्सपर्ट सोर्स के अनुसार, मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- रियल-टाइम इंटेलिजेंस और पहले से मौजूद उपायों के आधार पर आतंकी हमलों को होने से पहले ही रोकना।
- आतंकवादी गतिविधियों पर तेज़, सही और मिलकर जवाब देना।
- केंद्र, राज्य और स्थानीय एनफोर्समेंट बॉडी के बीच एजेंसी के बीच तालमेल को मज़बूत करना।
- कम्युनिटी के साथ मिलकर कट्टरता और चरमपंथी सोच को कम करना।
- आतंकवादियों को देश और विदेश में फंड, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने से रोकना।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके प्रभावित समुदायों में रिकवरी और मज़बूती को बढ़ावा देना।

पॉलिसी की खास बातें

इंटेलिजेंस पर आधारित और प्रोएक्टिव तरीका

PRAHAAR इंटेलिजेंस-फर्स्ट सिद्धांत पर ज़ोर देता है, जहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस (JTFI) रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और एजेंसियों के बीच मिलकर काम करने के लिए सेंट्रल नोड के तौर पर काम करते हैं।

पूरी सरकार और पूरे समाज की स्ट्रैटेजी

यह पॉलिसी इन चीज़ों को शामिल करते हुए मिलकर काम करने को बढ़ावा देती है:

- सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्स
- नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) जैसी स्पेशल यूनिट
- सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन, कम्युनिटी और धार्मिक नेता
- लचीलापन बढ़ाने और कट्टरपंथ के खतरे को कम करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप।

इंटरनेशनल सहयोग

PRAHAAR ग्लोबल काउंटर-टेरर कोशिशों के लिए भारत के कमिटमेंट को इन तरीकों से मज़बूत करता है:

- म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLATs) और एक्सट्रैडिशन एग्रीमेंट सहित बाइलेटरल और मल्टीलेटरल सहयोग को मज़बूत करना।
- यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादियों को डेज़िग्नेट करने के लिए डिप्लोमैटिक तरीके से जुड़ना।

उभरते और हाई-टेक खतरों से निपटना

पॉलिसी में बढ़ते आतंकी खतरों को पहचाना गया है, जिनमें शामिल हैं:

- स्मगलिंग या हमलों के लिए ड्रोन और रोबोटिक्स का गलत इस्तेमाल
- साइबर-रेडिकलाइज़ेशन, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और डार्क वेब ऑपरेशन
- टेरर फाइनेंसिंग के लिए क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल
- CBRNED खतरे (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल) उभरते हुए जोखिम हैं।

मानवाधिकार और कानून का राज

PRAHAAR के तहत भारत की काउंटर-टेरर स्ट्रैटेजी, ह्यूमन राइट्स और कानून के राज के फ्रेमवर्क के अंदर कार्रवाई को मज़बूती से करती है, यह पक्का करती है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन और कानूनी प्रोसेस इंटरनेशनल नियमों और सुरक्षा उपायों को बनाए रखें।

नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट

- ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी: भारत सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस का रुख रखता है और धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या विचारधारा के आधार पर हिंसा को सही ठहराने के किसी भी तरीके को खारिज करता है।
- यह स्ट्रैटेजी आतंकवाद से लड़ने में भारत के दशकों के अनुभव को शामिल करती है और इसका मकसद लंबे समय तक चलने वाली, टेक्नोलॉजी से चलने वाली काउंटर-टेरर नीति को संस्थागत बनाना है। PRAHAAR नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में रिएक्टिव पॉलिसी से प्रोएक्टिव, एंटीसिपेटरी थ्रेट मिटिगेशन की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है।

मल्टीनेशनल CTF-154 टास्क फोर्स

इंडियन नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 (CTF-154) की कमान संभाल ली है, जो एक मल्टीनेशनल नेवल ट्रेनिंग ग्रुप है। यह टेकओवर 11 फरवरी 2026 को बहरीन के मनामा में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) के हेडक्वार्टर में हुआ। इंडियन नेवी के कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी, शौर्य चक्र, CTF-154 के नए कमांडर बने, उन्होंने इटैलियन नेवी के जाने वाले कमांडर की जगह ली।

CTF-154 के बारे में

CTF-154, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) का हिस्सा है — यह लगभग 47 देशों की एक बड़ी इंटरनेशनल नेवल पार्टनरशिप है जो समुद्र में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। यह सदस्य देशों के नेवी के लोगों की ट्रेनिंग और स्किल बनाने पर फोकस करता है। इसमें मैरीटाइम अवेयरनेस, मैरीटाइम लॉ, रेस्क्यू ऑपरेशन और लीडरशिप जैसे एरिया शामिल हैं। CTF-154 मई 2023 में बनाया गया था और यह पूरे मिडिल ईस्ट में ट्रेनिंग इवेंट होस्ट करता है।

यह क्यों ज़रूरी है

यह पहली बार है जब इंडियन नेवी ने CMF टास्क फ़ोर्स को लीड किया है, जो ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया के रोल में एक ज़रूरी कदम है। यह इंडिया की नेवल स्किल और लीडरशिप पर दूसरे देशों के भरोसे को दिखाता है।

CTF-154 क्या करता है

यह टास्क फ़ोर्स कई देशों की नेवी को एक साथ ट्रेनिंग लेने में मदद करती है ताकि वे समुद्र में शेयर्ड चैलेंज को हैंडल कर सकें। ट्रेनिंग में शिप ट्रैकिंग, समुद्र में लॉ एनफोर्समेंट, मैरीटाइम रेस्क्यू और लीडरशिप स्किल शामिल हैं।

बड़ी तस्वीर

CTF-154 कई CMF टास्क फ़ोर्स में से एक है। दूसरे मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी-पायरेसी और खास समुद्री इलाकों में सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। इस फ़ोर्स को लीड करने से इंडिया का इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बड़े समुद्री रास्तों को सेफ़ रखने में रोल मज़बूत होता है।

114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये की डील

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने फ्रांस के साथ एक गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी (AoN) को मंज़ूरी दे दी है। इसकी अनुमानित लागत ₹3.25 लाख करोड़ (लगभग $40 बिलियन) है — यह शायद भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। यह एक्विजिशन इंडियन एयर फ़ोर्स के लिए है, जिसकी स्क्वाड्रन की ताकत ऑथराइज़्ड लेवल से नीचे आ गई है।

इसे कैसे किया जाएगा:

फ्रांस से 18 जेट फ्लाई-अवे कंडीशन में लिए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद शुरू होगी। बाकी जेट मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत में बनाए जाएंगे, जिनके प्रोडक्शन में काफी स्वदेशी कंटेंट होगा।

- स्ट्रेटेजिक टाइमिंग: यह मंज़ूरी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के फरवरी के बीच में भारत के ऑफिशियल दौरे से ठीक पहले आई है, जो भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को दिखाता है।
- बड़ी खरीद: DAC ने लगभग ₹3.60 लाख करोड़ के प्रपोज़ल के तहत दूसरे डिफेंस सिस्टम (जैसे, बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट) और मिसाइलों की खरीद को भी मंज़ूरी दी।

राफेल फाइटर जेट:

राफेल एक ट्विन-इंजन, कैनार्ड-डेल्टा विंग, मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड सपोर्ट, टोही और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन में काबिल है। इसे एडवांस्ड एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाला 4.5-जेनरेशन का फाइटर माना जाता है।

भारत में स्वदेशी हेलीकॉप्टर उत्पादन

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस (अडानी ग्रुप का हिस्सा) और इटली की लियोनार्डो (एक ग्लोबल एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी) ने भारत में एक पूरा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए हैं - जिसमें डिज़ाइन और प्रोडक्शन से लेकर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस तक सब शामिल है।

यह पार्टनरशिप क्यों मायने रखती है

- बढ़ती हेलीकॉप्टर की मांग को पूरा करना
- अगले दशक में भारत की सेना को 1,000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत पड़ने की उम्मीद है।
- यह सहयोग लियोनार्डो के AW169M और AW109 TrekkerM हेलीकॉप्टरों जैसे मॉडल पर फोकस करता है।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना (आत्मनिर्भर भारत)

- हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करने के बजाय, भारत का लक्ष्य उन्हें स्थानीय स्तर पर बनाना है, जिससे विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम होगी।
- यह पार्टनरशिप देश के अंदर क्षमताएं बनाकर सरकार के "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को सपोर्ट करती है।

भारत में पूरा हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम बनाना

इस समझौते में शामिल हैं:

- हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की स्थानीय डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली।
- भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सुविधाएं ताकि हेलीकॉप्टरों की सर्विस स्थानीय स्तर पर की जा सके।
- इन प्लेटफॉर्म पर भारतीय पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
- बाद में सिविल एविएशन (गैर-सैन्य हेलीकॉप्टर उपयोग) तक संभावित विस्तार।

भारत के लिए फायदे

- आर्थिक और रोज़गार में बढ़ोतरी: इस इकोसिस्टम से इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेवाओं में हज़ारों कुशल नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
- मज़बूत रक्षा क्षमताएं: भारत में हेलीकॉप्टर बनने और सपोर्ट मिलने से रक्षा बल ज़्यादा तैयार और आत्मनिर्भर बनेंगे।
- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और विशेषज्ञता साझा करना: लियोनार्डो एडवांस्ड हेलीकॉप्टर डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी लाता है। अडानी के साथ पार्टनरशिप से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के अनुभव का फायदा मिलेगा।

लियोनार्डो:

- इंडस्ट्री: एयरोस्पेस · डिफेंस
- स्थापना: 1948
- मुख्यालय: रोम, इटली
- चेयरमैन: स्टेफानो पोंटेकोर्वो
- CEO और जनरल मैनेजर: रॉबर्टो सिंगोलानी

अन्य प्रमुख खबरें

VOC पोर्ट अथॉरिटी एंटी-ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना

वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने एक आधुनिक एंटी-ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है, जिससे यह ऐसा करने वाला भारत का पहला पोर्ट बन गया है। इस कदम का मकसद पोर्ट पर समुद्री और तटीय सुरक्षा को मज़बूत करना है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- पोर्ट महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो व्यापार, आयात और निर्यात को संभालते हैं।
- अनाधिकृत ड्रोन जासूसी, तस्करी, या पोर्ट सुविधाओं पर हमलों जैसे सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- नया सिस्टम संदिग्ध ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने में मदद करेगा।

एंटी-ड्रोन सिस्टम में क्या शामिल है?

- इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) और रडार-आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
- मुख्य उपकरणों में शामिल हैं:
- ड्रोन डिटेक्टर,
- ड्रोन डिटेक्शन रडार,
- मैन-पैक जैमर डिवाइस।
- यह सिस्टम पोर्ट के चारों ओर 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है और 5 किमी तक के क्षेत्र को कवर कर सकता है।

यह सिस्टम किसने लगाया?

- यह सिस्टम वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के साथ मिलकर लगाया है।
- प्रोजेक्ट समझौते पर पोर्ट और CEL के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।

यह पूरी तरह से कब तैयार होगा?

- एंटी-ड्रोन सिस्टम अगले तीन महीनों के भीतर पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है।

भारत ने फाइटर जेट डेवलपमेंट के लिए टाटा, L&T-BEL, और भारत फोर्ज के ग्रुप्स को शॉर्टलिस्ट किया

भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने तीन इंडियन इंडस्ट्री कंटेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया है — टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कंसोर्टियम, और भारत फोर्ज (BEML लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स के साथ) के नेतृत्व वाला एक कंसोर्टियम — भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोग्राम के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन और डेवलप करने के लिए। यह सिलेक्शन सात बिडर्स की स्क्रीनिंग के बाद हुआ है और यह एडवांस्ड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के प्रयास में एक बड़ा कदम है।

एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोग्राम के बारे में

AMCA को पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के रूप में देखा गया है — एक सिंगल-सीट, ट्विन-इंजन एयरक्राफ्ट जिसमें स्टील्थ कोटिंग्स, इंटरनल वेपन बे और एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, जिसका मकसद हाई मैनूवरेबिलिटी और लो डिटेक्टेबिलिटी हासिल करना है। यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) की क्षमताओं को मज़बूत करने और लेटेस्ट कॉम्बैट जेट्स के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर यह सफल रहा, तो भारत F-22 और F-35 (USA), J-20 (चीन), और Su-57 (रूस) जैसे स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स चलाने वाले चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा।

प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का महत्व

AMCA प्रोटोटाइप फेज़ के लिए बड़ी भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्मों को शॉर्टलिस्ट करना, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाने और 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की दिशा में पॉलिसी में बदलाव को दिखाता है। यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जैसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर पारंपरिक निर्भरता से हटकर है – जिसे इस स्टेज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हाई ऑर्डर बुक के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है – जिससे यह भारत के डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम में एक ऐतिहासिक कदम बन गया है।

प्रोजेक्ट टाइमलाइन और स्कोप

शॉर्टलिस्ट किए गए इंडस्ट्री ग्रुप्स को पूरे मैन्युफैक्चरिंग राइट्स दिए जाने से पहले, AMCA के प्रोटोटाइप मॉडल बनाने और टेस्ट करने के लिए सरकारी फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। पहले प्रोटोटाइप अगले कुछ सालों में डेवलप किए जाने हैं, और IAF में ऑपरेशनल जेट्स के 2035 या उसके बाद शामिल होने की उम्मीद है। पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने अकेले प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए ₹15,000 करोड़ के अनुमानित बजट का ज़िक्र किया था।

बड़ा स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कॉन्टेक्स्ट

स्वदेशी फाइटर डेवलपमेंट को मज़बूत करना भारत के अपने आर्म्ड फोर्सेज़ के बड़े मॉडर्नाइज़ेशन का हिस्सा है, जिसमें फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स और इंडियन नेवी के लिए अतिरिक्त P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदना भी शामिल है। भारत की एयर फ़ोर्स बदलते सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाने और इस इलाके में टेक्नोलॉजिकल पैरिटी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। AMCA प्रोजेक्ट डिफेंस में आत्मनिर्भरता हासिल करने में एक अहम पिलर है, जो घरेलू फाइटर जेट इंजन कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने और हाई-एंड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करने जैसी दूसरी पहलों के साथ अलाइन है।

भारत, रूस Su-57 फाइटर जेट के जॉइंट प्रोडक्शन पर बातचीत कर रहे हैं: रिपोर्ट

भारत और रूस भारत में रूसी Su-57E पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट के जॉइंट प्रोडक्शन की संभावना तलाशने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह बात रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) के CEO वादिम बडेखा ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 एयर शो के दौरान कही।

Su-57 फाइटर जेट के बारे में

- Su-57 रूस द्वारा विकसित एक पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे एयर सुपीरियरिटी और मल्टीरोल कॉम्बैट मिशन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- रूस न केवल विमान की सप्लाई की पेशकश कर रहा है, बल्कि भारत में प्रोडक्शन शुरू करने और भारत के अपने फाइटर प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट की संभावना भी दे रहा है।

बातचीत में क्या शामिल है

बातचीत भारत में Su-57E के लाइसेंस्ड और जॉइंट प्रोडक्शन पर केंद्रित है, जिसमें उन सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले से ही रूसी विमान बना रही हैं। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय उद्योग और सिस्टम को प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाए। बातचीत को एक एडवांस्ड टेक्निकल स्टेज में बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक औपचारिक समझौतों की घोषणा नहीं की गई है।

व्यापक संदर्भ और रक्षा निहितार्थ

- भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा संबंध हैं, जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में Su-30MKI जैसे फाइटर जेट का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन शामिल है।
- रूसी टीमों द्वारा पहले किए गए टेक्निकल असेसमेंट से पता चला था कि HAL के पास Su-57 प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी लगभग 50% क्षमता है, लेकिन पूरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपग्रेड की ज़रूरत होगी।
- इस विषय पर बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहा है और अपनी वायु सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है।

यह क्यों मायने रखता है

- अगर सहमति बनती है, तो भारत में Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को काफी बढ़ावा दे सकता है और विदेशी आयात पर निर्भरता कम कर सकता है।
- यह सहयोग संभावित रूप से एडवांस्ड फाइटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है और भारत को जटिल एयरोस्पेस क्षमताएं बनाने में मदद कर सकता है।
- यह भविष्य के पांचवीं पीढ़ी के विमान विकास के लिए एक पुल भी प्रदान कर सकता है, जबकि भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है।

US और फिलीपींस ने डिफेंस पैक्ट को फिर से पक्का किया और सिक्योरिटी रिश्ते मजबूत किए

अमेरिका और फिलीपींस ने मनीला में हाई-लेवल बातचीत के दौरान अपने बाइलेटरल डिफेंस अलायंस को फिर से पक्का किया और मिलिट्री, इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी मामलों पर सहयोग को गहरा करने का वादा किया। यह फिर से पक्का करना दोनों देशों के बीच पक्की पार्टनरशिप को दिखाता है और इंडो-पैसिफिक में, खासकर साउथ चाइना सी के आसपास बढ़ते रीजनल टेंशन के बीच आया है।

म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी (MDT) और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट

U.S. और फिलीपींस के बीच सिक्योरिटी पार्टनरशिप 1951 में साइन की गई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी (MDT) पर आधारित है, जो दोनों देशों को किसी भी सरकार की आर्म्ड फोर्स, एयरक्राफ्ट या पब्लिक वेसल पर बाहरी हथियारबंद हमले की स्थिति में एक-दूसरे की मदद करने के लिए मजबूर करती है। यह ट्रीटी एशिया में सबसे लंबे समय से चले आ रहे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में से एक है और इसने मनीला और वाशिंगटन के बीच लगातार मिलिट्री सहयोग और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की नींव का काम किया है।

सहयोग और कमिटमेंट के मुख्य एरिया

दोनों पक्ष संभावित खतरों, खासकर विवादित समुद्री इलाकों में, को रोकने के लिए मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट एक्सरसाइज और जॉइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने पर सहमत हुए। नेताओं ने इलाके में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए लगातार आर्थिक और डिफेंस सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने साउथ चाइना सी जैसे स्ट्रेटेजिक वॉटरवेज़ में चीन की एक्टिविटीज़ पर भी चर्चा की और आपसी चिंता जताई, और एक फ्री, खुले और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक के लिए सपोर्ट दोहराया।

रीजनल सिक्योरिटी में स्ट्रेटेजिक महत्व

यह पुष्टि ऐसे समय में हुई है जब इंडो-पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, जिसमें नेविगेशन की आज़ादी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और समुद्री इलाकों में इंटरनेशनल लॉ के सम्मान पर फोकस है। U.S. और फिलीपींस ने ताइवान स्ट्रेट में शांति बनाए रखने के महत्व को भी दोहराया है, जो रीजनल सिक्योरिटी के लिए बड़े असर वाला एक मुख्य फ्लैशपॉइंट है।

बेहतर डिफेंस कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स

MDT के अलावा:
बढ़ा हुआ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट (EDCA) (2014) अमेरिका को फिलीपींस में सैनिकों और मिलिट्री एसेट्स को रोटेट करने की इजाज़त देता है, जिससे रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर होती है, साथ ही फिलीपींस की सॉवरेनिटी का भी सम्मान होता है (कोई परमानेंट बेस नहीं बनाया जाता)। विज़िटिंग फोर्सेज़ एग्रीमेंट (VFA) (1999) फिलीपींस में टेम्परेरी तौर पर रहने वाले अमेरिकी मिलिट्री कर्मचारियों के लिए लीगल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग और ड्यूटी अरेंजमेंट को आसान बनाता है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

वायु शक्ति

एक्सरसाइज़ वायु शक्ति क्या है?
एक्सरसाइज़ वायु शक्ति इंडियन एयर फ़ोर्स की एक बड़ी कॉम्बैट ड्रिल है। यह 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण एयर-टू-ग्राउंड रेंज में होगी, जिसकी रिहर्सल 24 फरवरी 2026 को होगी।

यह एक्सरसाइज़ क्यों ज़रूरी है
यह ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाएगी और नेशनल एयरस्पेस पर एयर फ़ोर्स के मज़बूत कंट्रोल को दिखाएगी। यह एयर फ़ोर्स की ज़मीनी सेनाओं के साथ सटीक हमले और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करने की क्षमता को दिखाती है।

एक्सरसाइज़ के दौरान मुख्य डेमोंस्ट्रेशन
सटीक टारगेटिंग, इंडियन आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन और मल्टी-डोमेन वॉरफेयर क्षमता दिखाई जाएगी। मानवीय सहायता और आपदा राहत भूमिकाएँ जैसे बचाव, निकासी और तेज़ी से एयरलिफ्ट भी दिखाई जाएगी। इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन, आकाश मिसाइल, स्पाइडर एयर डिफेंस और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस्ड सिस्टम दिखाए जाएंगे।

हिस्सा लेने वाले और शामिल एसेट्स
इस एक्सरसाइज में 120 से ज़्यादा डिफेंस एसेट्स हिस्सा लेंगे।
इनमें दर्जनों फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। राफेल, सुखोई, मिराज-2000, मिग-29, जगुआर और LCA तेजस जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म हिस्सा लेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्शन
यह एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई ऑपरेशनल सफलता और सटीक क्षमता को दिखाएगी। यह खतरों और आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का साफ संदेश देता है।

खंजर

भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास "खंजर" का 13वां संस्करण 4 फरवरी 2026 को असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हुआ और यह 17 फरवरी 2026 तक चलेगा।

- उद्देश्य: इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य भारत और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्सेज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- स्थान: यह अभ्यास असम के मिसामारी में हो रहा है - जो 2026 में अभ्यास की मेजबानी में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

इतिहास और महत्व:

- अभ्यास खंजर 2011 में शुरू किया गया था और तब से यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम बन गया है, जो गहरे होते रक्षा संबंधों को दर्शाता है।
- यह अभ्यास आमतौर पर भारत और किर्गिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है, जो रक्षा सहयोग के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- पिछला संस्करण: 12वां संस्करण (खंजर-XII) मार्च 2025 में किर्गिस्तान के टोकमोक में आयोजित किया गया था।
- प्रशिक्षण का फोकस: प्रशिक्षण मॉड्यूल में आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के जनादेश ढांचे के तहत शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियान, क्लोज-क्वार्टर बैटल, बिल्डिंग इंटरवेंशन और सामरिक समन्वय अभ्यास शामिल होते हैं।
- स्पेशल फोर्सेज की भागीदारी: पिछले संस्करणों में भारतीय पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज) और किर्गिज़ स्कॉर्पियन ब्रिगेड की भागीदारी देखी गई है, जो उच्च-तीव्रता वाले विशेष अभियानों के प्रशिक्षण को प्रदर्शित करता है।

यह अभ्यास क्यों शुरू किया गया

- आतंकवाद विरोधी सहयोग: दोनों देशों को आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ से खतरा है, खासकर अफगानिस्तान और आस-पास के इलाकों से। यह अभ्यास पहाड़ी और शहरी इलाकों में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है।
- मध्य एशिया में रणनीतिक जुड़ाव: भारत के लिए, मध्य एशिया अफगानिस्तान, यूरेशिया और प्रमुख ऊर्जा मार्गों के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। किर्गिस्तान के साथ सैन्य सहयोग भारत को इस क्षेत्र में सुरक्षा उपस्थिति और साझेदारी बनाए रखने में मदद करता है।
- रक्षा कूटनीति और विश्वास निर्माण: संयुक्त अभ्यास सशस्त्र बलों के बीच आपसी विश्वास, इंटरऑपरेबिलिटी और समझ को बढ़ाते हैं, जिससे लंबे समय तक रक्षा संबंध मजबूत होते हैं।

SAREX

- दक्षिण कोरिया और जापान सैन्य सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने के प्रयासों के तहत, नौ साल के अंतराल के बाद अपने द्विपक्षीय नौसैनिक खोज और बचाव अभ्यास (SAREX) को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
- यह समझौता जापान के योकोसुका में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के बीच बातचीत के दौरान हुआ।
- अभ्यास का उद्देश्य: नौसैनिक खोज और बचाव अभ्यास (SAREX) में दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा समन्वित समुद्री अभ्यास शामिल हैं ताकि जहाज संकट की घटनाओं और समुद्र में मानवीय बचाव अभियानों पर प्रतिक्रियाओं का अभ्यास किया जा सके।

SAREX और सहयोग के बारे में पृष्ठभूमि

- शुरुआत और इतिहास: कोरिया-जापान नौसैनिक SAREX 1999 में शुरू हुआ और 2017 तक नियमित रूप से आयोजित किया गया, जिसके बाद बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। अंतराल से पहले इसे दस बार आयोजित किया गया था।
- यह क्यों रुका: 2018 के रडार लॉक-ऑन विवाद के बाद द्विपक्षीय सैन्य आदान-प्रदान रोक दिए गए थे, जिसमें एक जापानी विमान और एक दक्षिण कोरियाई युद्धपोत के बीच एक विवादास्पद मुठभेड़ हुई थी, जिससे रक्षा सहयोग में तनाव आ गया था।

फिर से शुरू करने का महत्व:

- SAREX को फिर से शुरू करना व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों से खतरों के बीच सियोल और टोक्यो के बीच रक्षा संबंधों में सुधार को दर्शाता है।
- यह कोरिया गणराज्य नौसेना (ROKN) और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और विश्वास को भी मजबूत करता है।

रक्षा सहयोग का व्यापक संदर्भ:

- दक्षिण कोरिया और जापान हाल ही में रक्षा सहयोग को उन्नत करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवरहित प्रणालियों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों पर सहयोग शामिल है।
- दोनों देश अमेरिकी-जापानी-कोरियाई त्रिपक्षीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में सामूहिक रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना है।

MILAN 2026

राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम के समुद्रिका ऑडिटोरियम में MILAN 2026, जो एक बड़ी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, का ऑफिशियली उद्घाटन करेंगे। इस इवेंट में करीब 70 देशों की नेवी एक साथ आ रही हैं।

कहाँ और कब

यह एक्सरसाइज विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड बेस पर हो रही है। उद्घाटन से पहले हार्बर एक्टिविटीज़ शुरू हो गईं, और सी फेज़ 21 फरवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगा।

MILAN 2026 में क्या होगा

इस एक्सरसाइज में हार्बर और सी फेज़ शामिल हैं जो अलग-अलग नेवी के बीच टीमवर्क पर फोकस करते हैं।
इसमें हिस्सा लेने वाली नेवी इन चीज़ों में ड्रिल करेंगी:

- एंटी-सबमरीन वॉरफेयर
- एयर डिफेंस ऑपरेशन
- सर्च-एंड-रेस्क्यू मिशन

इसका मकसद फ्रेंडली नेवी फोर्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को बेहतर बनाना है।

सपोर्टिंग इवेंट्स

फॉर्मल ओपनिंग से पहले, ऑफिसर्स और डेलीगेट्स के लिए दो दिन का इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार होगा। कल्चरल इवेंट्स और इंटरेक्शन स्पेस के साथ विदेशी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करने के लिए एक MILAN विलेज भी बनाया गया था।

इतिहास और ग्रोथ

MILAN 1995 में कुछ रीजनल नेवी के साथ शुरू हुआ था और यह दुनिया की अहम नेवल एक्सरसाइज में से एक बन गया है। पिछले एडिशन मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हुए थे, लेकिन बेहतर फैसिलिटीज़ की वजह से इसे विशाखापत्तनम में शिफ्ट कर दिया गया। 70 देशों के साथ 2026 का एडिशन अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है।

उद्देश्य और महत्व

MILAN 2026 का मकसद फ्रेंडली देशों की नेवी के साथ मजबूत प्रोफेशनल रिश्ते बनाना है। यह नेवल ऑपरेशन्स में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने और समुद्र में कोऑपरेशन बढ़ाने में मदद करता है। यह इवेंट रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और पार्टनरशिप के भारत के विजन को सपोर्ट करता है।

धर्म गार्जियन

भारत और जापान के बीच सालाना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज "धर्म गार्जियन" का 7वां एडिशन 24 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ। यह एक्सरसाइज 9 मार्च 2026 तक चलेगी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक डिफेंस कोऑपरेशन और ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक साथ आएंगे।

एक्सरसाइज के मुख्य उद्देश्य:

- इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JGSDF) के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना।
- सेमी-अर्बन माहौल में जॉइंट ऑपरेशन के लिए मिली-जुली क्षमताओं को मजबूत करना।
- जॉइंट प्लानिंग, टैक्टिकल ड्रिल और मुश्किल मिलिट्री कामों को पूरा करने में सुधार करना।

हिस्सा लेने वाली सेनाएं:

- हर देश से 120 लोगों की एक टीम।
- भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं।
- जापान पक्ष का प्रतिनिधित्व JGSDF की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के लोग कर रहे हैं।

ट्रेनिंग में शामिल मुख्य एक्टिविटीज़:

- एक टेम्परारी ऑपरेटिंग बेस और मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट बनाना।
- एक इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) ग्रिड बनाना।
- घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन, हेलीबोर्न मिशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल करना।

स्ट्रेटेजिक महत्व:

- "धर्म गार्डियन" भारत और जापान में बारी-बारी से होता है और दोनों सेनाओं के बीच डिफेंस कोऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है।
- यह रीजनल सिक्योरिटी में योगदान देता है और भारत-जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को मज़बूत करता है।
- यह एक्सरसाइज दोनों देशों के जॉइंट काउंटर-टेररिज्म और अर्बन कॉम्बैट रेडीनेस स्ट्रेटेजी के कमिटमेंट को दिखाता है।

"धर्म गार्डियन" के बारे में:

- यह एक बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो पहली बार 2018 में भारत और जापान की ज़मीनी सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इस एक्सरसाइज में जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग, सिम्युलेटेड कॉम्बैट सिनेरियो और मॉडर्न टैक्टिकल प्रैक्टिस का एक्सचेंज शामिल है।

वज्र प्रहार

इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज "वज्र प्रहार" का 16वां एडिशन 24 फरवरी 2026 को स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल, बकलोह, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। यह 16 मार्च 2026 तक चलेगा।

एक्सरसाइज का मकसद:

- इंडिया और US के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना।
- स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स की इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना।
- स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक्स, टेक्नीक्स और प्रोसीजर (TTPs) के एक्सचेंज को आसान बनाना।

पार्टिसिपेंट्स:

- इंडियन टुकड़ी में इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेज से लिए गए 45 लोग शामिल हैं।

- US साइड को US आर्मी स्पेशल फोर्सेज (ग्रीन बेरेट्स) के 12 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

ट्रेनिंग फोकस:

- कड़ी फिजिकल कंडीशनिंग और जॉइंट मिशन प्लानिंग।
- पहाड़ी इलाकों में कोऑर्डिनेटेड टैक्टिकल ड्रिल्स।
- बेस्ट प्रैक्टिस और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस शेयर करना।

ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक संदर्भ:

- पहली बार 2010 में हुई, वज्र प्रहार सीरीज़ एक बाइलेटरल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसका मकसद डिफेंस कोऑपरेशन को गहरा करना है।
- पिछला (15वां) एडिशन नवंबर 2024 में USA के इडाहो में हुआ था।
- यह एक्सरसाइज बदलते रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स के बीच भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ती मिलिट्री पार्टनरशिप को हाईलाइट करती है।

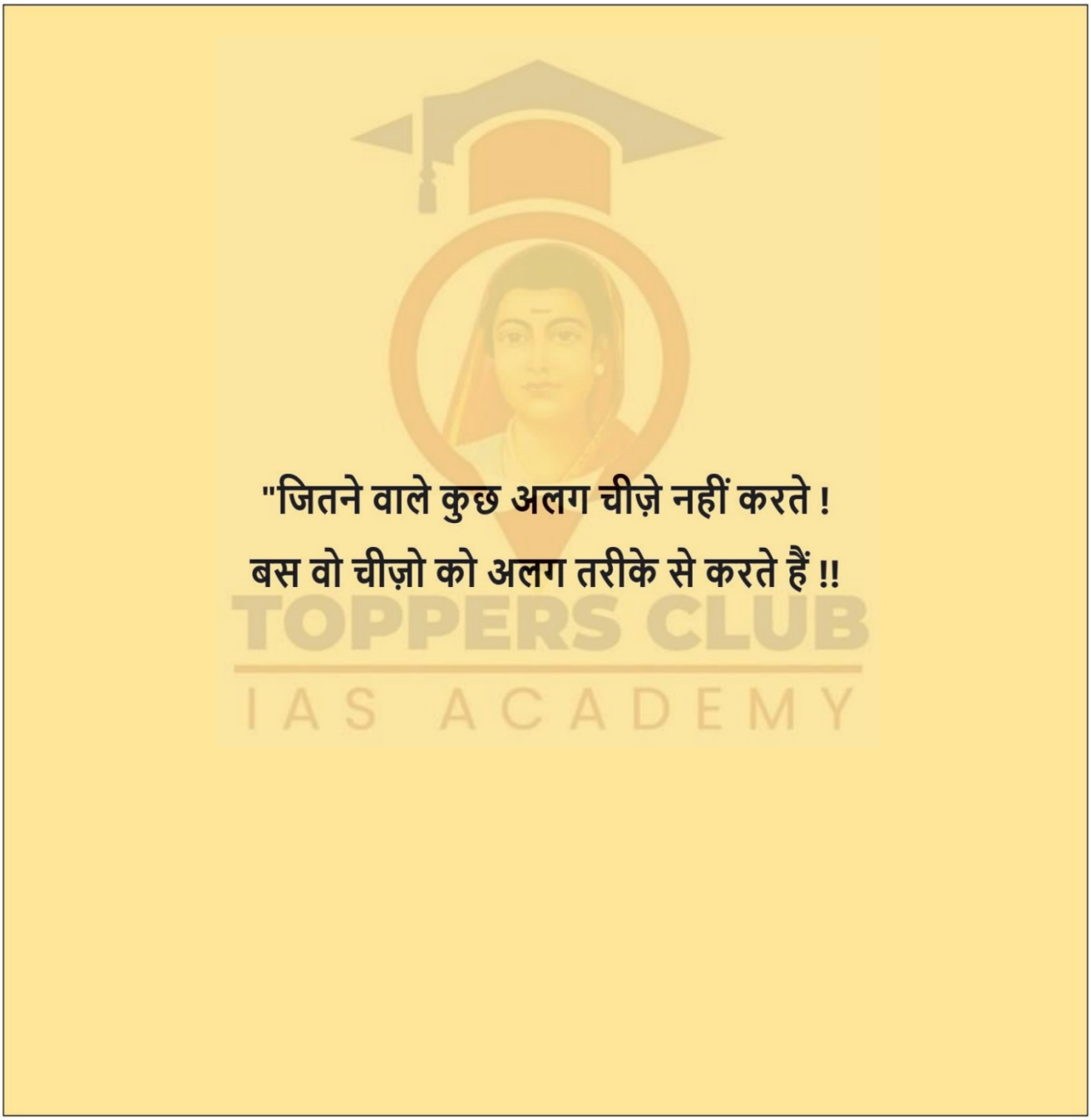

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दी गई एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उसे "दखल देने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला" क्योंकि क्लीयरेंस की शर्तों में "काफी सुरक्षा उपाय" शामिल थे। यह फैसला जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली छह सदस्यों वाली स्पेशल बेंच ने सुनाया।

प्रोजेक्ट के बारे में

यह प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत लगभग ₹80,000-₹90,000 करोड़ है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर लगभग 166 sq km ज़मीन पर फैला है।

इसमें शामिल हैं:

- ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
- इंटीग्रेटेड टाउनशिप
- डुअल-यूज़ (सिविल और मिलिट्री) एयरपोर्ट
- 450-MVA गैस और सोलर पावर प्लांट

NGT की मुख्य वजह

NGT बेंच ने कहा कि पहले से दी गई एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC) में इकोलॉजिकल असर को कम करने के लिए काफी शर्तें थीं। इसने देश के हित में प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर ध्यान दिया, खासकर यह देखते हुए कि आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के पास है — जो दुनिया का एक अहम शिपिंग रूट है। ट्रिब्यूनल ने देखा कि पहले बनी एक्सपर्ट कमेटियों ने उठाई गई चिंताओं की जांच की थी और आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (ICRZ) जैसे ज़रूरी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया था।

एनवायर्नमेंटल और इकोलॉजिकल संदर्भ

ग्रेट निकोबार आइलैंड, सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक है जहाँ पेड़-पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए 130 sq km से ज़्यादा जंगल की ज़मीन को दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत है और इसमें करीब दस लाख पेड़ काटने पड़ सकते हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी के नुकसान की चिंता बढ़ गई है।

आदिवासी समुदायों पर असर

यह आइलैंड निकोबारी और शोम्पेन जैसे आदिवासी ग्रुप्स का घर है, जिन्हें भारत में खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी ग्रुप्स (PVTGs) में बांटा गया है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह प्रोजेक्ट पारंपरिक लाइफस्टाइल, सांस्कृतिक तरीकों और जंगल के संसाधनों तक पहुंच में रुकावट डाल सकता है।

लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क

एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस भारत के एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) प्रोसेस से तय होती है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने से पहले इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक असर का आकलन करती है। आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (ICRZ), 2019 सेंसिटिव कोस्टल इकोसिस्टम की रक्षा करता है; अगर कोई उल्लंघन पता चलता है तो उसे कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। ग्रेट निकोबार केस, डेवलपमेंट की ज़रूरतों को एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन और ट्राइबल राइट्स के साथ बैलेंस करने पर चल रही बहस को दिखाता है — यह भारत में एनवायर्नमेंटल गवर्नेंस में एक बार-बार आने वाला विषय है।

हरियाणा का जंगल सफारी प्रोजेक्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के बड़े जंगल सफारी प्रोजेक्ट को रोक दिया है क्योंकि "अरावली रेंज" की कानूनी परिभाषा पर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है — यह भारत के सबसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाकों में से एक है। यह प्रोजेक्ट हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों में अरावली रेंज की तलहटी में प्रस्तावित था।

जंगल सफारी प्रोजेक्ट क्या है?

2021–22 में शुरू हुए जंगल सफारी (जिसे अरावली ज़ू सफारी भी कहा जाता है) का मकसद अरावली की तलहटी में दुनिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक बनाना था, जो ओरिजिनल 10,000 एकड़ से बदलाव के बाद लगभग 3,000–3,500 एकड़ में फैला होगा। इसे हरियाणा सरकार ने एक कमर्शियल वेंचर के बजाय इको-टूरिज्म, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पहल के तौर पर प्रमोट किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दखल क्यों दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि अरावली को प्रभावित करने वाली कोई भी एक्टिविटी – जिसमें जंगल सफारी प्रोजेक्ट भी शामिल है – तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक "अरावली रेंज" की एक साफ़, एक्सपर्ट-समर्थित परिभाषा तय नहीं हो जाती। 12 फरवरी 2026 को सुनवाई में, कोर्ट ने हरियाणा की उस रिक्वेस्ट को भी मना कर दिया जिसमें एक्सपर्ट के विचार के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जमा करने की बात कही गई थी, और कहा कि वह इस मामले पर तभी फैसला करेगा जब एक आधिकारिक परिभाषा उपलब्ध हो जाएगी। बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया: "हम किसी को भी अरावली को छूने की इजाज़त नहीं देंगे" जब तक कि कोई स्वतंत्र एक्सपर्ट बॉडी इस रेंज को साइंटिफिक रूप से परिभाषित नहीं कर देती।

अरावली की परिभाषा क्यों मायने रखती है

अरावली रेंज भारत के सबसे पुराने फोल्ड पहाड़ों में से एक है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है, और दिल्ली-NCR क्षेत्र में इकोलॉजिकल स्थिरता, ग्राउंडवाटर रिचार्ज और एयर क्वालिटी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई ऑपरेशनल डेफ़िनिशन को स्वीकार किया, जो लोकल रिलीफ़ से 100 मीटर की ऊंचाई वाले लैंडफ़ॉर्म को अरावली हिल मानती है, लेकिन साइंटिस्ट और एनवायरनमेंटलिस्ट ने इस क्राइटेरिया को चुनौती दी है क्योंकि इसमें इकोलॉजिकली ज़रूरी निचली चोटियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने डेफ़िनिशन के मुद्दे पर खुद से संज्ञान लिया है, क्योंकि लोगों के बड़े पैमाने पर विरोध और एनवायरनमेंटल सेफ़्टी के कमज़ोर होने को लेकर एक्सपर्ट्स की चिंताएँ हैं।

- प्रोजेक्ट से जुड़ी एनवायरनमेंटल चिंताएँ: वाइल्डलाइफ़ कॉरिडोर का टूटना: एनवायरनमेंटलिस्ट का तर्क है कि इको-टूरिज़्म प्रोजेक्ट भी तेंदुओं और हिरण जैसी देसी प्रजातियों के हैबिटैट को तोड़ सकते हैं, और बायोडायवर्सिटी को बिगाड़ सकते हैं।
- हाइड्रोलॉजिकल असर: अरावली लैंडस्केप को बिगाड़ने से ग्राउंडवॉटर रिचार्ज ज़ोन पर असर पड़ सकता है, जिससे आस-पास के ज़िलों में पानी की कमी बढ़ सकती है। कानूनी सुरक्षा: यह विवाद कई कानूनों को जोड़ता है, जिसमें वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, और सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) जैसी संस्थाओं द्वारा रेगुलेटरी निगरानी शामिल है।

पटना पक्षी अभयारण्य और छारी-ढांड

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में छारी-ढांड को 31 जनवरी, 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (जो 2 फरवरी को मनाया जाता है) से पहले, आधिकारिक तौर पर भारत की रामसर साइट्स सूची (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) में शामिल किया गया।

इस कदम का महत्व:

- इनके शामिल होने से, भारत में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 98 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति देश की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रामसर पदनाम जैव विविधता संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करता है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

- यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर ईरान के रामसर में (1971 में) हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत 1 फरवरी, 1982 को इसका हस्ताक्षरकर्ता बना और कन्वेंशन के अनुबंधित पक्षों में से एक है।

पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)

यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह अभयारण्य मीठे पानी के दलदल, जंगल और घास के मैदानों में फैला हुआ है, जो आवासों का एक समृद्ध मिश्रण बनाता है। यह 178 पक्षी प्रजातियों और 252 पौधों की प्रजातियों को सहारा देता है, जिसमें प्रवासी जलपक्षी भी शामिल हैं। इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है, खासकर सर्दियों में एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में इसकी भूमिका के कारण। पक्षियों के अलावा, यह चौड़ी थूथन वाले मगरमच्छ (क्षेत्रीय रूप से कमजोर), नीलगाय, सियार, जंगली बिल्ली और मॉनिटर छिपकली जैसी प्रजातियों को भी सहारा देता है। यह स्थानीय इको-टूरिज्म और धार्मिक यात्रा में योगदान देता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक मूल्य बढ़ता है।

छारी-ढांड (गुजरात)

यह कच्छ के बन्नी घास के मैदानों और नमक के मैदानों के बीच स्थित एक मौसमी खारे पानी की आर्द्रभूमि है। मानसून के दौरान इसमें बाढ़ आती है, जो विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति और समृद्ध जैव विविधता को सहारा देती है। यह आर्द्रभूमि जलपक्षियों के सर्दियों में रहने के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ सोशिएबल लैपविंग, कॉमन पोचार्ड और सालाना लगभग 30,000 कॉमन क्रेन जैसी प्रजातियाँ आती हैं। वनस्पति में भारतीय गोंद ट्रैगाकैंथ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय बडेलियम-वृक्ष शामिल हैं। पटना पक्षी अभयारण्य की तरह, इसे भी आक्रामक प्रजातियों और मानवीय गड़बड़ी से पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बहाली और निगरानी के प्रयास जारी हैं।

भारत की रामसर कहानी

- कुल रामसर साइट्स (2026): 98 — 2014 में 26 साइट्स से काफी ज़्यादा (≈ 276% की बढ़ोतरी)।

- रामसर साइट्स वेटलैंड्स की सुरक्षा में मदद करती हैं जो बायोडायवर्सिटी, पानी के रेगुलेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंस और प्रवासी प्रजातियों के गलियारों के लिए इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण हैं।
- विश्व वेटलैंड्स दिवस: वेटलैंड संरक्षण के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है।

नागालैंड में पैंगोलिन के शिकार पर बैन

यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी (USLP), जो संगतम नागा कम्युनिटी की सबसे बड़ी आदिवासी संस्था है, ने एक प्रस्ताव पास किया है **जिससे नागालैंड में उसके इलाके में पैंगोलिन के शिकार पर बैन लग जाएगा। यह इस खतरे में पड़े मैमल को बचाने और गैर-कानूनी वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कम्युनिटी की तरफ से एक बड़ी पहल है।

- पैंगोलिन की प्रजातियां और खतरे: पैंगोलिन, जिन्हें अक्सर "स्केली एंटीईटर्स" कहा जाता है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किए जाने वाले मैमल में से हैं, क्योंकि गैर-कानूनी वाइल्डलाइफ ट्रेड में उनके स्केल्स और मीट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जबकि इनकी कोई साबित मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। इंडियन पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकौडाटा) और चाइनीज़ पैंगोलिन (मैनिस पेंटाडैक्टाइला) दोनों ही खतरे में पड़ी प्रजातियां हैं।
- कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट और पार्टनर: यह बैन वाइल्डलाइफ़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (WTI) के नेतृत्व में पैंगोलिन ट्रैफिकिंग रोकने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन नेटवर्क के पैंगोलिन क्राइसिस फंड ने नागालैंड और पड़ोसी मणिपुर के फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गैर-कानूनी वाइल्डलाइफ़ व्यापार से निपटने के लिए सपोर्ट किया है।
- कम्युनिटी गवर्नेंस और वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट: नागालैंड भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A के तहत काम करता है, जो अपने मूल समुदायों को ज़मीन, जंगल और आम कानूनों पर आज़ादी देता है। इसलिए, कम्युनिटी के नेतृत्व वाले कंज़र्वेशन प्रस्तावों का वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 जैसे राष्ट्रीय कानूनों के साथ-साथ काफ़ी महत्व है, जो लिस्टेड वाइल्डलाइफ़ प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाता है।
- बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट: नागालैंड इंडो-म्यांमार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, जो दुनिया के सबसे अमीर इकोसिस्टम में से एक है, जहाँ अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे और जानवर पाए जाते हैं, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में छेद होने की वजह से यह अवैध शिकार और गैर-कानूनी व्यापार के लिए भी कमज़ोर है।
- आदिवासी समुदायों की भूमिका: नागालैंड में पारंपरिक ग्राम परिषदें और आदिवासी निकाय प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्होंने वन्यजीव संरक्षण का तेज़ी से समर्थन किया है, जो सरकारी नीतियों और लागू करने की कोशिशों में मदद करता है।

असम में बाढ़ और नदी किनारे के कटाव का मैनेजमेंट

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम में बाढ़ मैनेजमेंट और नदी किनारे के कटाव कंट्रोल को मज़बूत करने के लिए USD 182 मिलियन की एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग को मंज़ूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के कमज़ोर इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा। यह लोन चल रहे क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड बाढ़ और नदी किनारे के कटाव रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे असल में अक्टूबर 2023 में मंज़ूरी दी गई थी।

लोन का मकसद

- असम को बार-बार प्रभावित करने वाली गंभीर बाढ़ और नदी किनारे के कटाव से निपटने की क्षमता बढ़ाना।
- ब्रह्मपुत्र के चार और हाई-प्रायोरिटी वाले इलाकों में इंटीग्रेटेड बाढ़ और कटाव रिस्क मैनेजमेंट उपायों को बढ़ाना।
- गांवों की रोज़ी-रोटी की रक्षा करना, गरीबी कम करना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विस्थापन को रोकना।
- स्ट्रक्चरल, अडैप्टिव और नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन को मिलाकर रिस्क-इन्फॉर्म्ड तरीकों को मज़बूत करना।

बढ़ाए गए प्रोजेक्ट की खास बातें

- एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग: USD 182 मिलियन (मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लगभग ₹1,500+ करोड़)।
- कुल प्रोजेक्ट साइज़: पिछले ADB सपोर्ट और राज्य के योगदान को मिलाकर लगभग USD 487 मिलियन।

असम को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है

असम का ब्रह्मपुत्र बेसिन हर साल बाढ़ और नदी के किनारे के बहुत ज़्यादा कटाव के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जिससे जान-माल का नुकसान होता है, खेती की ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, और लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। पुराने डेटा से पता चलता है कि बड़े टेक्टोनिक बदलावों (जैसे, 1950 का असम भूकंप) के बाद से नदी चौड़ी हो गई है, जिससे कटाव और बाढ़ की घटनाएं तेज हो गई हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ की फ्रीक्वेंसी और गंभीरता बढ़ जाती है।

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ

मेरी रसोई योजना

भगवंत मान की पंजाब सरकार ने 'मेरी रसोई योजना' शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA)/स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 40 लाख परिवारों को अप्रैल 2026 से हर तीन महीने में मुफ़्त फ़ूड किट मिलेंगी। इस स्कीम का मकसद राज्य भर में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की फ़ूड और न्यूट्रिशन की कमी को दूर करना है।

स्कीम के हिस्से और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान

योग्य लाभार्थी (NFSA के तहत नीले कार्ड होल्डर) को अप्रैल 2026 से हर तीन महीने (अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर) में फ़ूड किट मिलेंगी।

हर तीन महीने की किट में ये चीज़ें होंगी:

2 kg चना/दालें
2 kg चीनी
1 kg आयोडीन वाला नमक
200 g हल्दी पाउडर
1 लीटर सरसों का तेल

ये किट NFSA के तहत पहले से दिए जा रहे सब्सिडी वाले गेहूं के अलावा होंगी।

लागू करने का तरीका

मार्कफेड (पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन) फ़ूड किट को इकट्ठा करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। फ़ूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी कंट्रोल की देखरेख करेगा, यह पक्का करेगा कि किट मुफ़्त में डिलीवर हों और स्टैंडर्ड के हिसाब से हों।

खाने की चीज़ों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाए रखने के लिए समय-समय पर क्वालिटी की कड़ी जांच की जाएगी।

फाइनेंशियल कमिटमेंट

इस स्कीम में पूरे राज्य में फ़ूड किट खरीदने और बांटने में मदद के लिए लगभग ₹950 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA), 2013 के बारे में

NFSA का मकसद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के ज़रिए सही मात्रा और क्वालिटी का खाना सस्ते दामों पर उपलब्ध कराकर फ़ूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना है। NFSA के तहत, गांव की 75% आबादी और शहर की 50% आबादी राशन कार्ड के ज़रिए सब्सिडी वाला अनाज (खासकर चावल और गेहूं) पाने की हकदार है। इस स्कीम में मैटरनिटी हक और बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और दूध पिलाने वाली मांओं के लिए कुपोषण कम करने के लिए खास इंतज़ाम भी शामिल हैं।

PM RAHAT स्कीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए PM RAHAT (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइज़ेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट) स्कीम शुरू की।

- उद्देश्य: रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को समय पर और सस्ती इमरजेंसी मेडिकल केयर देना और इलाज में देरी से होने वाली मौतों को कम करना।
- कवरेज: एलिजिबल पीड़ितों को एक्सीडेंट की तारीख से सात दिनों के टाइम के लिए हर एक्सीडेंट पर ₹1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा।

स्टेबिलाइज़ेशन केयर:

- जिन चोटों से जान को खतरा न हो, उनके लिए 24 घंटे तक।
- जान को खतरा वाले मामलों के लिए 48 घंटे तक।
- इंप्लीमेंटेशन: तेज़ी से हॉस्पिटल में भर्ती होने और डिजिटल ऑथेंटिकेशन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS 112) से जुड़ा, पुलिस, हॉस्पिटल और अधिकारियों के बीच आसान कोऑर्डिनेशन के लिए eDAR और TMS 2.0 प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना। रीइंबर्समेंट: हॉस्पिटल को पेमेंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड (MVAF) से किया जाएगा; इंश्योर्ड गाड़ी के मामलों में, इंश्योरेंस कंपनियां कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि सरकार हिट-एंड-रन या बिना इंश्योर्ड मामलों को कवर करती है।
- समय पर पेमेंट: हॉस्पिटल के लिए फाइनेंशियल निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए अप्रूव्ड क्लेम को स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा 10 दिनों के अंदर सेटल किया जाना है।

- शिकायत का समाधान: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली रोड सेफ्टी कमेटियों के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल सिस्टम।

याद रखने योग्य बिंदु

- कैशलेस ट्रीटमेंट: मरीज़ को बिना पहले पेमेंट किए दी जाने वाली मेडिकल केयर, जिसका बिल सीधे स्कीम में जाएगा।
- गोल्डन आवर: किसी गंभीर चोट के बाद पहले 60 मिनट, जो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट से जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
- इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS 112): पूरे भारत में एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर जो दुर्घटना की रिपोर्टिंग और अस्पताल तक पहुँच को जोड़ता है।
- मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड (MVAF): इस स्कीम के तहत दुर्घटना के शिकार लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों को रीइंबर्स करने के लिए डेडिकेटेड फंड।

नए सेवा तीर्थ ऑफिस से चार बड़ी स्कीम को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के नए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया – जिसमें अब प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO), नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हैं – और वहां अपने पहले दिन, महिलाओं, किसानों, एक्सीडेंट केयर और स्टार्टअप्स को टारगेट करते हुए चार बड़ी स्कीम को मंज़ूरी दी।

चार खास फैसले मंज़ूर

1. PM राहत स्कीम की शुरुआत: सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इमरजेंसी इलाज देती है ताकि पैसे की देरी या तुरंत देखभाल की कमी से होने वाले जान के नुकसान को कम किया जा सके। समाज के सभी वर्गों के लिए इमरजेंसी हेल्थकेयर कवरेज को मज़बूत करने का मकसद।
2. लखपति दीदी पहल का विस्तार: लखपति दीदी (सेल्फ-हेल्प ग्रुप के ज़रिए सालाना ₹1 लाख या उससे ज़्यादा कमाने वाली महिलाएं) का टारगेट मार्च 2029 तक 3 करोड़ से दोगुना करके 6 करोड़ कर दिया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम।
3. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ावा: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एलोकेशन ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है। किसानों के लिए स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग और कटाई के बाद के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है।
4. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0: शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स, खासकर डीप टेक, इनोवेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को फंड करने के लिए ₹10,000 करोड़ के कॉर्पस को मंजूरी दी गई। युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने की कोशिश।

सेवा तीर्थ – नया PMO कॉम्प्लेक्स

सेवा तीर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में एक अहम मॉडर्नाइजेशन कदम है, जो बेहतर कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी के लिए बड़े ऑफिसों को एक छत के नीचे लाता है। यह नाम सरकार के "सेवा" (पब्लिक सर्विस) पर फोकस को दिखाता है।

स्कीम के बारे में

- PM RAHAT: इमरजेंसी केयर और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों से जुड़ा है।
- लखपति दीदी: सरकार के ग्रामीण आजीविका और महिलाओं के नेतृत्व वाले माइक्रो एंटरप्राइज लक्ष्यों को सपोर्ट करता है।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: खेती की वैल्यू चेन को मजबूत करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की लंबे समय की कोशिशों का हिस्सा।
- स्टार्टअप इंडिया फंड: यह इनोवेशन इकोसिस्टम ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए, ग्लोबल स्टार्टअप हब के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की लीडरशिप में दिल्ली कैबिनेट ने "मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम" को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद खादी, हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्री और अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर जैसे सेक्टर में कारीगरों और पारंपरिक काम करने वालों को मज़बूत बनाना है।

इसका फ़ायदा किसे होगा:

मुख्य फ़ायदों में दर्जी, कढ़ाई करने वाले, कुम्हार, बढ़ई, मोची, टोकरी बनाने वाले, बांस के कारीगर, बुनकर और दूसरे पारंपरिक कारीगर और महिलाएं शामिल हैं, खासकर वे जो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं।

लागू करना और ट्रेनिंग:

इसे दिल्ली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड (DKVIB) के ज़रिए लागू किया जाएगा। इसमें 96 घंटे (12 दिन) की स्ट्रक्चर्ड स्किल ट्रेनिंग शामिल है, साथ ही दो दिन का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (EDP) भी होगा। हर एक पर ध्यान देने के लिए ट्रेनिंग बैच में 35–45 लोग होंगे।

फाइनेंशियल मदद:

लाभार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान खाने के लिए ₹4,800 (₹400/दिन) का स्टाइपेंड और ₹100/दिन मिलते हैं। उन्हें ज़रूरी टूलकिट भी दिए जाते हैं, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर पैर से चलने वाली सिलाई मशीनें भी शामिल हैं।

मार्केट लिंकेज और सर्टिफिकेशन:

हर पार्टिसिपेंट की प्रोफ़ाइल और प्रोडक्ट डिटेल्स को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म पर ई-कैटलॉग के ज़रिए डिजिटली ऑनबोर्ड किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट सहित बड़े मार्केट तक पहुंच बनाई जा सके। इस स्कीम में कारीगरों के हुनर को फॉर्मल तौर पर सर्टिफाई करने के लिए पहले सीखी गई चीज़ों की पहचान (RPL) और MSME/उद्यम रजिस्ट्रेशन, ब्रांडिंग सपोर्ट और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच के लिए मदद शामिल है।

बजट एलोकेशन:

2025–26 के लिए, 3,728 लाभार्थियों को ₹8.95 करोड़ के अप्रूव्ड खर्च से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कीम को बढ़ाने के लिए 2026–27 के लिए ₹57.50 करोड़ का बड़ा खर्च प्रस्तावित है।

केरल NPS की जगह एश्योर्ड पेंशन स्कीम लाएगा

केरल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह एक नई एश्योर्ड पेंशन स्कीम लाने का फैसला किया है। यह घोषणा वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने विधानसभा में केरल राज्य बजट 2026-27 पेश करते समय की।
जो कर्मचारी NPS में रहना चाहते हैं, वे उसमें रह सकते हैं; नई पेंशन योजना में जाना वैकल्पिक होगा।

एश्योर्ड पेंशन स्कीम का क्या मतलब है

नई योजना के तहत, रिटायर सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% तक पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन राशि में महंगाई राहत (DR) भी शामिल होगी। सरकार और कर्मचारियों दोनों के योगदान को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। विस्तृत दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2026 तक जारी होने की उम्मीद है।

केरल बजट में अन्य प्रमुख घोषणाएँ

- केरल के बजट में कल्याण पेंशन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए ₹14,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- एक 12वां वेतन संशोधन आयोग बनाया जाएगा; इसकी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर आने की उम्मीद है।
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सभी लंबित महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया दो किस्तों में - फरवरी और मार्च की सैलरी के साथ - क्लियर किए जाएंगे।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस फिर से शुरू किया जाएगा।

प्रतिक्रियाएँ और संदर्भ

- बजट में लोकप्रिय कल्याणकारी उपाय शामिल हैं जैसे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों में वृद्धि।
- विपक्षी नेताओं ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसे आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और केरल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे अवास्तविक बताया।

केरल

- गठन: 1 नवंबर 1956
- राजधानी: तिरुवनंतपुरम
- जिले: 14
- राज्यपाल: राजेंद्र अर्लेकर
- मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन
- मुख्य सचिव: ए. जयतिलक

नमो लक्ष्मी योजना

गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि वह 2025-26 एकेडमिक वर्ष में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 12 लाख से ज़्यादा छात्राओं को सपोर्ट करने के लिए ₹1,250 करोड़ आवंटित करेगी — यह एक वित्तीय सहायता पहल है जिसका मकसद प्राइमरी शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने

की दर को कम करना है, लड़कियों को सेकेंडरी (कक्षा IX-X) और हायर सेकेंडरी (कक्षा XI-XII) स्कूली शिक्षा के माध्यम से सहायता देकर।

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय बाधाएं लड़कियों की प्राइमरी स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने में रुकावट न बनें और राज्य में महिला साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

योजना के मुख्य प्रावधान:

- प्रति छात्र कुल सहायता: चार साल में (कक्षा IX-XII) ₹50,000 तक।
- कक्षा IX-X के लिए: कुल ₹20,000 की सहायता, जिसमें शामिल हैं:
- हर साल 10 महीने के लिए ₹500 प्रति माह (₹5,000 प्रति वर्ष)
- कक्षा X बोर्ड परीक्षा पास करने पर ₹10,000 का बोनस। कक्षा XI–XII के लिए: कुल ₹30,000 की सहायता, जिसमें शामिल हैं:
- हर साल 10 महीनों के लिए ₹750 प्रति माह
- कक्षा XII बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद ₹15,000 का बोनस।
- पात्रता: वे लड़कियाँ जिन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग पूरी कर ली है और मान्यता प्राप्त स्कूलों (गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड या CBSE) में पढ़ रही हैं, जिसमें ₹6 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी (प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए)।
- यह योजना दूसरी सरकारी स्कॉलरशिप की पूरक है (उन्हें बदलती नहीं है) — दूसरी स्कॉलरशिप के लाभार्थी भी नमो लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उत्पत्ति और बजट संदर्भ:

- नमो लक्ष्मी योजना की घोषणा गुजरात बजट 2025–26 के हिस्से के रूप में की गई थी, जहाँ राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को मज़बूत करने के लिए इस पहल के लिए विशेष रूप से ₹1,250 करोड़ आवंटित किए।

तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट

तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट क्या है?

तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट एक नेविगेशन लॉक-कम-कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसे उत्तरी जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर वुलर झील के आउटलेट पर प्रस्तावित किया गया है। इसका मकसद पानी के बहाव को रेगुलेट करना है ताकि नदी में साल भर नेविगेशन (नावों की आवाजाही) के लिए काफी गहराई बनी रहे, खासकर सूखे सर्दियों के महीनों में। इस बैराज से बाढ़ कंट्रोल, सेडिमेंट मैनेजमेंट और डाउनस्ट्रीम बिजली बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद थी।

प्रोजेक्ट का इतिहास

यह आइडिया पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में आया था, और काम 1984 में शुरू हुआ था। हालांकि, इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) पार्टनर पाकिस्तान की लगातार आपत्तियों के बाद कि यह स्ट्रक्चर ट्रीटी का उल्लंघन कर सकता है, 1987/1988 में कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था। इस वजह से, यह प्रोजेक्ट लगभग चार दशकों तक रुका रहा।

प्रोजेक्ट क्या करेगा

यह वुलर झील से पानी के बहाव को कंट्रोल करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि झेलम नदी में नावों के लिए साल भर काफी गहराई रहे। इससे नदी ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, डाउनस्ट्रीम में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन बेहतर हो सकता है, और कश्मीर घाटी में वॉटर मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है।

रेगुलेटेड पानी छोड़ने से सेडिमेंट बिल्ड-अप को कम करने और नदी की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है।

इसे क्यों रोका गया

पाकिस्तान ने तर्क दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से IWT का उल्लंघन हो सकता है, जो यह रेगुलेट करता है कि भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी सिस्टम के पानी को कैसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद का मानना था कि तुलबुल स्ट्रक्चर एक स्टोरेज फैसिलिटी की तरह काम कर सकता है और डाउनस्ट्रीम पानी के फ्लो को प्रभावित कर सकता है, जो ट्रीटी के तहत ज़्यादातर पाकिस्तान को दिया जाता है। हालांकि, भारत ने तर्क दिया कि इस प्रोजेक्ट में नेविगेशन जैसा नॉन-कंजम्पटिव इस्तेमाल शामिल है, जिसकी IWT के तहत इजाज़त है, और पाकिस्तान प्रोजेक्ट से असली नुकसान नहीं दिखा सका।

हाल के डेवलपमेंट

पहलगाम टेरर अटैक के बाद अप्रैल 2025 में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद, जम्मू और कश्मीर सरकार ने तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिशें फिर से शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार दशकों की देरी के बाद प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के साथ काम कर रही है। उनका कहना है कि ट्रीटी के रुकने से इस इलाके की नेविगेशन, हाइड्रोपावर और वॉटर मैनेजमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से आगे बढ़ने का मौका मिलता है।

यह इंडस वॉटर्स ट्रीटी (IWT) से कैसे जुड़ा है

1960 की इंडस वॉटर्स ट्रीटी, इंडस बेसिन की नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। भारत पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलुज) को कंट्रोल करता है और पाकिस्तान पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को कंट्रोल करता है, जिसमें भारत के पास पश्चिमी नदियों पर नॉन-कंजम्प्शनल इस्तेमाल के लिए लिमिटेड अधिकार हैं। भारत ने अक्सर कहा है कि तुलबुल प्रोजेक्ट उन अधिकारों में फिट बैठता है, लेकिन पाकिस्तान के एतराज़ों ने सालों तक प्रोग्रेस को रोक दिया। ट्रीटी के हालिया सस्पेंशन ने डिप्लोमैटिक कॉन्टेक्स्ट को बदल दिया है।

तुलबुल प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है

प्रोजेक्ट के फिर से शुरू होने से J&K में रिवर नेविगेशन खुल सकता है, बोट ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म शुरू हो सकता है, और लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। यह डाउनस्ट्रीम हाइड्रोपावर जेनरेशन को बेहतर बना सकता है और झेलम बेसिन में वॉटर मैनेजमेंट को बेहतर बना सकता है। इस प्रोजेक्ट का एक सिंबॉलिक महत्व है क्योंकि यह एक लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा रीजनल डेवलपमेंट का काम है, जो इंटरनेशनल वॉटर पॉलिटिक्स की वजह से रुका हुआ है।

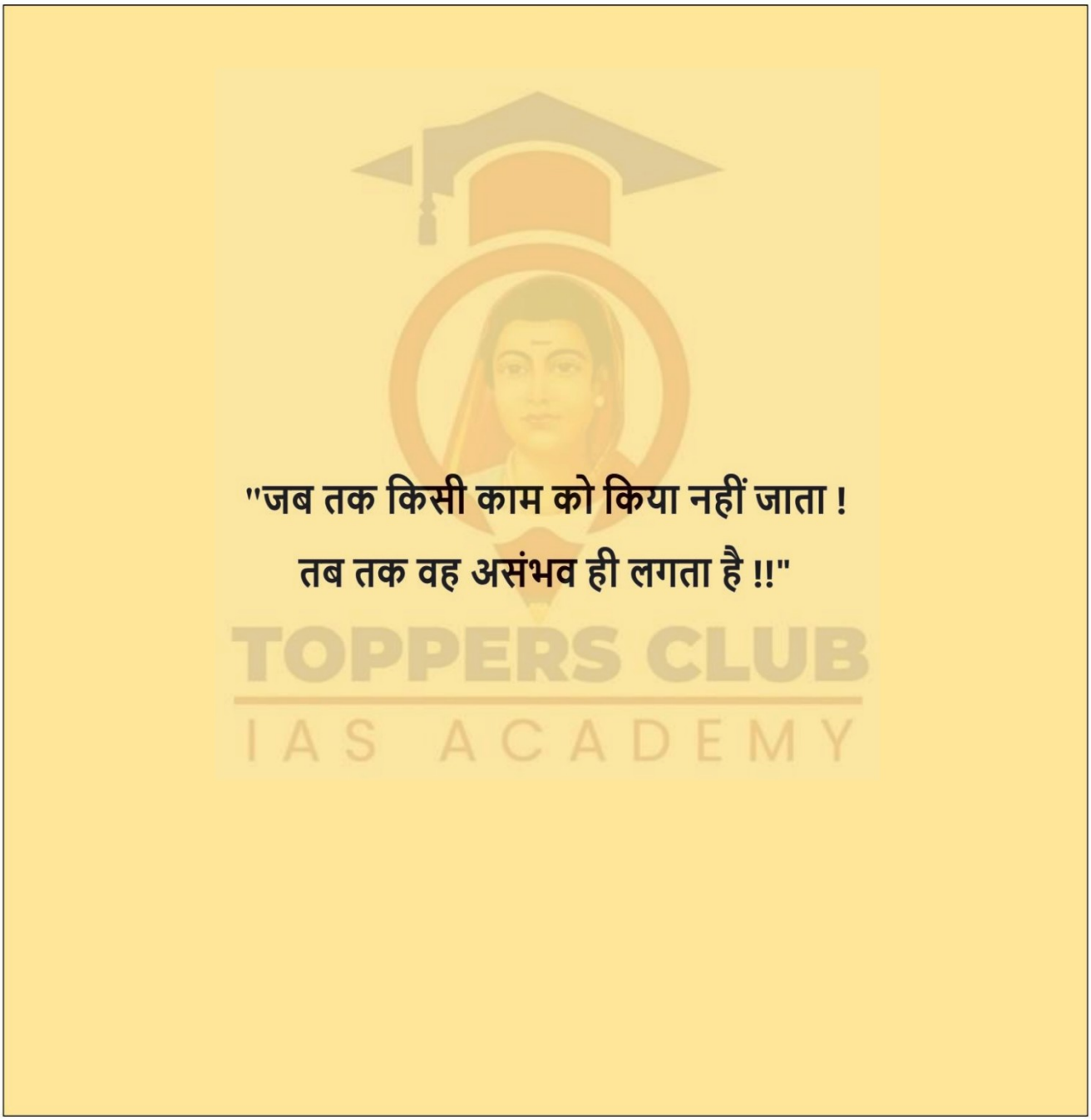

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन-ट्रेडिंग प्रोग्राम

भारत अपने पहले कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन-ट्रेडिंग प्रोग्राम को लागू करने को फाइनल कर रहा है, जो FY 2025-26 के समय के लिए इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ के बीच कार्बन एमिशन को मॉनिटर करने और ट्रेड करने के लिए देश के क्लाइमेट पॉलिसी फ्रेमवर्क में एक बड़ा कदम है। प्रोग्राम ने हिस्सा लेने वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए एमिशन टारगेट जारी करना शुरू कर दिया है और 2026 के आखिर में क्रेडिट जारी करने और ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा है।

कार्बन-ट्रेडिंग स्कीम की खास बातें

प्रोग्राम का स्ट्रक्चर:

इस स्कीम में नौ सेक्टर्स में 800 यूनिट्स को कवर करने वाला एक ज़रूरी कम्प्लायंस कम्पोनेंट और एक वॉलंटरी ऑफसेट कम्पोनेंट शामिल है। इन कम्पोनेंट्स में कार्बन क्रेडिट अलग-अलग जारी और ट्रेड किए जाएंगे।

नोटिफिकेशन और कवरेज:

अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 में ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के ज़रिए सात सेक्टर्स में लगभग 490 यूनिट्स के लिए एमिशन टारगेट जारी किए गए थे। यह शुरुआती ग्रुप भारत के लगभग 20% इंडस्ट्रियल एमिशन को कवर करता है।

फेज़-I में शामिल नहीं:

- स्टील और फर्टिलाइज़र सेक्टर – बड़े इंडस्ट्रियल एमिटर – को अभी तक एमिशन टारगेट नहीं मिले हैं, जिससे उन्हें शामिल करने में देरी हो रही है।
- पावर सेक्टर, जो भारत का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, पहले फेज़ का हिस्सा नहीं है।

टाइमलाइन:

- पहला कम्प्लायंस साइकिल 31 मार्च 2026 तक चलेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन और असेसमेंट फेज़ होंगे।
- कार्बन क्रेडिट अक्टूबर 2026 तक जारी होने की उम्मीद है, और ट्रेडिंग नवंबर 2026 और जनवरी 2027 के बीच होने की संभावना है।

प्राइस सेटिंग:

कार्बन कॉस्ट टारगेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कीमतें USD 10 प्रति टन CO_2 के आसपास रहें, जिससे इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस और क्लाइमेट इंसेंटिव को बैलेंस किया जा सके।

BIRAC–RDI फंड

BIRAC–RDI फंड क्या है?

भारत सरकार ने ₹2,000 करोड़ के BIRAC–RDI फंड के लिए पहली नेशनल कॉल शुरू की है। यह फंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत ₹1 लाख करोड़ के बड़े रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देना है।

फंड क्यों बनाया गया

BIRAC–RDI फंड का मकसद रिसर्च को असली प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में बदलने में मदद करना है — खासकर बायोटेक्नोलॉजी जैसे कटिंग-एज एरिया में। इसका मकसद लैब डिस्कवरी और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के बीच के गैप को कम करना है, ऐसे आइडिया को सपोर्ट करना जो उम्मीद जगाने वाले हैं लेकिन अकेले प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए बहुत रिस्की हो सकते हैं।

इसे कौन मैनेज करेगा

फंड को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) मैनेज करेगी। फाइनेंसिंग के लिए BIRAC को "सेकंड-लेवल फंड मैनेजर" बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यह तय करेगा कि किन प्रोजेक्ट्स और कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा।

फंड कैसे काम करेगा

₹2,000 करोड़ पांच साल तक खर्च किए जाएंगे, और भविष्य में रकम बढ़ाने का ऑप्शन भी है। यह डेवलपमेंट के ऊंचे स्टेज पर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा — मिड-लेवल प्रोटोटाइप टेस्टिंग से लेकर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार होने तक (आमतौर पर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से 9 के बीच)।

फंडिंग इक्विटी, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स और लॉन्ग-टर्म डेट जैसे टूल्स के ज़रिए दी जाएगी, जिससे रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन और स्टार्टअप दोनों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

सपोर्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है

स्टार्टअप, छोटे और मीडियम एंटरप्राइज (SME), इंडस्ट्री पार्टनर और हाई-इम्पैक्ट बायोटेक आइडिया पर काम करने वाले रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रपोज़ल के लिए पहली कॉल अभी खुली है, और फेज़ 1 एप्लीकेशन की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 है।

यह भारत के लिए क्यों ज़रूरी है

यह फंड भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के ग्रोथ इंजन के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़े पुश का संकेत देता है। भारत का बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम 2014 में लगभग 50 कंपनियों से बढ़कर 2026 तक 11,000 से ज़्यादा हो गया है। बायोइकॉनमी तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुँच गई है, और सरकार का लक्ष्य आने वाले दशक में और भी ऊँचे टारगेट तक पहुँचना है। इस कदम से भारत लाइफ साइंसेज, बायोमैन्युफैक्चरिंग और नए ज़माने की टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल दावेदार के तौर पर उभर रहा है।

लंबे समय का विज़न

अधिकारियों का कहना है कि यह फंड भारतीय रिसर्च को इंडस्ट्रियलाइज़ करने में मदद करेगा, न कि सिर्फ़ एकेडमिक स्टडीज़ को बढ़ावा देगा। यह बायोएनर्जी, बायोइंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा, एडवांस्ड कंप्यूटेशन और यहाँ तक कि स्पेस बायोटेक जैसे उभरते हुए क्षेत्रों को भी सपोर्ट करता है, जिससे भारत की साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल क्षमताएँ बढ़ेंगी।

भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी

IIT मद्रास में इनक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप, ePlane कंपनी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी e200x पर काम करने के लिए NVIDIA के साथ हाथ मिलाया है।

कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी?

ePlane, e200x एयरक्राफ्ट का डिजिटल ट्विन बनाने के लिए NVIDIA Omniverse का इस्तेमाल करेगा। डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल है जो कंप्यूटर सिमुलेशन में असली एयरक्राफ्ट के बिहेवियर को कॉपी करता है। इसका इस्तेमाल करके, इंजीनियर वर्चुअल दुनिया में फ्लाइट फिजिक्स, सेंसर और ऑटोनॉमस सिस्टम को सुरक्षित रूप से टेस्ट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट में NVIDIA IGX भी होगा, जो ज़रूरी फ्लाइट सॉफ्टवेयर और सेंसर चलाने के लिए एक पावरफुल ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम है।

प्रोजेक्ट का लक्ष्य

यह पार्टनरशिप शहर के ट्रैफिक को कम करने और तेज़, साफ यात्रा ऑप्शन देने के लिए अर्बन एयर मोबिलिटी सॉल्यूशन बनाने का हिस्सा है।

कुल असर

यह कोलेबोरेशन भारत के डीप-टेक एविएशन फील्ड में एडवांस्ड सिमुलेशन टूल्स और AI कंप्यूटिंग लाता है। यह डिजिटल सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी डेवलपमेंट में ePlane को लीडर बनाता है।

NVIDIA

- CEO: जेन्सेन हुआंग
- स्थापना: 5 अप्रैल 1993
- मुख्यालय: कैलिफ़ोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स
- अध्यक्ष: जेन्सेन हुआंग

देसी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (Td) वैक्सीन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने ऑफिशियली देश में बनी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (Td) वैक्सीन लॉन्च की। यह लॉन्च हिमाचल प्रदेश के कसौली में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRI) में हुआ।

लॉन्च की गई वैक्सीन का नाम

लॉन्च की गई वैक्सीन टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (Td) वैक्सीन है। यह पहले की टेटनस टॉक्सॉइड (TT) वैक्सीन की जगह लेती है, जो सिर्फ टेटनस से बचाती थी।

यह लॉन्च क्यों ज़रूरी है

यह वैक्सीन भारत में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सरकार के हेल्थ और दवाओं में भारत को आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर भारत) बनाने के लक्ष्य में मदद करती है।

वैक्सीन क्या करती है

Td वैक्सीन टेटनस और डिप्थीरिया — दो गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचाती है। यह अब भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) में शामिल है ताकि सभी उम्र के लोगों को बचाने में मदद मिल सके।

प्रोडक्शन और सप्लाई

सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRI) अप्रैल 2026 तक UIP के तहत वैक्सीन की लगभग 55 लाख (5.5 मिलियन) डोज़ सप्लाई करेगा। आने वाले सालों में प्रोडक्शन और बढ़ने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलिया-इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड

इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया-इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड (AISRF) के राउंड 16 के तहत पांच जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स फाइनल किए हैं, जिससे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आपसी सहयोग मजबूत होगा।

प्रोजेक्ट्स में शामिल मुख्य एरिया:

पांचों प्रोजेक्ट्स स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर-ओरिएंटेड डोमेन में फैले हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग
2. क्वांटम टेक्नोलॉजी
3. एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग
4. क्लाइमेट-रेसिलिएंट एग्रीकल्चर
5. सेलुलर इम्यूनोथेरेपी (हेल्थ और बायोटेक)

ऑस्ट्रेलिया-इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड (AISRF) के बारे में

AISRF ऑस्ट्रेलिया सरकार और भारत सरकार के बीच एक बाइलेटरल रिसर्च पार्टनरशिप है, जिसे 2006 में मिलकर साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाइलेटरल साइंस और रिसर्च प्रोग्राम है, और 2026 तक इसकी 20वीं एनिवर्सरी होगी। यह फंड भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूशन के बीच मिलकर रिसर्च ग्रांट, रिसर्चर फेलोशिप, लोगों के एक्सचेंज और जॉइंट इनोवेशन इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है।

हेल्थ AI इकोसिस्टम के लिए SAHI और BODH लॉन्च

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इंडिया AI समिट 2026 में दो बड़े नेशनल इनिशिएटिव — SAHI (भारत के लिए हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्ट्रैटेजी) और BODH (हेल्थ AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म) लॉन्च करने की घोषणा की। इन इनिशिएटिव का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ज़िम्मेदारी से और सबूतों के आधार पर अपनाकर भारत के हेल्थ सेक्टर को मज़बूत करना है।

SAHI – भारत के लिए हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्ट्रैटेजी

- मकसद: हेल्थकेयर में AI के नैतिक, सुरक्षित, सबको साथ लेकर चलने वाले और सबूतों के आधार पर इस्तेमाल को गाइड करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है।
- स्कोप: इसमें हेल्थ सिस्टम में AI टूल्स के डेटा स्टीवर्डशिप, वैलिडेशन, इस्तेमाल, गवर्नेंस और मॉनिटरिंग के लिए गाइडलाइन शामिल हैं।
- लक्ष्य: राज्यों और हेल्थकेयर संस्थानों को AI को ऐसे तरीकों से अपनाने में मदद करना जो पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकताओं के साथ मेल खाते हों और हेल्थकेयर डिलीवरी को मज़बूत करें।

BODH – हेल्थ AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म

इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर (IIT कानपुर) ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया है।

- काम: एक प्राइवेसी बनाए रखने वाला बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म जो बिना अंदरूनी डेटासेट शेयर किए, अलग-अलग रियल-वर्ल्ड डेटा का इस्तेमाल करके हेल्थ AI मॉडल्स को इवैल्यूएट करता है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पर, इसका मकसद AI हेल्थ सॉल्यूशंस में भरोसा, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ाना है।

इंडिया AI समिट 2026

इंडिया AI समिट एक अहम सरकारी प्लेटफॉर्म है जो गवर्नेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सहित नेशनल डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल और इम्पैक्ट पर फोकस करता है। यह पॉलिसीमेकर्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को अलग-अलग सेक्टर्स में AI अपनाने पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स

एक डिजिटल पब्लिक गुड एक ओपन-सोर्स टूल, डेटा सेट, स्टैंडर्ड या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को मानता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देता है। BODH जैसे फ्रेमवर्क पब्लिक हेल्थ में ज़िम्मेदार AI को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल कोशिशों (जैसे, WHO डिजिटल हेल्थ गाइडलाइंस) के साथ अलाइन होते हैं।

AI गवर्नेंस और एथिक्स

SAHI, AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर सरकार के बढ़ते फोकस को दिखाता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और फायदेमंद AI डिप्लॉयमेंट जैसे प्रिंसिपल शामिल हैं।

इसी तरह के गवर्नेंस स्ट्रक्चर OECD AI प्रिंसिपल्स और AI की एथिक्स पर UNESCO की रिकमेंडेशन जैसी इंटरनेशनल पहलों का हिस्सा हैं।

अग्नि-III इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-III इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) का सफल परीक्षण किया। यह लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की देखरेख में किया गया और इसने मिसाइल सिस्टम के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वेरिफाई किया।

परीक्षण की मुख्य बातें

- इस परीक्षण ने अग्नि-III मिसाइल की ऑपरेशनल तैयारी और विश्वसनीयता को दिखाया।
- यह भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।
- मिसाइल सिस्टम की निगरानी एडवांस्ड रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन, रडार और टेलीमेट्री सिस्टम द्वारा की गई।

अग्नि-III मिसाइल के बारे में

- प्रकार: इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM)
- रेंज: ~3,000–3,500 किमी
- स्टेज: दो-स्टेज, सॉलिड-फ्यूल से चलने वाली
- पेलोड क्षमता: परमाणु और पारंपरिक हथियार
- गाइडेंस सिस्टम: उच्च सटीकता वाला इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम (INS)
- ऑपरेटर: स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड
- डेवलपर: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)

रणनीतिक महत्व

- अग्नि-III भारत के भूमि-आधारित परमाणु प्रतिरोधक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह विस्तारित रणनीतिक पड़ोस में खतरों को रोकने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह मिसाइल भारत के विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक और पहले इस्तेमाल न करने (NFU) के परमाणु सिद्धांत का समर्थन करती है।
- इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR), ओडिशा
- ओडिशा के चांदीपुर में स्थित।
- DRDO द्वारा प्रबंधित।
- मिसाइलों, रॉकेटों, UAVs और रक्षा प्रणालियों के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।

अग्नि मिसाइल श्रृंखला – संक्षिप्त अवलोकन

- अग्नि-I: शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
- अग्नि-II: मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
- अग्नि-III: इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
- अग्नि-IV और अग्नि-V: लंबी दूरी की / इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास मिसाइलें

NEONSAT-1A

दक्षिण कोरिया ने 2027 तक पृथ्वी की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की अपनी योजना के तहत सफलतापूर्वक एक नैनोसेटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। इस लॉन्च की पुष्टि कोरिया एयरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (KASA) ने की।

सैटेलाइट और लॉन्च के बारे में

सैटेलाइट का नाम NEONSAT-1A है, यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन नैनोसेटेलाइट है जिसे कोरियाई प्रायद्वीप और आस-पास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे अमेरिकी स्पेस कंपनी रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह लॉन्च न्यूजीलैंड के माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से हुआ।

कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य

- NEONSAT-1A उन 11 नैनोसेटेलाइट्स में से दूसरा है जिन्हें पूरा कॉन्स्टेलेशन बनाने के लिए प्लान किया गया है।

- पूरा होने के बाद, यह सैटेलाइट नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने, पृथ्वी की हाई-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें लेने और दक्षिण कोरिया के लिए निगरानी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- इस प्रोजेक्ट में KAIST (कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी) सहित कई संस्थान शामिल हैं जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में योगदान दे रहे हैं।
- इसे कोरियाई सरकार के विज्ञान और ICT मंत्रालय (MSIT) द्वारा फंड दिया जाता है।

पिछला लॉन्च और भविष्य की योजनाएँ

- इस प्रोजेक्ट का पहला सैटेलाइट, NEONSAT-1, पहले अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था।
- इस अकेले लॉन्च से कॉन्स्टेलेशन अभी पूरा नहीं होगा - 2027 तक योजना के हिस्से के रूप में और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे।

AI-डिज़ाइन वायरस "Evo-Φ2147"

वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके लैब में एक बिल्कुल नया वायरस (जिसका नाम Evo-Φ2147 है) डिज़ाइन और बनाया है। यह वायरस प्रकृति में मौजूद नहीं है और इसे पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं के बजाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बनाया गया है।

कहाँ और किसने?

यह रिसर्च अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया के पालो ऑल्टो में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की।

मुख्य नतीजे:

AI ने बैक्टीरियोफेज टेम्प्लेट से प्रेरित 285 अनोखे वायरल जीनोम बनाए। इनमें से 16 वायरस ने लैब टेस्ट में एस्चेरिचिया कोलाई (E. coli) बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से संक्रमित किया और मार दिया। सबसे प्रभावी डिज़ाइन अपने प्राकृतिक समकक्षों की तुलना में बैक्टीरिया को संक्रमित करने में लगभग 25% तेज़ी से काम करते थे।

यह कैसे किया गया?

वैज्ञानिकों ने वायरस जीनोम बनाने के लिए खरबों DNA बेस पेयर पर प्रशिक्षित एक उन्नत AI सिस्टम का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने एक तेज़, उच्च-सटीक तरीके का इस्तेमाल करके लैब में इन जीनोम को इकट्ठा किया।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- बैक्टीरियोफेज क्या हैं? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया को मारने की अपनी क्षमता के लिए उनका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है और उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के संभावित विकल्प माना जाता है, खासकर एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ।
- यह दवा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? AI के साथ वायरस डिज़ाइन करने की क्षमता फेज थेरेपी के विकास को तेज़ कर सकती है, जिससे बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के नए तरीके मिल सकते हैं जो अब पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
- विज्ञान और AI का मिलन: यह सफलता जैविक अनुसंधान में जेनरेटिव AI की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जहाँ AI मॉडल अब सिर्फ डेटा का विश्लेषण करने के बजाय पूरे कार्यात्मक आनुवंशिक अनुक्रम उत्पन्न कर सकते हैं।
- बायोसिक्योरिटी और नैतिक चिंताएँ: हालांकि Evo-Φ2147 बैक्टीरिया को टारगेट करता है और इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दुरुपयोग या खतरनाक रोगजनकों के आकस्मिक निर्माण को रोकने के लिए सख्त बायोसिक्योरिटी नियमों और नैतिक निगरानी की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
- दोहरे उपयोग वाली तकनीक का जोखिम: जैविक अनुक्रमों को डिज़ाइन करने में सक्षम AI सिस्टम दोहरे उपयोग के जोखिम पैदा करते हैं - जिसका मतलब है कि अगर ऐसी तकनीक को ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया तो इसका इस्तेमाल हानिकारक परिणामों के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए मज़बूत बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। समकालीन शोध चेतावनी देता है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

अन्य प्रमुख खबरें

भाभा, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, 1955: AI में भारत के लिए क्या करें और क्या न करें

AI की तुलना 1955 की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी से क्यों करें?

भारत नई दिल्ली में एक बड़ा AI समिट होस्ट कर रहा है। यह कोल्ड वॉर (1955) के दौरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अनुभव से सबक लेता है ताकि यह पता चल सके कि भारत को आज AI को कैसे हैंडल करना चाहिए।

1955 में जिनेवा में क्या हुआ था?

1955 में, डॉ. होमी जे. भाभा ने जिनेवा में एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर पहले UN कॉन्फ्रेंस में भारत को लीड किया। भारत ने डेवलपिंग देशों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक सहयोग और शांतिपूर्ण पहुंच पर ज़ोर दिया। भाभा चाहते थे कि भारत अपनी साइंटिफिक ताकत बनाए और इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग करे।

न्यूक्लियर युग से सबक

भारत ने देश में न्यूक्लियर नॉलेज बढ़ाई और साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप भी मांगी। बाद में, भारत ने न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में अपनी रफ़्तार खो दी क्योंकि उसने फोकस और स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी बनाए नहीं रखी। यह इतिहास दिखाता है कि सिर्फ़ गुडविल या यूनिवर्सल सहयोग पर निर्भर रहना सफलता की गारंटी नहीं है।

AI के लिए भारत को क्या करना चाहिए

आर्टिकल में तीन खास काम सुझाए गए हैं:

- नेशनल AI की ताकत बढ़ाएं
- कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं।
- रिसर्च और ट्रेनिंग बढ़ाएं।
- AI ग्रोथ के लिए साफ और सपोर्टिव नियम।
- एडवांस्ड देशों के साथ पार्टनरशिप करें
- यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे टेक लीडर्स के साथ कोलेबोरेशन जारी रखें।
- सिर्फ एक ग्रुप के साथ नहीं, बल्कि कई देशों के साथ रिश्ते खुले रखें।

ग्लोबल AI नियमों को सही तरीके से बनाएं

ग्लोबल गवर्नेंस की बहसों में एक्टिव रोल निभाएं। भारत का योगदान सिर्फ आइडियल्स पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित हो।

पिछली गलतियां न दोहराएं

भारत को ग्लोबल आइडियल्स और नेशनल इंटरेस्ट के बीच कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। मकसद पहले मजबूत डोमेस्टिक AI कैपेबिलिटी बनाना होना चाहिए, फिर इसका इस्तेमाल भारत और पूरी दुनिया दोनों के फायदे के लिए करना चाहिए। डोमेस्टिक डेवलपमेंट में सफलता दूसरे डेवलपिंग देशों की भी मदद कर सकती है।

आसान शब्दों में

कोल्ड वॉर की न्यूक्लियर कहानी सिखाती है कि घर पर ताकत + स्मार्ट ग्लोबल कोऑपरेशन = सफलता। AI में भारत का भविष्य अपनी स्किल्स और टेक को बढ़ाने, विदेश में समझदारी से पार्टनरशिप करने और ग्लोबल लेवल पर सही AI नियमों को बनाने में मदद करने पर निर्भर करता है।

भारत के IT सेक्टर में AI, ऑटोमेशन और "SaaSpocalypse"

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन में तेज़ी से हो रही तरक्की के साथ, भारत के बड़े इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) और बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) सेक्टर में नौकरियां जाने और स्ट्रक्चरल रुकावट की चिंता है। "SaaSpocalypse" शब्द का इस्तेमाल नौकरियों के बड़े पैमाने पर खत्म होने, खासकर रूटीन कोडिंग और बार-बार होने वाले कामों को बताने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि AI से चलने वाले टूल और प्लेटफॉर्म पारंपरिक काम की जगह ले रहे हैं। यह बहस AI अपनाने से जुड़े आर्थिक मौकों और सामाजिक जोखिमों पर रोशनी डालती है।

मुख्य कॉन्सेप्ट समझाए गए

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन

AI का मतलब है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो ऐसे काम कर सकते हैं जिनमें आम तौर पर इंसानी समझ की ज़रूरत होती है, जैसे सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और फैसले लेना। ऑटोमेशन का मतलब है बिना इंसानी दखल के काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। AI से चलने वाला ऑटोमेशन आसान नियम-आधारित कामों से लेकर एडवांस्ड कॉग्निटिव कामों तक हो सकता है। IT सेक्टर में, इनमें ऑटोमेटेड कोड लिखना, टेस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट बॉट और AI से चलने वाला डेटा एनालिसिस शामिल हैं।

SaaSpocalypse

SaaS (Software as a Service) और एपोकैलिप्स का मिला-जुला रूप है, जो इस डर की ओर इशारा करता है कि स्केलेबल AI और क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स बड़ी संख्या में IT जॉब्स खत्म कर सकते हैं। इसमें यह आइडिया शामिल है कि AI टूल्स (जैसे, जेनरेटिव AI) को बड़े पैमाने पर अपनाने से कई रूटीन IT फंक्शन बेकार हो सकते हैं।

भारत के IT सेक्टर के लिए यह क्यों मायने रखता है

एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर: भारत की IT और BPM इंडस्ट्रीज़ लाखों वर्कर्स को नौकरी देती हैं, खासकर बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे पहले के ग्रोथ हब में। इस वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा रूटीन और बार-बार होने वाले कामों में लगा हुआ है—ठीक वही काम जो AI ऑटोमेशन

के लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। आर्थिक योगदान: IT सेक्टर भारत की GDP और एक्सपोर्ट अर्निंग्स में एक बड़ा योगदान देता है, जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ एक्सपोर्ट कुल सर्विस एक्सपोर्ट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाता है। यह इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इफ़ेक्ट्स के ज़रिए रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सहायक सेक्टर्स को सपोर्ट करता है।

रिस्क के बीच मौके

AI जॉब क्रिएटर के तौर पर: भले ही AI कुछ रोल की जगह ले रहा है, लेकिन यह नई जॉब बनाता है जिनके लिए AI रिसर्च, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और सिस्टम आर्किटेक्चर में हायर-ऑर्डर स्किल्स की ज़रूरत होती है। वर्कफोर्स को भविष्य के रोल में बदलने में मदद करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस: AI इंटीग्रेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लागत कम कर सकता है और सर्विस क्वालिटी में सुधार कर सकता है, जिससे ग्लोबल IT मार्केट में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।

चुनौतियाँ और पॉलिसी का असर

- स्किल मिसमैच: मौजूदा वर्कफोर्स स्किल्स और AI से चलने वाली जॉब्स के लिए ज़रूरी स्किल्स के बीच एक गैप है, जिसके लिए एजुकेशन रिफॉर्म, इंडस्ट्री-एकेडमिक कोलेबोरेशन और बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है।
- इनकम में असमानता: अगर ऑटोमेशन को ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो यह एंट्री-लेवल जॉब्स पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है, इनकम में असमानता बढ़ा सकता है और सामाजिक कमज़ोरियों को बढ़ा सकता है।
- रेगुलेटरी और एथिकल फ्रेमवर्क: सरकारों और इंडस्ट्री बॉडीज़ को AI डिप्लॉयमेंट के लिए एथिकल चिंताओं, डेटा प्राइवेसी और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स (इंडिया)

- नेशनल AI स्ट्रैटेजी: इंडिया की नेशनल AI पॉलिसी हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और गवर्नेंस पर फोकस करते हुए वर्कफोर्स ट्रांज़िशन को बैलेंस करते हुए इनक्लूसिव AI एडॉप्शन पर ज़ोर देती है।

तिरुमाला मंदिर में इस्तेमाल की जा रही 'ई-नोज़' और 'ई-टंग' टेक क्या हैं?

तिरुमाला में नई फ़ूड टेस्टिंग लैब

आंध्र प्रदेश सरकार भक्तों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी पक्का करने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में एक मॉडर्न फ़ूड टेस्टिंग लैब बना रही है। इस प्रोजेक्ट का खर्च लगभग ₹25 करोड़ है।

लैब की ज़रूरत क्यों है

यह कदम मिलावटी घी और प्रसाद (पवित्र भोजन) बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को लेकर चिंताओं के बाद उठाया गया है। लैब का मकसद खाने की सुरक्षा को मज़बूत करना, लोगों का भरोसा वापस लाना और क्वालिटी को ज़्यादा असरदार तरीके से मॉनिटर करना है।

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी: ई-नोज़ और ई-टंग

लैब में इलेक्ट्रॉनिक नोज़ (ई-नोज़) और इलेक्ट्रॉनिक टंग (ई-टंग) मशीनें होंगी। ये मशीनें सेंसर-बेस्ड टूल हैं जो खाने की गंध और स्वाद की प्रोफ़ाइल की जांच करती हैं ताकि गंदगी या क्वालिटी में बदलाव का पता लगाया जा सके। ई-नोज़ खुशबू और वोलाटाइल कंपाउंड को एनालाइज़ करता है, जबकि ई-टंग स्वाद से जुड़े केमिकल कॉम्पोनेंट की जांच करता है। दोनों सिस्टम स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोफ़ाइल वाले सैंपल की तुलना करने के लिए पैटर्न-रिकग्निशन सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं।

वे कैसे काम करते हैं

ई-नोज़ गैस सेंसर का इस्तेमाल करता है जो खराब गंध या मिलावट का पता लगाने के लिए वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करते हैं। ई-टंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का इस्तेमाल करता है जो स्वाद पर असर डालने वाले केमिकल पर रिएक्ट करते हैं। दोनों डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल और AI मॉडल का इस्तेमाल करके प्रोसेस करते हैं ताकि खाने की क्वालिटी को क्लासिफ़ाई किया जा सके। साथ में, वे ट्रेडिशनल लैब टेस्ट की तुलना में मिलावट या खराबी का तेज़ी से पता लगाने में मदद करते हैं।

क्या टेस्ट किया जाएगा

लैब प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले लगभग 60 रॉ मटीरियल की जांच करेगी, जिसमें घी, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, चीनी और भी बहुत कुछ शामिल है। यह पानी और तैयार प्रसादम में पेस्टिसाइड के बचे हुए हिस्से, माइक्रोब्स, हेवी मेटल्स और दूसरी मिलावटों का भी टेस्ट कर सकता है। यह फ़ैसिलिटी रोज़ाना की टेस्टिंग के लिए लगभग 50 एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेंड स्टाफ़ का इस्तेमाल करेगी।

इन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे

ये सिस्टम खाने की क्वालिटी को बिना इंसानी टेस्टिंग के तेज़ी से और ऑटोमैटिकली चेक करने में मदद करते हैं। ये खाना सर्व करने से पहले क्वालिटी की दिक्कतों को पकड़ने के लिए शुरुआती स्क्रीनिंग टूल के तौर पर काम कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी मंदिर में रेगुलर क्वालिटी मॉनिटरिंग में एक्यूरेसी और स्पीड जोड़ती है।

संस्कृति एवं इतिहास

चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल

माउंट फ़ूजी के पास चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कैंसिल कर दिया गया जापान ने 2026 के लिए अरकुरायामा सेंगेन पार्क में होने वाला सालाना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कैंसिल कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला टूरिस्ट की गलत हरकतों और ओवरटूरिज्म की वजह से लिया गया है।

फेस्टिवल कहाँ और क्या था

यह फेस्टिवल माउंट फ़ूजी के पास फ़ूजीयोशिदा में 10 साल से ज़्यादा समय तक होता रहा। हर बसंत में चेरी ब्लॉसम और सुंदर नज़ारे देखने के लिए लाखों विज़िटर यहाँ आते थे।

इसे क्यों कैंसिल किया गया

स्थानीय लोगों ने टूरिस्ट के खराब व्यवहार की शिकायत की।

अधिकारियों ने इन समस्याओं की रिपोर्ट की:

विज़िटर द्वारा छोड़ी गई गंदगी और कचरा।
प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना इजाज़त घुसना।
टूरिस्ट का निजी घरों में घुसना या रोकी गई जगहों पर घूमना।
स्थानीय सरकार ने कहा कि इन समस्याओं से लोगों की शांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खतरा है।

ओवरटूरिज्म का असर

माउंट फ़ूजी और फेस्टिवल की जगह बहुत पॉपुलर हो गई, कुछ हद तक सोशल मीडिया और आसान ट्रैवल की वजह से।
ज़्यादा भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम और सेफ्टी की चिंताएँ हुईं, खासकर लोकल बच्चों और कम्युनिटीज़ के लिए।

अब क्या होगा

हालांकि ऑफिशियल फेस्टिवल नहीं होगा, लेकिन अरकुरायामा सेंगेन पार्क और चेरी ब्लॉसम स्प्रिंग के दौरान विज़िटर्स को दिखाई देंगे। लोकल अथॉरिटीज़ विज़िटर्स को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, टेम्पररी टॉयलेट और पार्किंग जैसे क्राउड मैनेजमेंट के तरीके लागू कर सकती हैं।

आगे का रास्ता:

भीड़ को कंट्रोल करें: विज़िटर्स की लिमिट तय करें और पीक सीज़न के दौरान एडवांस बुकिंग का इस्तेमाल करें। सख्ती से लागू करना: कूड़ा फेंकने, बिना इजाज़त घुसने और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाना। अवेयरनेस ड्राइव: टूरिस्ट को लोकल कल्चर और ज़िम्मेदार व्यवहार के बारे में एजुकेट करें। बेहतर सुविधाएं: ज़्यादा टॉयलेट, डस्टबिन, पार्किंग और सिक्योरिटी स्टाफ़ लगाएं। स्थानीय लोगों की सुरक्षा करें: पक्का करें कि टूरिज़्म से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई दिक्कत न हो।

मिस्र की वैली ऑफ़ द किंग्स में भारतीय भाषा के शिलालेख

एक खास आर्कियोलॉजिकल खोज में, **रिसर्चर्स ने मिस्र में वैली ऑफ़ द किंग्स में चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरों के अंदर तमिल-ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत में लिखे शिलालेखों को डॉक्यूमेंट किया है। ये शिलालेख, जो पहली से तीसरी सदी CE के हैं, उनमें ग्रीक ग्रैफ़िटी के साथ खुदे हुए भारतीय नाम शामिल हैं — जो कॉमन एरा की शुरुआती सदियों के दौरान लाल सागर के ट्रेड हब से दूर अंदरूनी इलाकों में भारतीय यात्रियों की मौजूदगी का इशारा करते हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ

- वैली ऑफ़ द किंग्स: लक्सर के पास थेबन नेक्रोपोलिस का एक हिस्सा, यह वैली लगभग 16वीं से 11वीं सदी BCE तक मिस्र के राजघरानों का मुख्य दफ़नाने का इलाका था। UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचानी जाने वाली इस जगह में बड़े-बड़े हाइरोग्लिफ़ और दफ़नाने की चीज़ें वाली कब्रें हैं।
- शिलालेख: तमिल-ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत में लगभग 30 शिलालेख रिकॉर्ड किए गए थे — ये भाषाएँ/लिपियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुईं। उदाहरणों में सिकाई कोर्रान और कोपन जैसे नाम शामिल हैं, जो दक्षिण भारतीय (तमिल) और उत्तर-पश्चिमी भारतीय मूल के लगते हैं।

लिपियों की व्याख्या

- तमिल-ब्राह्मी: तमिल लिपि का एक शुरुआती रूप जो ब्राह्मी वर्णमाला से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल तीसरी शताब्दी BCE से किया जाता था, जो दक्षिण भारत में शुरुआती साक्षरता का अहम सबूत देता है।

- संस्कृत और प्राकृत: क्लासिकल और मध्य भारतीय भाषाएँ, जो प्राचीन भारत और मध्य एशिया में साहित्य, व्यापार और धार्मिक ग्रंथों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती थीं।

खोज का महत्व

इंडो-रोमन व्यापार संबंध

शिलालेख शुरुआती शताब्दियों CE में बड़े पैमाने पर इंडो-रोमन समुद्री व्यापार के सबूत देते हैं। प्लिनी द एल्डर और टॉलेमी जैसे क्लासिकल रोमन लेखकों ने भूमध्यसागरीय बाज़ारों में मसाले, कपड़े, हाथी दांत और रत्न जैसे भारतीय आयातों का ज़िक्र किया है। इंडियन एक्सपोर्ट शायद बेरेनिके जैसे मिस्र के पोर्ट तक पहुँचता था और फिर यात्रियों या व्यापारियों के ज़रिए देश के अंदर तक फैल जाता था।

कल्चरल मोबिलिटी

ग्रीक ग्रैफ़िटी के साथ इंडियन नामों का होना कई दिशाओं में यात्रा का संकेत देता है — सिर्फ़ व्यापार ही नहीं, बल्कि शायद कल्चरल लेन-देन और तीर्थयात्रा भी। यह दिखाता है कि कैसे इंडियन व्यापारी और विज़िटर पुरानी दुनिया के बड़े कॉस्मोपॉलिटन नेटवर्क में शामिल थे।

इतिहास और आर्कियोलॉजी के लिए बड़े असर

- पुराना ग्लोबलाइज़ेशन: यह खोज दिखाती है कि पुराना ग्लोबलाइज़ेशन सिर्फ़ सामान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कॉन्टिनेंट के पार आइडिया, भाषा का कॉन्टैक्ट और पर्सनल मोबिलिटी भी शामिल थी।
- इंडियन इंटरेक्शन का रीअसेसमेंट: सबूत पुराने विचारों को चुनौती देते हैं कि इंडिया के शुरुआती बाहरी कॉन्टैक्ट ज़मीनी बॉर्डर तक ही सीमित थे; इसके बजाय, यह दूर तक फैले समुद्री और अंदरूनी कनेक्शन को दिखाता है।

केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंज़ूरी

भारत की यूनियन कैबिनेट ने केरल राज्य का ऑफिशियल नाम बदलकर "केरलम" करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस फ़ैसले से राज्य का नाम बदलने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू हो गया है।

कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस:

- कैबिनेट ने केरल (नाम बदलने) बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है।
- भारत के प्रेसिडेंट पहले इस बिल को केरल लेजिस्लेटिव असेंबली को उनकी राय के लिए भेजेंगे, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत ज़रूरी है।
- असेंबली की राय के बाद, बिल को मंज़ूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।
- संसद से पास होने और प्रेसिडेंट की मंज़ूरी मिलने के बाद, नाम बदलने को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल में ऑफिशियली लागू कर दिया जाएगा।

बदलाव का कारण:

- केरलम नाम राज्य के ओरिजिनल मलयालम उच्चारण और कल्चरल पहचान से मेल खाता है।
- केरल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहले इस बदलाव के सपोर्ट में एक प्रस्ताव पास किया था, पहले अगस्त 2023 में, और फिर जून 2024 में यूनियन होम मिनिस्ट्री के सुझाव के अनुसार टेक्निकल बदलावों के साथ। सपोर्ट करने वालों का कहना है कि केरलम मलयालम बोलने वाले लोगों की भाषाई विरासत और इतिहास को दिखाता है।

पॉलिटिकल और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अहमियत:

- यह नाम बदलाव 2026 में केरल असेंबली इलेक्शन से पहले हुआ है, जिससे यह पॉलिटिकली अहम फैसला बन गया है।
- इस फैसले को केरल में दोनों पार्टियों का बड़ा सपोर्ट मिला है, जिसमें अलग-अलग पॉलिटिकल लाइन के नेताओं का सपोर्ट भी शामिल है, जिनका कहना है कि यह कल्चरल जड़ों का सम्मान करता है।

संविधान का आर्टिकल 3:

- संसद को नए राज्य बनाने, मौजूदा राज्यों के एरिया, बाउंड्री या नाम बदलने का अधिकार देता है, लेकिन सिर्फ राज्य लेजिस्लेचर की राय मिलने के बाद।
- राष्ट्रपति को बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले राज्य लेजिस्लेचर की राय के लिए भेजना होगा।

संविधान का पहला शेड्यूल:

- भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके ऑफिशियल नामों से लिस्ट करता है।
- राज्य के नामों में किसी भी बदलाव के लिए संविधान के इस हिस्से में बदलाव की ज़रूरत होती है।

2026 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स (BAFTAs)

79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स (BAFTAs) को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए, जिसमें पिछले साल रिलीज़ हुई फिल्मों के लिए ग्लोबल सिनेमा में बेहतरीन काम को पहचान दी गई। इस सेरेमनी को एलन कमिंग ने होस्ट किया था और इसमें फिल्म, एक्टिंग, टेक्निकल और स्पेशल अचीवमेंट कैटेगरी के अलग-अलग विनर्स शामिल थे।

मेजर विनर्स और हाइलाइट्स

- बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर: वन बैटल आफ्टर अनदर शाम की सबसे बड़ी विनर बनी, जिसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर (पॉल थॉमस एंडरसन), बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (शॉन पेन) समेत छह अवॉर्ड मिले।
- बेस्ट लीडिंग एक्टर: रॉबर्ट अरामायो ने आई स्वियर के लिए जीता, साथ ही EE राइजिंग स्टार अवॉर्ड (पब्लिक-वोटेड) भी मिला।
- बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म: जेसी बकले ने हैमनेट के लिए लीडिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता, जिसने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी जीता। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: सिनर्स ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (वुन्मी मोसाकू), बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले (रायन कूगलर) के लिए तीन अवॉर्ड जीते।

टेक्निकल और दूसरी फ़िल्म कैटेगरी:

फ्रेंकस्टीन ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, मेकअप और हेयर, और प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवॉर्ड जीता। मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवॉर्ड मिला। सेंटिमेंटल वैल्यू ने फ़िल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज का अवॉर्ड जीता। ज़ूट्रोपोलिस 2 ने बेस्ट एनिमेटेड फ़िल्म का अवॉर्ड जीता।

- आउटस्टैंडिंग डेब्यू: माई फादर्स शैडो ने ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का आउटस्टैंडिंग डेब्यू अवॉर्ड जीता।
- बच्चों और फ़ैमिली फ़िल्म: मणिपुरी फ़िल्म बूंग ने बेस्ट बच्चों और फ़ैमिली फ़िल्म का अवॉर्ड जीता, जो BAFTA में इंडियन रीजनल सिनेमा के लिए एक हिस्टोरिक जीत है।
- स्पेशल अवॉर्ड: BAFTA फ़ेलोशिप — एकेडमी का सबसे बड़ा अवॉर्ड — डेम डोना लैंगली को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए दिया गया, जबकि क्लेयर बिन्स को सिनेमा में आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड मिला।

अतिरिक्त तथ्य:

- BAFTA अवार्ड्स: ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स सबसे जाने-माने इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में से एक हैं, जिन्हें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स हर साल फिल्म, टेलीविजन और गेम्स में शानदार कामों को पहचानने के लिए देता है। इन्हें अक्सर एकेडमी अवार्ड्स (ऑस्कर) का एक अहम हिस्सा माना जाता है।
- EE राइजिंग स्टार अवार्ड: यह कैटेगरी अकेला BAFTA अवार्ड है जिसे जनता वोट करती है, जिसका मकसद उभरते हुए एक्टर्स और परफॉर्मर्स को पहचान देना है।

भव्य भारत भूषण अवॉर्ड्स 2026

कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में ईशा महाशिवरात्रि 2026 के सेलिब्रेशन के दौरान, स्पिरिचुअल लीडर सद्गुरु ने भव्य भारत भूषण अवॉर्ड्स लॉन्च किए। यह एक नया नेशनल सम्मान है जो कई क्षेत्रों में भारत की तरक्की में शानदार योगदान को पहचान देता है। ये अवॉर्ड्स भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साइंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, डिफेंस और कम्युनिटी डेवलपमेंट में खास कामयाबी हासिल करने वालों को दिए। इस इवेंट में स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को नेशनल पहचान के साथ मिलाया गया।

भव्य भारत भूषण अवॉर्ड के बारे में

भव्य भारत भूषण अवॉर्ड एक नया शुरू किया गया सम्मान है जो उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है जिनके जीवन भर के काम और लगन ने भारत के विकास और कल्चरल रिचनेस में अहम योगदान दिया है। इसका उद्देश्य इस बात को मज़बूत करना है कि देश बनाना लोगों से चलता है, न कि सिर्फ़ पॉलिसी या भूगोल से।

मौका और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट

ये अवॉर्ड्स महाशिवरात्रि के दौरान दिए गए, जो भगवान शिव को समर्पित एक बड़ा हिंदू त्योहार है, जिसे हर साल पूरे भारत में स्पिरिचुअल गैदरिंग के साथ मनाया जाता है।

खास अवॉर्ड पाने वाले

कुछ जाने-माने अवॉर्ड पाने वालों में शामिल हैं:

- साइना नेहवाल – ओलंपिक मेडलिस्ट और भारत की टॉप बैडमिंटन आइकॉन में से एक।
- डॉ. एस. के. किरण कुमार – इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) के पूर्व चेयरमैन, जिन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम में दशकों के काम के लिए पहचान मिली।
- एन. राजम (वायलिन उस्ताद) और अलार्मेल वल्ली (क्लासिकल डांसर) जैसी जानी-मानी कल्चरल हस्तियां।
- डिफेंस सम्मान: इंडियन आर्म्ड फोर्सेज़ को ऑपरेशन सिंदूर (एक सिक्योरिटी ऑपरेशन) में उनकी लीडरशिप और बेहतरीन सर्विस के लिए खास श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड, सदर्न कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड जैसी यूनिट्स को सम्मान दिया गया।

बड़ा महत्व: यह अवॉर्ड देश की तरक्की के आपस में जुड़े होने को दिखाता है, यह दिखाता है कि कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स और डिफेंस मिलकर "भव्य भारत" (एक शानदार और मज़बूत भारत) के आइडिया में योगदान देते हैं।

ग्लोबल टीचर प्राइज 2026

भारतीय टीचर और एजुकेटर रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता, जो $1 मिलियन का एक प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचिंग अवॉर्ड है। उन्हें यह अवॉर्ड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में मिला। यह अवॉर्ड दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दिया।

उन्हें क्यों सम्मानित किया गया

रूबल नागी को बच्चों को पढ़ाने के लिए क्रिएटिव कला और शिक्षा का इस्तेमाल करने के लिए पहचाना गया। उन्होंने उपेक्षित दीवारों को एजुकेशनल म्यूरल्स में बदल दिया जो पढ़ना, लिखना, अंकगणित, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता सिखाते हैं। उनका काम वंचित और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों तक पहुंचने पर केंद्रित है।

प्राइज मनी के लिए योजनाएं

रूबल नागी $1 मिलियन के प्राइज का इस्तेमाल एक ऐसा संस्थान बनाने की योजना बना रही हैं जो वंचित युवाओं की मदद करने के उद्देश्य से मुफ्त व्यावसायिक ट्रेनिंग और डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगा।

ग्लोबल टीचर प्राइज के बारे में

ग्लोबल टीचर प्राइज GEMS एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वर्की फाउंडेशन और यूनेस्को के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। यह दुनिया भर के असाधारण टीचरों को टीचिंग और सीखने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचानता है।

मानवता का सैनिक पुरस्कार

भूटान की महारानी, महामहिम ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को उनकी बेहतरीन मानवीय सेवा, दयालु नेतृत्व और सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के लिए जीवन भर के प्रयासों के लिए 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'मानवता का सिपाही' पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह असम के कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के ज्वहलाओ नीलेश्वर ब्रह्मा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। यह सम्मान असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने प्रदान किया, जिन्होंने मानवीय गरिमा, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।

'मानवता के सैनिक' पुरस्कार के बारे में

उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट (UNBT) ने 2004 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'मानवता के सैनिक' पुरस्कार की स्थापना की, ताकि उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जा सके जो बोडो समुदाय के दूरदर्शी नेता 'बोडोफा' उपेंद्र नाथ ब्रह्मा से प्रेरित होकर बलिदान, साहस, मानव गरिमा और मानवता की सेवा के मूल्यों को अपनाते हैं। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, पारंपरिक बोडो औपचारिक वस्तुएँ (अरोनाई, दोखना, आदि) और एक नकद पुरस्कार (जैसे ₹2 लाख) शामिल है जो निरंतर मानवीय प्रयासों की पहचान का प्रतीक है। महारानी माँ दोरजी वांगमो वांगचुक यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी विदेशी नागरिक हैं, जो इस पुरस्कार की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता को दर्शाता है।

महारानी माँ दोरजी वांगमो वांगचुक के बारे में

दोरजी वांगमो वांगचुक का जन्म 10 जून 1955 को हुआ था और वह पूर्व राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की पहली पत्नी के रूप में भूटान की महारानी माँ हैं। वह अपनी मानवीय दृष्टि के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित हैं, विशेष रूप से तरायाना फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में - यह एक ऐसा संगठन है जो भूटान के दूरदराज के क्षेत्रों में समग्र ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी पहल भूटान के विकास दर्शन को दर्शाती है, जिसमें सकल राष्ट्रीय खुशी (GNH) की अवधारणा शामिल है - यह एक ऐसा मॉडल है जो विशुद्ध रूप से आर्थिक विकास के बजाय कल्याण को प्राथमिकता देता है - जो मानवीय और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। (सामान्य प्रासंगिक तथ्य)

क्रैफोर्ड पुरस्कार

भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने जियोसाइंस में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। क्रैफोर्ड पुरस्कार को अक्सर इसकी प्रतिष्ठा के कारण "जियोसाइंस का नोबेल" कहा जाता है।

उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला

रामनाथन को जलवायु परिवर्तन पर दशकों के रिसर्च के लिए यह पुरस्कार मिला। उनका काम सुपर-पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स पर केंद्रित था, जिसने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वैज्ञानिक समझ को बदल दिया है। 1975 में, NASA में काम करते समय, उन्होंने पाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना ज़्यादा गर्मी रोकते हैं।

उनके काम का प्रभाव

उनके रिसर्च ने जलवायु विज्ञान को बदल दिया और CO_2 से परे प्रदूषकों की भूमिका को उजागर किया। इन निष्कर्षों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बनाने में मदद की, जिससे हानिकारक उत्सर्जन कम हुआ।

पृष्ठभूमि और शिक्षा

- रामनाथन का जन्म मदुरै में हुआ था और वे भारत के चेन्नई में पले-बढ़े।
- उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के तौर पर की और बाद में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई की।
- वह अब स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया, सैन डिएगो में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमेरिटस हैं।

विज्ञान से परे काम

रामनाथन ने इंडियन ओशन एक्सपेरिमेंट (INDOEX) पर भी काम किया, जिसने दक्षिण एशिया में एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स का दस्तावेजीकरण किया। उनके अध्ययनों ने वायु प्रदूषण को भारतीय मानसून के कमजोर होने और हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से जोड़ा। उन्होंने वैश्विक नेताओं और यहां तक कि वेटिकन को भी जलवायु नैतिकता पर सलाह दी है।

क्रैफोर्ड पुरस्कार के बारे में

इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और लगभग 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 900,000 अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं। यह मई 2026 में स्टॉकहोम और लुंड में क्रैफोर्ड डेज़ के दौरान प्रदान किया जाएगा।

68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स

68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 1 फरवरी, 2026 को लॉस एंजिल्स, USA में Crypto.com एरिना में शुरू हुए। ये अवार्ड्स एलिजिबिलिटी पीरियड (31 अगस्त, 2024 – 30 अगस्त, 2025) के सर्वश्रेष्ठ संगीत रिकॉर्डिंग, कंपोजिशन और कलाकारों को पहचान देते हैं।

होस्ट और सेरेमनी फॉर्मेट

- कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने छठी और आखिरी बार होस्ट किया।
- CBS टेलीविज़न नेटवर्क पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और Paramount+ पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है।

टॉप नॉमिनी और दावेदार

- केंड्रिक लैमर को नौ नॉमिनेशन के साथ सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले।
- लेडी गागा को सात नॉमिनेशन मिले।

ऐतिहासिक जीत और हाइलाइट्स

- बैड बनी एल्बम ऑफ़ द ईयर जीतने वाले पहले लैटिन कलाकार बनकर इतिहास रचा।
- बिली इलिश ने सॉन्ग ऑफ़ द ईयर जीता और अपने एक्सेप्टेंस स्पीच का इस्तेमाल अप्रवासी अधिकारों की वकालत करने के लिए किया, जिससे उन्हें दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला।
- ओलिविया डीन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चुना गया।
- केंड्रिक लैमर रात के सबसे बड़े विजेताओं में से एक थे, उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ़ द ईयर और बेस्ट रैप एल्बम सहित कई अवार्ड जीते।

नई कैटेगरी और संगीत पहचान

- इस एडिशन में नई अवार्ड कैटेगरी पेश की गईं, जो इंडस्ट्री में बदलाव और विकास को दर्शाती हैं, जिसमें बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम और बेस्ट एल्बम कवर जैसे अवार्ड शामिल हैं।

अतिरिक्त नोट्स

- म्यूजिक फिल्मों और स्पेशल प्रोजेक्ट्स ने भी प्रतिष्ठित अवार्ड जीते, जिसमें स्टीवन स्पीलबर्ग और दलाई लामा के काम को पहचान मिली।
- विभिन्न शैलियों के उभरते और कम जाने-माने कलाकारों ने पहली बार ग्रैमी जीता, जो मनाए जाने वाले टैलेंट की विस्तृत श्रृंखला को दर्शाता है।

गणतंत्र दिवस परेड 2026 पुरस्कार

भारत सरकार ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखाए गए शानदार झांकियों और मार्चिंग टुकड़ियों को पहचानते हुए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 पुरस्कारों की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता, अनुशासन और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, जो वार्षिक गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य उद्देश्य हैं।

मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया

- झांकियों और टुकड़ियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक जूरी द्वारा इन आधारों पर किया गया:
- राष्ट्रीय विषय से प्रासंगिकता
- दृश्य प्रस्तुति और नवाचार
- सांस्कृतिक और सामाजिक कहानी
- कुल मिलाकर सार्वजनिक प्रभाव
- जूरी पुरस्कारों के अलावा, एक पॉपुलर चॉइस श्रेणी भी शामिल की गई, जिसमें नागरिकों ने MyGov पोर्टल के माध्यम से वोट दिया, जिससे शासन में सार्वजनिक भागीदारी मजबूत हुई।

सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार – राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

पहला पुरस्कार

- महाराष्ट्र ने अपनी झांकी के लिए पहला स्थान जीता जिसका शीर्षक था
- "गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक"
- झांकी में इन बातों पर प्रकाश डाला गया:
- समुदाय-आधारित सांस्कृतिक परंपराएं
- स्वदेशी शिल्प कौशल
- आत्मनिर्भर भारत की भावना
- गणेशोत्सव को आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

दूसरा पुरस्कार

- जम्मू और कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया
- "जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य"

झांकी में दिखाया गया:

- पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कालीन, शॉल और लकड़ी का काम
- समृद्ध लोक नृत्य परंपराएं
- इसने केंद्र शासित प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण को रेखांकित किया।

तीसरा पुरस्कार

- केरल ने तीसरा स्थान जीता
- "वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता"

झांकी में इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- वाटर मेट्रो के माध्यम से स्थायी शहरी परिवहन
- सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता में केरल की उपलब्धि
- इसने प्रौद्योगिकी, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ा।

सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियां

- भारतीय नौसेना ने जजों को प्रभावित किया:
- असाधारण अनुशासन और समन्वय
- पेशेवर सैन्य प्रस्तुति

दिल्ली पुलिस को भी इसके लिए पहचाना गया:

- सटीक मार्चिंग
- आंतरिक सुरक्षा तैयारियों का प्रदर्शन

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- गणतंत्र दिवस परेड हर साल 26 जनवरी को 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद में आयोजित की जाती है।
- कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) औपनिवेशिक विरासत से नागरिक-केंद्रित शासन की ओर बदलाव का प्रतीक है।

झांकियां इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं:

- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
- केंद्रीय मंत्रालय और विभाग

- MyGov पोर्टल 2014 में नीति और शासन में नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। सांस्कृतिक झांकियाँ अक्सर भारत की विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट-पावर टूल के रूप में काम करती हैं।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला

भारत के राष्ट्रपति ने जीवन बचाने में मानवता के सराहनीय कार्यों के लिए 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला – 2025 प्रदान करने को मंज़ूरी दी। इस सूची में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक (6), उत्तम जीवन रक्षा पदक (6), और जीवन रक्षा पदक (18) पुरस्कार विजेता शामिल हैं।

- छह पुरस्कार विजेताओं को यह सम्मान मरणोपरांत मिला।
- जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों की श्रेणियाँ
- सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक (6 पुरस्कार)
- जीवन बचाने में सबसे असाधारण साहस और आत्म-बलिदान के लिए दिया जाता है।
- **2025 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं:**
- श्री मनोहर सिंह चौहान (मरणोपरांत), मध्य प्रदेश
- श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, मध्य प्रदेश
- श्री पी एस गौरीशंकर राजा (मरणोपरांत), तमिलनाडु
- नायक आशुतोष बिस्वास (मरणोपरांत), रक्षा मंत्रालय
- श्री दीपक कुमार (मरणोपरांत), रक्षा मंत्रालय
- नायब सूबेदार मनजीत (मरणोपरांत), रक्षा मंत्रालय।

उत्तम जीवन रक्षा पदक (6 पुरस्कार)

- जीवन बचाने की स्थितियों में असाधारण साहस और त्वरित कार्रवाई के लिए दिया जाता है।
- 2025 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं: श्री सुमित यादव (दिल्ली), श्री वसीम अहमद गनी (जम्मू और कश्मीर), श्री मोहम्मद शमिल सी (केरल), श्री जोसेफ लालनुमाविया (मिजोरम), श्री सौम्यरंजन बेहरा (रक्षा मंत्रालय), और सिपाही श्वेनसिनलो सेम्प (मरणोपरांत, रक्षा मंत्रालय)।

जीवन रक्षा पदक (18 पुरस्कार)

- मानव जीवन बचाने में काफी साहस के लिए दिया जाता है।
- इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, सीमा सड़क संगठन और रक्षा मंत्रालय के प्राप्तकर्ता शामिल हैं।

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के बारे में

- उद्देश्य: ये पुरस्कार दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियों या अन्य खतरनाक स्थितियों के दौरान जीवन बचाने में मानवीय स्वभाव के साहसी कार्यों को मान्यता देते हैं।
- पात्रता: यह सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए खुला है, जिसमें नागरिक, सरकारी अधिकारी और रक्षा कर्मी शामिल हैं। • श्रेणियाँ:
- सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक: सबसे ज़्यादा बहादुरी के लिए सबसे ऊँची श्रेणी।
- उत्तम जीवन रक्षा पदक: असाधारण साहस के लिए दूसरी श्रेणी।
- जीवन रक्षा पदक: उल्लेखनीय बहादुरी के लिए तीसरी श्रेणी।
- ये पुरस्कार एक मेडल, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, और एकमुश्त नकद राशि के रूप में दिए जाते हैं।
- यदि बहादुरी के कार्य में बचाव करने वाले की जान चली जाती है, तो यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।

अन्य प्रमुख खबरें

राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की मूर्ति की जगह सी. राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया गया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सी. राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया, जो एडविन लुटियंस की मूर्ति की जगह है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था। सी. राजगोपालाचारी की मूर्ति को अशोक मंडप के पास ग्रैंड ओपन सीढ़ी पर लगाया गया है, जो दशकों से वहां लगी सर एडविन लुटियंस की मूर्ति की जगह लेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह बदलाव कॉलोनियल सोच की निशानियों को खत्म करने और भारतीय संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में

जन्म: दिसंबर 1878, राजगोपालाचारी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद और राजनेता थे। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित बड़े आंदोलनों में भाग लिया। राजगोपालाचारी आज़ाद भारत (1948–50) के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल बने, इससे पहले कि भारत के गणतंत्र बनने पर यह पद खत्म कर दिया गया। उन्होंने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

एडविन लुटियंस और कॉलोनियल संदर्भ के बारे में

सर एडविन लुटियंस एक मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर नई दिल्ली के बड़े हिस्सों को डिज़ाइन किया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक शामिल हैं। उनका काम भारत में ब्रिटिश शाही आर्किटेक्चर का प्रतीक था। उनके बस्ट को बदलने को राष्ट्रीय संस्थानों में कॉलोनियल प्रतीकों से भारतीय विरासत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

भारत की पब्लिक मेमोरी में डीकोलोनाइजेशन

भारत ने हाल ही में कॉलोनियल निशानों को फिर से समझने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

- नेशनल इंस्टीट्यूशन में कॉलोनियल दौर की मूर्तियों और तस्वीरों को हटाना या बदलना,
- पब्लिक जगहों और भारतीय ऐतिहासिक हस्तियों को हाईलाइट करने वाली कल्चरल पहलों का नाम बदलना।

यूनेस्को ने वियतनाम के लिए इमरजेंसी सहायता पैकेज की घोषणा की

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वियतनाम को प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और शिक्षा को बनाए रखने में मदद करने के लिए लगभग US$740,000 के इमरजेंसी सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की घोषणा 23 जनवरी, 2026 को नवंबर 2025 में वियतनाम में आए विनाशकारी तूफानों (विफा, बुआलोई और माटमो) की एक श्रृंखला के जवाब में की गई थी।

सहायता का उद्देश्य

- इस सहायता का उद्देश्य बाढ़ और तूफानों से क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा करना है, जिसमें ह्यू और होई एन में विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, तकनीकी मूल्यांकन और इमरजेंसी सुरक्षा उपायों को लागू करके।
- यह सुरक्षित सीखने की जगहों को बहाल करके, ज़रूरी स्कूल उपकरणों को बदलकर, और छात्रों और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करके शिक्षा को बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, खासकर काओ बैंग और लैंग सोन जैसे प्रांतों में कमजोर और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में।
- पार्टनर फंडिंग (जैसे जापान) के समर्थन से, यूनेस्को स्कूल सुरक्षा और दीर्घकालिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को भी बढ़ावा देगा।

यह समर्थन क्यों महत्वपूर्ण है

- तूफानों ने लगभग 10,000 स्कूलों को प्रभावित किया, लाखों घरों को नुकसान पहुंचाया, और पूरे वियतनाम में जान-माल का भारी नुकसान हुआ, जिससे सांस्कृतिक और शैक्षिक रिकवरी एक प्राथमिकता बन गई।
- यूनेस्को का पैकेज संस्कृति, शिक्षा और आपदा लचीलेपन को जोड़ने में संगठन की भूमिका को दर्शाता है, जो विरासत की रक्षा करने और बिना किसी रुकावट के सीखने को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करता है।

"यदि मंज़िल न मिले तो रास्ते बदलो !
क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं जड़े नहीं !!"

चर्चित व्यक्तित्व

नियुक्तियाँ

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	नियुक्ति / पद	विभाग / संगठन	संक्षिप्त विवरण
1	रॉब जेटन	प्रधानमंत्री	नीदरलैंड सरकार	38 वर्ष की आयु में गठबंधन गठन के बाद नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।
2	सुरेश अग्रवाल	एमडी एवं सीईओ (नामित)	एमएंडएम–मैनुलाइफ लाइफ इंश्योरेंस संयुक्त उपक्रम	प्रस्तावित 50:50 जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम के प्रमुख नियुक्त, नियामकीय मंजूरी के अधीन।
3	साने ताकाइची	प्रधानमंत्री (पुनर्नियुक्त)	जापान सरकार	स्नैप आम चुनाव में एलडीपी की सुपरमेजोरिटी जीत के बाद पुनर्नियुक्त।
4	तारिक रहमान	प्रधानमंत्री (शपथ ग्रहण हेतु)	बांग्लादेश सरकार	2026 चुनाव में भारी जीत के बाद बीएनपी संसदीय दल के नेता चुने गए।
5	मिया मोटली	प्रधानमंत्री (तीसरा कार्यकाल)	बारबाडोस सरकार	लगातार तीसरी बार जीत; उनकी पार्टी ने सभी 30 सीटें जीतीं।
6	पुनीत अग्रवाल	थाईलैंड में राजदूत	विदेश मंत्रालय, भारत	थाईलैंड के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त।
7	कमोडोर एंडी डॉउलिंग	रेजिडेंट डिफेंस एडवाइजर	न्यूजीलैंड उच्चायोग, भारत	भारत में न्यूजीलैंड के पहले रेजिडेंट डिफेंस एडवाइजर नियुक्त।
8	केंटा कोन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन	1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, प्रबंधन पुनर्गठन के तहत नियुक्त।
9	सोराया अघाएई हाजियाघा	सदस्य	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)	145वें आईओसी सत्र में चुनी गई पहली ईरानी महिला सदस्य।
10	युमनाम खेमचंद सिंह	मुख्यमंत्री	मणिपुर सरकार, भारत	राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
11	एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया	एओसी-इन-सी, ईस्टर्न एयर कमांड	भारतीय वायु सेना	1 फरवरी 2026 को ईस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला।
12	डेम सारा मुलैली	आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी	चर्च ऑफ इंग्लैंड	1,400 वर्ष के इतिहास में चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला प्रमुख बनीं।
13	शेख जोआन बिन हमद अल थानी	अध्यक्ष	ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA)	राजा रणधीर सिंह के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष निर्वाचित।
14	आनंद श्रीनिवासन	मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO)	अकासा एयर	प्रवीण अय्यर के इस्तीफे के बाद सीसीओ का पद संभाला।
15	पीटर बुर्रिल	अंतरिम मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	डिएगो डी जॉर्जी के इस्तीफे के बाद अंतरिम सीएफओ नियुक्त।

निधन

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	संबंधित क्षेत्र	विवरण
1	मुकुल रॉय	भारतीय राजनीति	पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता; कोलकाता में 71 वर्ष की आयु में हृदयाघात से निधन।
2	रिकी ए. जे. सिंगकों	भारतीय राजनीति	शिलांग से लोकसभा सांसद (VPP); फुटबॉल खेलते समय गिरने के बाद 54 वर्ष की आयु में निधन।
3	जेसी जैक्सन	सिविल राइट्स एवं अमेरिकी राजनीति	प्रमुख अमेरिकी सिविल राइट्स नेता और दो बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार; 84 वर्ष की आयु में निधन।
4	फ्रेडरिक वाइज़मैन	डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण	प्रभावशाली अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता; 96 वर्ष की आयु में निधन।
5	रमेश शुक्ला	फोटोग्राफी	यूएई के "रॉयल फोटोग्राफर" जिन्होंने देश के गठन को कैमरे में कैद किया; 87 वर्ष की आयु में निधन।
6	गीता पटनायक	संगीत (ओड़िया प्लेबैक गायन)	प्रसिद्ध ओड़िया गायिका, फिल्म और शास्त्रीय गीतों के लिए जानी जाती थीं; 73 वर्ष की आयु में निधन।
7	सरला महेश्वरी	पत्रकारिता एवं प्रसारण	दूरदर्शन की वरिष्ठ समाचार वाचिका; नई दिल्ली में 71 वर्ष की आयु में निधन।
8	जेम्स वैन डेर बीक	फिल्म एवं टेलीविजन अभिनय	अमेरिकी अभिनेता, "डॉसन'स क्रीक" के लिए प्रसिद्ध; कैंसर से संघर्ष के बाद 48 वर्ष की आयु में निधन।
9	कैथरीन ओ'हारा	फिल्म एवं टेलीविजन अभिनय	कनाडाई-अमेरिकी अभिनेत्री, "होम अलोन" और "शिट्स क्रीक" के लिए प्रसिद्ध; 71 वर्ष की आयु में निधन।
10	माइकल नोब्स	हॉकी (खिलाड़ी एवं कोच)	पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी और भारत के पूर्व कोच; 72 वर्ष की आयु में निधन।
11	अजीत पवार	भारतीय राजनीति	महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री; बारामती के पास विमान दुर्घटना में निधन।
12	आई. एस. बिंद्रा	क्रिकेट प्रशासन	पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष; भारतीय क्रिकेट के वैश्विक उभार में महत्वपूर्ण भूमिका; 84 वर्ष की आयु में निधन।
13	मार्क टली	पत्रकारिता एवं प्रसारण	वरिष्ठ बीबीसी पत्रकार, "वॉयस ऑफ इंडिया" के रूप में प्रसिद्ध; 90 वर्ष की आयु में निधन।

TOPPERS CLUB IAS ACADEMY

"जीतने का असली मज़ा तो तब है !
जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो !!

खेल-कूद

मैग्नस कार्लसन ने 2026 FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती

नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 2026 FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइटल जीता, जो जर्मनी के वीसेनहाउस में हुई थी। कार्लसन ने फाइनल में USA के फैबियानो कारुआना को हराकर चैंपियन बने।

FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या है?

FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रीस्टाइल चेस फॉर्मेट में एक ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसे Chess960 या फिशर रैंडम चेस भी कहा जाता है, जहाँ क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने और याद किए गए ओपनिंग पर निर्भरता कम करने के लिए पीस की शुरुआती व्यवस्था रैंडम होती है। 2026 एडिशन पहली ऑफिशियली मान्यता प्राप्त FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसे FIDE (इंटरनेशनल चेस फेडरेशन) और फ्रीस्टाइल चेस ऑपरेशंस ने मिलकर ऑर्गनाइज़ किया था।

टूर्नामेंट का फ़ॉर्मेट और नतीजे

इस इवेंट में टाइटल वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्ले-इन खुला था, जिसके बाद कई दिनों तक आठ टॉप ग्रैंडमास्टर्स के बीच फ़ाइनल हुआ। ग्रुप और सेमीफ़ाइनल स्टेज में टॉप पर रहने के बाद, कार्लसन फ़ाइनल में पहुँचे और तीसरे गेम में एक अहम जीत और चौथे गेम में एक अहम ड्रॉ के साथ वर्ल्ड टाइटल पक्का किया। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव (उज़्बेकिस्तान) तीसरे स्थान पर रहे, और वह और कारुआना दोनों कार्लसन के साथ 2027 चैंपियनशिप के लिए क्वालिफ़ाई हुए।

जीत का महत्व

इस टाइटल को शतरंज में एक बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप माना जाता है, और यह कार्लसन के शानदार रिकॉर्ड में जुड़ता है, जिससे अलग-अलग फ़ॉर्मेट में उनके कुल वर्ल्ड टाइटल 21 हो गए हैं — जिसमें क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप शामिल हैं। यह जीत एक ऐसे फ़ॉर्मेट में मिली जो एडजस्ट करने की क्षमता और क्रिएटिविटी पर ज़ोर देता है, जिससे कार्लसन की विरासत स्टैंडर्ड टाइम-कंट्रोल शतरंज इवेंट्स से आगे बढ़ती है।

खास प्रतिभागी और प्रदर्शन

फ़बियानो कारुआना (USA) — रनर-अप और दुनिया के टॉप शतरंज ग्रैंडमास्टर्स में से एक। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव (UZB) — ब्रॉन्ज़ मैच जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। विंसेंट कीमर (GER) — टूर्नामेंट में ज़ोरदार मुकाबला किया। दूसरे जाने-माने खिलाड़ियों में हैंस नीमन (USA) और लेवोन एरोनियन (ARM) शामिल थे।

विंटर ओलंपिक्स 2026 — जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो का ऐतिहासिक नौवां गोल्ड मेडल

जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो ने इटली के मिलानो कॉर्टिना में हुए 2026 विंटर ओलंपिक्स में क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में अपना रिकॉर्ड तोड़ नौवां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने टेसेरो क्रॉस-कंट्री स्की स्टेडियम में पुरुषों की 4×7.5 km रिले में नॉर्वे की जीत में अहम भूमिका निभाकर यह उपलब्धि हासिल की। इस नौवें गोल्ड ने उन्हें विंटर ओलंपिक्स के इतिहास के सभी एथलीटों से आगे कर दिया है।

ऐतिहासिक उपलब्धि

क्लेबो का नौवां ओलंपिक गोल्ड एक नया विंटर ओलंपिक रिकॉर्ड है, जिससे वह गोल्ड मेडल के मामले में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले पुरुष विंटर ओलंपियन बन गए हैं। उन्होंने नॉर्वे के मशहूर विंटर एथलीट मैरिट ब्योर्गेन, ब्योर्न डेहली और ओले आइनार ब्योर्नडालेन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम आठ-आठ गोल्ड मेडल थे।

2026 विंटर ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस

क्लेबो ने मिलान-कॉर्टिना 2026 गेम्स में चार गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 10 km फ्रीस्टाइल, 20 km स्कीथलॉन, इंडिविजुअल स्प्रिंट और रिले इवेंट शामिल हैं। नॉर्वे की टीम ने रिले में 1:04:24.5 का समय लिया, जो फ्रांस से 22.2 सेकंड और इटली से 47.9 सेकंड आगे रहा।

करियर की खास बातें

क्लेबो ने इससे पहले 2018 प्योंगचांग ओलंपिक्स में तीन गोल्ड मेडल और 2022 बीजिंग ओलंपिक्स में दो गोल्ड मेडल जीते थे। स्प्रिंट, डिस्टेंस और रिले इवेंट्स में उनकी वर्सेटाइल स्किल क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में उनके दबदबे को दिखाती है।

कर्नाटक ने रोमांचक सुपर ओवर में नेशनल T20 ब्लाइंड क्रिकेट का खिताब जीता

कर्नाटक ने दिल्ली को एक रोमांचक सुपर ओवर में हराकर नागेश ट्रॉफी जीती। फाइनल 13 फरवरी 2026 को गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में खेला गया था। कर्नाटक ने दिल्ली के टोटल का पीछा किया और मैच टाई होने के बाद, सुपर ओवर में दिल्ली के 10 रन के मुकाबले 11 रन बनाकर जीत पक्की कर ली।

नागेश ट्रॉफी क्या है?

यह भारत का नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो देखने में अक्षम (ब्लाइंड) खिलाड़ियों के लिए है। यह कॉम्पिटिशन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है, जो पूरे देश में सबको साथ लेकर चलने वाले और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को बढ़ावा देता है।

टॉप परफ़ॉर्मर और अवॉर्ड

सुनील रमेश को उनकी मैच जिताने वाली सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। संजय कुमार शाह, रामबीर सिंह और सुनील रमेश को पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा परफ़ॉर्मेंस देने के लिए प्लेयर्स ऑफ़ द सीरीज़ का सम्मान मिला।

इनाम और पहचान

चैंपियन कर्नाटक टीम को ₹1,50,000 का इनाम मिला। दिल्ली की रनर-अप टीम ने ₹1,25,000 जीते, जो ब्लाइंड क्रिकेट के लिए बढ़ते सपोर्ट और प्रोफ़ेशनल पहचान को दिखाता है।

भारत ने SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप का खिताब जीता

भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराकर SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया। भारत की U-17 महिला टीम ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिससे उन्हें आने वाली कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता के लिए अनुभव मिला। भाग लेने का उद्देश्य: भारत ने 2026 में होने वाले AFC U-17 महिला एशियाई कप की तैयारी के लिए U-19 चैम्पियनशिप में अपनी U-17 महिला राष्ट्रीय टीम को मैदान में उतारा।

- स्थान: पोखरा रंगशाला स्टेडियम, नेपाल।
- टूर्नामेंट आयोजक: साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (SAFF), जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (AFC) के तहत दक्षिण एशिया में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। (सामान्य फुटबॉल ज्ञान)

SAFF के बारे में:

SAFF का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, जिसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और मालदीव।

SAFF विभिन्न आयु-समूह और सीनियर टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिसमें SAFF चैम्पियनशिप, SAFF U-19, SAFF U-17, और SAFF महिला चैम्पियनशिप शामिल हैं। ये क्षेत्रीय टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई टीमों के बीच प्रतिभा को निखारने और प्रतिस्पर्धी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- गठन: 1997
- मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
- अध्यक्ष: काजी सलाहुद्दीन
- उपाध्यक्ष: सुंदर नरसिंह जोशी
- महासचिव: पुरुषोत्तम कट्टेल

सर्विसेज़ ने 8वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता

सर्विसेज़ फुटबॉल टीम ने असम के धकुआखाना फुटबॉल स्टेडियम में एक्स्ट्रा टाइम के बाद केरल को 1-0 से हराकर अपना आठवां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता।

चैंपियन और रनर-अप

- चैंपियन: सर्विसेज़ टीम (आठवां खिताब)
- रनर-अप: केरल फुटबॉल टीम
- स्थान: धकुआखाना फुटबॉल स्टेडियम, असम
- संस्करण: 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप (संतोष ट्रॉफी)
- ऐतिहासिक संदर्भ: यह सिर्फ़ दूसरी बार था जब सर्विसेज़ और केरल संतोष ट्रॉफी के फाइनल में मिले; पिछली फाइनल भिड़ंत 2012-13 संस्करण में कोच्चि में हुई थी, जिसे सर्विसेज़ ने पेनल्टी शूट-आउट से जीता था।
- पिछले खिताब: सर्विसेज़ 2023-24 में भी चैंपियन थे, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में फाइनल में गोवा को 1-0 से हराया था।

संतोष ट्रॉफी के बारे में

संतोष ट्रॉफी भारत में एक राष्ट्रीय राज्य-स्तरीय फुटबॉल चैम्पियनशिप है, जिसमें राज्य टीमों और संस्थागत टीमों (जैसे, सर्विसेज़, रेलवे) के बीच मुकाबला होता है। यह पहली बार 1941 में आयोजित की गई थी, जिसका नाम संतोष के सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया था।

सबसे ज़्यादा खिताब: पश्चिम बंगाल ने सबसे ज़्यादा संतोष ट्रॉफी जीती हैं।

भारत ने रिकॉर्ड छठा ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता

भारत ने ज़िम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हुए फाइनल में इंग्लैंड अंडर-19 को 100 रनों से हराकर ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में उनका छठा खिताब है। भारत ने अपने 50 ओवरों में 411/9 का शानदार स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों पर रिकॉर्ड तोड़ 175 रन बनाए—जो अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। जवाब में, इंग्लैंड 40.2 ओवर में 311 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारत ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया।

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप

- आयोजक: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
- पहला एडिशन: 1988 ऑस्ट्रेलिया
- लेटेस्ट एडिशन: 2026 ज़िम्बाब्वे, नामीबिया
- टीमों की संख्या: 16
- मौजूदा चैंपियन: भारत (छठा खिताब)
- सबसे सफल: भारत (6 खिताब)
- सबसे ज़्यादा रन: इयोन मॉर्गन (606) (आयरलैंड)
- सबसे ज़्यादा विकेट: वेस्ली मधेवेरे (28) (ज़िम्बाब्वे) और क्वेना मफाका (28) (साउथ अफ्रीका)

स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल की रिकॉर्ड तोड़ पारी की बदौलत RCB ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दूसरा WPL खिताब

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने वडोदरा में WPL 2026 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को छह विकेट से हरा दिया। DC ने 20 ओवर में 203/4 रन बनाए, जो फाइनल में एक मजबूत स्कोर था। RCB ने 19.4 ओवर में 204 रन बनाकर WPL फाइनल में सबसे बड़ा सफल रन चेज़ पूरा किया। इस जीत से RCB ने अपना दूसरा WPL खिताब जीता और वह एक ही समय में IPL और WPL दोनों ट्रॉफियां जीतने वाली पहली फ्रेंचाइजी बन गई।

समारोह में दिए गए पुरस्कार

टीम पुरस्कार

- विजेता: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम — ₹6 करोड़ का पुरस्कार।
- उपविजेता: दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम — ₹3 करोड़ का पुरस्कार।

व्यक्तिगत पुरस्कार

- फाइनल के बाद प्रस्तुति के हिस्से के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत पुरस्कार में नकद पुरस्कार (आमतौर पर ₹5 लाख) शामिल था।
- प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल): स्मृति मंधाना (RCB) — उनकी मैच जिताऊ 87 रनों की पारी के लिए।
- ऑरेंज कैप (टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन): स्मृति मंधाना (RCB) — 377 रन।
- पर्पल कैप (टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट): सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) — 17 विकेट।
- सीज़न की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP): सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स)।
- सीज़न की उभरती हुई खिलाड़ी: नंदिनी शर्मा (DC)।
- सीज़न की सुपर स्ट्राइकर: ग्रेस हैरिस (RCB) — सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट।
- टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल: लॉरेन बेल (RCB)।
- सीज़न का कैच: लूसी हैमिल्टन (DC)।
- सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट (सीज़न): ग्रेस हैरिस (RCB)।
- टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के (विशेष): हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस)।
- फेयर प्ले अवार्ड: मुंबई इंडियंस। WPL
- एडमिनिस्ट्रेटर: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

- हेडक्वार्टर: मुंबई, भारत
- फॉर्मेट: T20
- पहला एडिशन: 2023
- लेटेस्ट एडिशन: 2026
- मौजूदा चैंपियन: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (दूसरा टाइटल)
- सबसे सफल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2 टाइटल) और मुंबई इंडियंस (2 टाइटल)
- सबसे ज़्यादा रन: नेट साइवर-ब्रंट (1,348) (इंग्लैंड)
- सबसे ज़्यादा विकेट: अमेलिया केर (54) (न्यूजीलैंड)

मीराबाई चानू ने नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में तीन नेशनल रिकॉर्ड तोड़े

नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने महिलाओं की 48 kg कैटेगरी में तीन नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में कॉम्पिटिशन करते हुए, उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल लिफ्ट में नए रिकॉर्ड बनाए, जिससे भारतीय वेटलिफ्टिंग में उनका दबदबा फिर से साबित हुआ।

बनाए गए नेशनल रिकॉर्ड

- टोटल लिफ्ट: 205 kg — नया नेशनल रिकॉर्ड।
- स्नैच: 89 kg — नया नेशनल रिकॉर्ड।
- क्लीन एंड जर्क: 116 kg — नया नेशनल रिकॉर्ड।
- इन लिफ्ट्स ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके 199 kg के लिफ्ट की तुलना में उनके पिछले कंबाइंड बेस्ट में 6 kg का सुधार किया।

गोल्ड मेडल

- चानू के 205 kg के टोटल लिफ्ट ने उन्हें इवेंट में महिलाओं की 48kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिलाया।

कार्लोस अल्काराज़ ने 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, सबसे कम उम्र के करियर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने

कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन) ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क के रॉड लेवर एरिना में फाइनल में नोवाक जोकोविच (सर्बिया) को हराकर 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता। यह अल्काराज़ का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और कुल मिलाकर उनका 7वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। 22 साल और 272 दिन की उम्र में, अल्काराज़ ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम (सभी चार प्रमुख एकल खिताब जीतना) पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अल्काराज़ ने मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जोकोविच के अजेय रिकॉर्ड (10-0) को खत्म कर दिया।

ऐतिहासिक संदर्भ:

टेनिस इतिहास में केवल नौ पुरुषों ने करियर ग्रैंड स्लैम (सभी चार प्रमुख खिताब जीतना) पूरा किया है, जिसमें रॉड लेवर, आंद्रे अगासी, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और अब कार्लोस अल्काराज़ जैसे दिग्गज शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कैलेंडर वर्ष के चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से पहला है, जो सालाना जनवरी-फरवरी में मेलबर्न में खेला जाता है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026

- संस्करण: 114वाँ
- श्रेणी: ग्रैंड स्लैम
- प्राइज मनी: A$111,500,000
- स्थान: मेलबर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया

चैंपियन 2026:

- पुरुष एकल: कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन)
- महिला एकल: एलेना रायबाकिना (कजाकिस्तान)
- पुरुष युगल: क्रिश्चियन हैरिसन / नील स्कुपस्की
- महिला युगल: एलिस मर्टेंस / झांग शुआई
- मिश्रित युगल: ओलिविया गैडेकी / जॉन पीयर्स

परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन

दिवस	मनाया जाता है	थीम/महत्व
01-मार्च	शून्य भेदभाव दिवस	जीवन बचाएँ: अपराधमुक्त करें
03- मार्च	विश्व वन्यजीव दिवस	औषधीय और सुगंधित पौधे: स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण
04- मार्च	राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	युवा दिमागों को बढ़ावा दें - अपनी संस्कृति को सुरक्षित करें
08- मार्च	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	पाने के लिए दो
10- मार्च	सीआईएसएफ स्थापना दिवस	10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना को चिह्नित करने हेतु
14- मार्च	नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	हमारी नदियाँ, हमारा भविष्य
15- मार्च	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता
18- मार्च	आयुध निर्माणी दिवस	18 मार्च 1802 को कोलकाता के कोसीपुर में भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी की स्थापना को चिह्नित करने हेतु
20- मार्च	अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस	दिमागदार • आभारी • दयालु
21- मार्च	अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस	वन और अर्थव्यवस्थाएँ
22- मार्च	विश्व जल दिवस	जल और लिंग
23- मार्च	विश्व मौसम विज्ञान दिवस	आज का पालन, कल की सुरक्षा
24- मार्च	विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस	हाँ! हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं: प्रतिबद्ध हों, निवेश करें, परिणाम दें
27- मार्च	विश्व रंगमंच दिवस	रंगमंच कलाओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु

पुस्तकें एवं लेखक

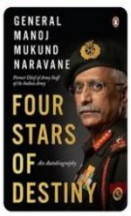

पुस्तक: फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी: एन ऑटोबायोग्राफी
लेखक: जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
बारे में: इसमें आर्म्ड फोर्सेज़ को मज़बूत करने और उन्हें आने वाली इक्कीसवीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों के लिए और अच्छे से तैयार करने के लिए ज़रूरी सुधारों के बारे में बताया गया है।

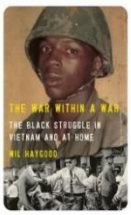

पुस्तक: द वॉर विदिन अ वॉर
लेखक: विल हेगुड
बारे में: यह वियतनाम युद्ध में अफ्रीकी-अमेरिकी सैनिकों के अनुभव, सेना में नस्लभेद और अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन को दिखाती है।

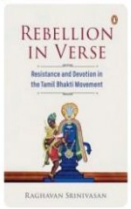

पुस्तक: रेबेलियन इन वर्स
लेखक: राघवन श्रीनिवासन
बारे में: यह बताती है कि तमिल भक्ति कवियों ने भक्ति के माध्यम से जाति व्यवस्था और धार्मिक सत्ता को चुनौती देकर सामाजिक बदलाव लाया।

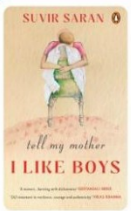

पुस्तक: टेल माय मदर आई लाइक बॉयज़
लेखक: सुवीर सरन
बारे में: यह पहचान, परिवार की अपेक्षाओं, यौनिकता की समझ और आत्मस्वीकार की सरल व भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है।

पुस्तक: तात्यासाहेब
लेखक: हरीश दामोदरन
बारे में: यह एक उद्यमी के जीवन के माध्यम से बॉम्बे के व्यापारिक इतिहास, सामाजिक बदलाव और आर्थिक नेटवर्क के विकास को समझाती है।

पुस्तकें एवं लेखक

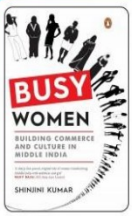

पुस्तक: बिज़ी वुमन
लेखक: शिंजिनी कुमार
बारे में: यह दिखाती है कि घर और काम दोनों जगह महिलाओं का योगदान कम आंका जाता है और बराबरी के सम्मान की ज़रूरत है।

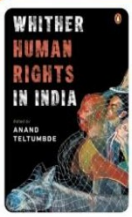

पुस्तक: व्हिदर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया
लेखक: आनंद तेलतुंबड़े
बारे में: यह बताती है कि राजनीति और नीतियों के कारण खासकर गरीब और हाशिये के लोगों के मानवाधिकार धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं।

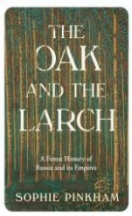

पुस्तक: द ओक एंड द लार्च
लेखक: सोफी पिंखम
बारे में: यह रूस के इतिहास, संस्कृति और साम्राज्य को पेड़ों और जंगलों के नज़रिये से समझाने का अनोखा प्रयास करती है।

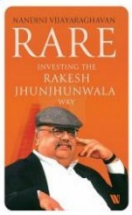

पुस्तक: रेयर
लेखक: नंदिनी विजयराघवन
बारे में: यह राकेश झुनझुनवाला की निवेश सोच, धैर्य, अनुशासन और व्यावहारिक वित्तीय समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है

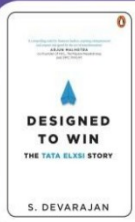

पुस्तक: डिज़ाइन्ड टू विन
लेखक: एस. देवराजन
बारे में: यह बताती है कि कैसे टाटा एल्क्सी ने रणनीति, नवाचार और डिज़ाइन-केंद्रित सोच से संकट से निकलकर वैश्विक तकनीकी पहचान बनाई।

केंद्रीय बजट 2026-27 हाइलाइट्स

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और यह विकास, नागरिकों की आकांक्षाओं और समावेशी विकास पर केंद्रित है।

1. मुख्य लक्ष्य (कर्तव्य)
यह बजट तीन बड़े लक्ष्यों से प्रेरित है:
1. उत्पादकता में सुधार करके अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाना और वैश्विक बदलावों के सामने भारत को मज़बूत बनाना।
2. लोगों की क्षमताओं और अवसरों को बढ़ाकर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना।
3. समावेशी विकास सुनिश्चित करना ताकि हर परिवार, क्षेत्र, समुदाय और क्षेत्र को लाभ हो।

2. बजट के आंकड़े (अनुमान)
- कुल प्राप्तियां (उधार के बिना): ₹36.5 लाख करोड़
- कुल खर्च: ₹53.5 लाख करोड़
- केंद्र का शुद्ध कर राजस्व: ₹28.7 लाख करोड़
- सकल बाज़ार उधारी: ₹17.2 लाख करोड़
- शुद्ध बाज़ार उधारी (पुनर्भुगतान के बाद): ₹11.7 लाख करोड़
- राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3%
- ऋण-से-GDP अनुपात: 55.6% (पिछले साल से कम)

3. पहला कर्तव्य — विकास और रणनीतिक विकास
इस खंड में उद्योगों, नौकरियों और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाएं शामिल हैं:

A. मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना
बजट का लक्ष्य 7 रणनीतिक सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है:
- बायोफार्मा शक्ति: भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए 5 सालों में ₹10,000 करोड़। नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPERs) और मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स डेवलप की जाएंगी।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण और टेक्नोलॉजी बनाने के लिए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स: बजट बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया।
- दुर्लभ पृथ्वी गलियारे: खनिज-समृद्ध राज्यों में खनन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए।
- केमिकल पार्क: केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए तीन पार्क।
- पूंजीगत सामान: निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए नए टूल रूम और योजनाएं।
- कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग: 5 सालों में ₹10,000 करोड़ की एक समर्पित योजना।

B. कपड़ा क्षेत्र योजना
बजट में एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम पेश किया गया है जिसमें शामिल हैं:
- प्राकृतिक और नए फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना।
- क्लस्टर को आधुनिक बनाने के लिए टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना।
- टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क।
- खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल।

C. पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर
बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित करने की योजना।

D. छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए समर्थन
- भविष्य की चैंपियन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड।

- सूक्ष्म उद्यमों के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड में ₹2,000 करोड़ जोड़े गए।
- पेशेवर निकाय छोटे शहरों में बिजनेस सलाहकारों को प्रशिक्षित करने में मदद करेंगे।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में काफी बढ़ोतरी की है:

- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।
- एक इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी फंड निजी डेवलपर्स को सपोर्ट करेगा।
- REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) सरकारी रियल एस्टेट संपत्तियों को रीसायकल करने में मदद करेंगे।

नई कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- समर्पित फ्रेट कॉरिडोर: तेज कार्गो आवाजाही के लिए डंकुनी (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) तक।
- आंतरिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
- वाराणसी और पटना में नाव मरम्मत सुविधाएं।
- 2047 तक शिपिंग हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटीय कार्गो संवर्धन योजना।
- कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ाने के लिए सीप्लेन मैन्युफैक्चरिंग और संचालन के लिए समर्थन।

5. ऊर्जा एवं शहरी विकास

- कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS) टेक्नोलॉजी के लिए 5 सालों में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- सुधार-आधारित फाइनेंसिंग के साथ शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 5 सालों में प्रति शहर आर्थिक क्षेत्र ₹5,000 करोड़।
- प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

6. शासन और वित्तीय सुधार

- विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करेगी।
- बेहतर दक्षता के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनर्गठन।
- विदेशी निवेश नियमों (FEMA) को आसान और आधुनिक बनाने के लिए उनकी समीक्षा की जाएगी।
- नगरपालिका बॉन्ड: बड़े शहरों द्वारा ₹1,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड के लिए ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन।

7. दूसरा कर्तव्य — लोगों की आकांक्षाएं और क्षमता निर्माण

बजट में कौशल, नौकरियों, स्वास्थ्य और सेवाओं के साथ लोगों का समर्थन करने के लिए कई उपाय शामिल हैं:

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

- 5 सालों में 100,000 नए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे।
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब।
- तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन

- ऑरेंज इकोनॉमी समर्थन: 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब।
- औद्योगिक क्षेत्रों के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप।
- हर जिले में लड़कियों के छात्रावास बनाए जाएंगे।
- पर्यटन समर्थन में गाइडों का अपस्किलिंग और एक राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड शामिल है।
- 15 ऐतिहासिक स्थलों को सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

खेल

खेल बुनियादी ढांचे और प्रतिभा को मजबूत करने के लिए एक नया खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा।

8. तीसरा कर्तव्य — समावेशी विकास ("सबका साथ, सबका विकास")

A. कृषि और किसान सहायता

- एकीकृत कृषि सहायता के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों की परियोजनाएँ।
- तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी ज़्यादा कीमत वाली फसलों के लिए सहायता।
- भारत-विस्तार: किसानों को कृषि जानकारी और टेक्नोलॉजी तक पहुँचने में मदद करने के लिए एक बहुभाषी AI टूल।

B. दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना

दिव्यांगजन कौशल योजना दिव्यांग व्यक्तियों को IT, AVGC, हॉस्पिटैलिटी और F&B सेक्टर में नौकरियाँ खोजने में मदद करेगी।

C. मानसिक स्वास्थ्य

उत्तर भारत में NIMHANS-2 स्थापित किया जाएगा, और मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।

D. क्षेत्रीय विकास

- दुर्गापुर में एक मज़बूत नोड के साथ पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा।
- पूर्वोत्तर में पाँच पर्यटन स्थल और स्थायी यात्रा के लिए 4,000 ई-बसें।
- पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास।

9. राज्यों के लिए सहायता

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, FY 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹1.4 लाख करोड़ प्रदान किए गए।

10. कर और सीमा शुल्क प्रस्ताव (सरलीकृत)

प्रत्यक्ष कर

- नया आयकर अधिनियम, 2025 अप्रैल 2026 से आसान अनुपालन के लिए शुरू होगा।
- जुर्माना नियमों में बदलाव का लक्ष्य मुकदमों को कम करना और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना है।
- मोटर दुर्घटना दावों से प्राप्त ब्याज आयकर से मुक्त होगा।
- विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा/चिकित्सा के लिए भेजे गए पैसे पर TCS घटाकर 2% किया जाएगा।
- IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियमों का विस्तार 15.5% मार्जिन और उच्च सीमा के साथ किया गया है।
- भारत से क्लाउड सेवाएँ प्रदान करने वाले अनिवासियों को 2047 तक टैक्स छूट मिलेगी।
- MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर) घटाकर 14% किया गया और इसे अंतिम कर बनाया गया।

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क

- स्टील, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्माण का समर्थन करने के लिए सीमा शुल्क सरलीकरण।
- कई छूटें पेश की गईं (जैसे, लिथियम-आयन बैटरी के पुर्जे, विमान के पुर्जे)।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क दर 20% से घटाकर 10% की गई।
- 17 दवाओं पर छूट और कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए शुल्क-मुक्त आयात। कस्टम्स सुविधा
- अप्रैल 2026 तक बेहतर डिजिटल सिस्टम से कस्टम्स क्लीयरेंस तेज़ और आसान होगा।
- सभी ट्रेड प्रोसेस के लिए 2 साल में कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (CIS) लॉन्च किया जाएगा।

निर्यात प्रोत्साहन

- भारतीय जलक्षेत्र या गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछली को बिना ड्यूटी के निर्यात माना जाएगा।
- छोटे व्यवसायों को ग्लोबल मार्केट तक पहुँचने में मदद करने के लिए प्रति खेप कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख की सीमा हटा दी गई है।

यात्रा में आसानी और टैक्सपेयर्स को राहत

- आधुनिक यात्रा ज़रूरतों के हिसाब से इंटरनेशनल बैगेज नियमों को अपडेट किया जाएगा।
- ईमानदार टैक्सपेयर्स जुर्माने के बजाय अतिरिक्त राशि देकर विवादों को सुलझा सकते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण हाइलाइट्स

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 (जिसे आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण 2026 कहा जाता है) भारत सरकार की एक वार्षिक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है जो पिछले वर्ष देश के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करती है, मैक्रोइकोनॉमिक विकास का आकलन करती है, और भविष्य की संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा बताती है। यह विकास, मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय प्रदर्शन, राजकोषीय रुझानों और संरचनात्मक चुनौतियों पर डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान प्रदान करके केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए मंच तैयार करता है।

हर साल आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है?

यह सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सरकारी अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की एक टीम इस आधिकारिक दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए आर्थिक डेटा संकलित और विश्लेषण करती है।

आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया जाता है और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है?

यह सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है - 2026 में इसे बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया था। इसे औपचारिक रूप से लोकसभा (संसद के निचले सदन) के समक्ष एक पूर्व-बजट दस्तावेज़ के रूप में रखा जाता है ताकि सांसदों, विश्लेषकों और जनता को अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया जा सके।

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 का क्या महत्व है?

सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

- प्रदर्शन की समीक्षा करता है: पिछले वर्ष भारत की आर्थिक प्रगति, चुनौतियों और लचीलेपन का आकलन करता है।
- नीति निर्माण को सूचित करता है: ऐसे साक्ष्य और अनुमान प्रदान करता है जो बजट निर्माण और नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं।
- दिशा का संकेत देता है: संरचनात्मक सुधारों, जोखिमों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है।
- सार्वजनिक बहस को आकार देता है: शिक्षाविदों, निवेशकों, व्यापारिक नेताओं और मीडिया के लिए प्रमुख आर्थिक रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 केंद्रीय बजट 2026 से किस तरह जुड़ा है?

आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के लिए एक नैदानिक और विश्लेषणात्मक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। आर्थिक विकास, राजकोषीय रुझानों, मुद्रास्फीति और क्षेत्रीय प्रदर्शन का इसका आकलन केंद्रीय बजट 2026-27 में बजट अनुमानों, राजस्व लक्ष्यों, व्यय प्राथमिकताओं और सुधार उपायों को आकार देने में मदद करता है। नीति निर्माता राजकोषीय रणनीति को आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए इसके अनुमानों और सिफारिशों का उपयोग करते हैं।

सर्वे के ज़रिए आर्थिक परिदृश्य

1) अर्थव्यवस्था की स्थिति

- FY26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% बढ़ी।
- सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 7.3% की वृद्धि हुई।
- भारत लगातार चौथे साल सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा।
- सेवा क्षेत्र में H1 FY26 में 9.3% की वृद्धि हुई और पूरे साल के लिए इसका अनुमान 9.1% है।

2) राजकोषीय विकास

- FY25 में केंद्र सरकार का राजस्व GDP के 9.2% तक बढ़ गया।

- आयकर फाइल करने वालों की संख्या 6.9 करोड़ (FY22) से बढ़कर 9.2 करोड़ (FY25) हो गई।
- GST कलेक्शन ₹17.4 लाख करोड़ (अप्रैल-दिसंबर 2025) तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 6.7% बढ़ा।
- प्रभावी पूंजीगत व्यय बढ़कर GDP का लगभग 4% हो गया।
- सामान्य सरकारी कर्ज 2020 की तुलना में 7.1 प्रतिशत अंक कम हो गया।

3) मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र

- बैंकों का सकल NPA घटकर 2.2% हो गया, जबकि शुद्ध NPA घटकर 0.5% हो गया।
- 55.02 करोड़ जन धन खाते खोले गए, जिसमें 36.63 करोड़ ग्रामीण खाते शामिल हैं।
- डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से ज़्यादा हो गई।
- भारत में अब 12 करोड़ से ज़्यादा यूनिक निवेशक हैं, जिनमें लगभग 25% महिला निवेशक हैं।

4) बाहरी क्षेत्र

- वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% हो गई।
- सेवा निर्यात रिकॉर्ड USD 387.6 बिलियन तक पहुंच गया।
- भारत को USD 135.4 बिलियन का रेमिटेंस मिला, जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा है।
- विदेशी मुद्रा भंडार USD 701.4 बिलियन था, जो लगभग 11 महीने के आयात को कवर करता है।

5) मुद्रास्फीति

अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.7% पर कम रही।

6) कृषि और खाद्य

- खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 3,577.3 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो 254.3 LMT ज़्यादा है।
- PM-KISAN योजना के तहत किसानों को ₹4.09 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जारी की गई।

7) उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और PLI

- मैन्युफैक्चरिंग GVA Q1 FY26 में 7.72% और Q2 FY26 में 9.13% बढ़ा।
- प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं ने ₹2.0 लाख करोड़ से ज़्यादा का असल निवेश आकर्षित किया।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में 10 प्रोजेक्ट्स में ₹1.60 लाख करोड़ का निवेश हुआ।

8) इंफ्रास्ट्रक्चर

- हाई-स्पीड हाईवे कॉरिडोर 550 किमी से बढ़कर 5,364 किमी हो गए।
- लगभग 3,500 किमी रेलवे लाइनें जोड़ी गईं।
- 99.1% रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया।
- भारत 164 चालू एयरपोर्ट के साथ तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया।

9) रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी

- भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और सौर ऊर्जा में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा।
- SpaDeX मिशन के ज़रिए, भारत ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया।

10) शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास

- भारत में अब 23 IIT, 21 IIM और 20 AIIMS हैं, जिनमें 2 इंटरनेशनल IIT कैंपस शामिल हैं।
- देश भर में मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई।

11) रोज़गार, श्रम और सामाजिक प्रगति

- ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज़्यादा मज़दूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 54% महिलाएं हैं।
- नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 2.8 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों की वैकेंसी लिस्ट की गईं।
- मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) 55.3% (2005-06) से घटकर 11.28% (2022-23) हो गया।

12) रणनीतिक विज़न – अनुशासित स्वदेशी

- टारगेटेड स्वदेशीकरण के ज़रिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्भरता कम करने पर ध्यान।
- उच्च प्रभाव वाली और लागत प्रभावी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के निर्माण पर ज़ोर।
- दीर्घकालिक लक्ष्य: आत्मनिर्भरता से वैश्विक बाज़ारों में रणनीतिक अनिवार्यता की ओर बढ़ना।

TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

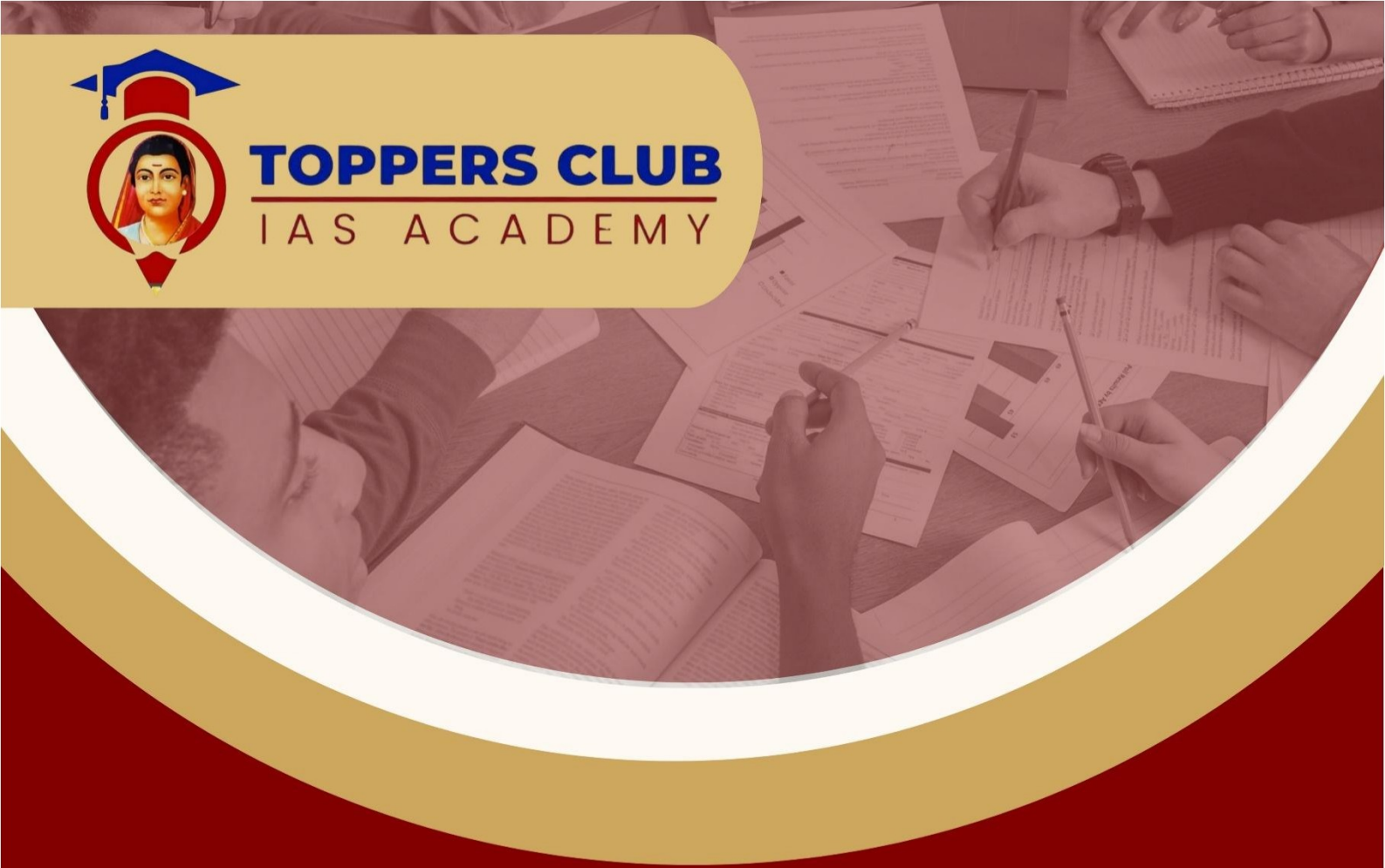

Monthly CURRENT AFFAIRS

By - Toppers Club

Staying updated with current affairs is crucial for academic and professional growth. It enhances knowledge, sharpens critical thinking, and improves decision-making. Awareness of global issues aids in competitive exams, essays, and interviews. Beyond academics, it reflects adaptability and curiosity—key traits in today's fast-changing world. Being informed broadens perspective, builds confidence, and opens up new opportunities.

+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
Toppers CLUB IAS
www.topperclubiasacademy.in
Sec 12 HNO 687 MUNSHI PULIYA INDIRA NAGAR LUCKNOW 226016